(सिर्फ सीसी सदस्यों के लिए)

भारत देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग पर हमारी पार्टी का दृष्टिकोण–राजनीतिक कार्यक्रम

मसविदा

दिसंबर 2024

केंद्रीय कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

विषयवस्तु

1. प्रस्तावना 5
2. साम्राज्यवाद–पूंजीवाद की चरम अवस्था–सर्वहारा वर्ग की क्रांतियों का युग 9
3. भारत देश में पूंजीवादी वर्ग का उद्‌भव–परिणाम क्रम–जाति की भूमिका 12
4. पहला चरण उपनिवेशवादी काल से 15 अग्रस्त, 1947 तक.... 24
5. दूसरा चरण 15 अगस्त, 1947 से 1991 तक 35
6. तीसरा चरण 1991 से आज तक (2024) 45
7. राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग का विकास में कदम–कदम पर रोड़ा बने हुए हैं साम्राज्यवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग 64
8. भारत राष्ट्र, देश की एकता एवं संपूर्णता के नाम पर देश को राष्ट्रीयताओं का कैदखाना के रूप में तब्दील करने और अखंड भारत के लक्ष्य में निहित हैं सिर्फ साम्राज्यवादियों एवं दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के हित 67
9. भारत देश के शासक वर्गों के विस्तारवादीकांक्षा में निहित हैं सिर्फ साम्राज्यवादियों एवं ब्राह्मणीय हिंदुत्व व पीड़क जाति आधिपत्य वाले दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के हित 70
10. सीबीबी के प्रति संशोधनवादियों एवं विभिन्न मा–ले पार्टियों के दृष्टिकोण 76
11. हमारा राजनीतिक कार्यक्रम 89

★★★

भारत देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग पर हमारी पार्टी का दृष्टिकोण–राजनीतिक कार्यक्रम

मसविदा

दिसंबर 2024

1. प्रस्तावना

2007 के एकता कांग्रेस के दौरान ही भारत देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग (सीबीबी) के संबंध में अध्ययन करने के बारे में केंद्रीय कमेटी (सीसी) द्वारा निर्णय लिया गया था. लेकिन कांग्रेस से लेकर केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा भारत देश के क्रांतिकारी आंदोलन को उन्मूलन करने के लक्ष्य को लेकर लगातार हमले किए जा रहे हैं. इसकी वजह से हमारे केंद्रीय कमेटी के सदस्य उल्लेखनीय संख्या में शहीद हो गए एवं गिरफ्तार हो गए. फलस्वरूप भारत देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग पर हमारी सीसी ने इस दस्तावेज को बनाने में अक्षम हुई. कांग्रेस के उपरांत 17 वर्षों के बाद 'भारत देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग पर हमारी पार्टी का दृष्टिकोण–राजनीतिक कार्यक्रम' नामक इस मसविदा दस्तावेज को जारी कर रही है. इस अवसर पर भारत देश के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में एवं हमारी पार्टी के इतिहास में सीबीबी पर हुई चर्चा पर सरसरी नजर डालेंगे.

भारत देश के पूंजीपति वर्ग को राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के रूप में, स्वतंत्र वर्ग के रूप में मान्यता देने वाली भाकपा और भाकपा (एम) की संशोधनवादी एवं नयी संशोधनवादी दलीलों को तिरस्कार कर, 1970 में संपन्न पूर्ववर्ती भाकपा (मा–ले) की 8वीं कांग्रेस में भारत देश की क्रांति की रणनीति/बुनियादी लाइन बनायी गयी थी. भाकपा (मा–ले) की धारा की भाकपा (मा–ले) [पीपुल्स वार] ने 2001 तक चार प्रमुख अंतरविरोधों के रूप में – साम्राज्यवाद (जब अमेरिका व रूस महाशक्तियों के रूप में थे, उन दोनों को मिलाकर बताया गया) एवं भारत की जनता के बीच; समंतवाद एवं व्यापक जनता के बीच; पूंजी व श्रम के बीच; शासक वर्गों के बीच अंतरविरोधों को बताती आयी थी. इस पूरे काल में वह दलाल नौकरशाह पूंजीपति एवं व्यापक जनता के बीच के अंतरविरोध को एक मौलिक अंतरविरोध के रूप में हो या एक प्रमुख अंतरविरोध के रूप में उसने नहीं बतायी थी. वह इस समझदारी से चलती आयी कि यह अंतररिवोध साम्राज्यवाद एवं भारत की जनता के बीच अंतरविरोध में और पूंजी एवं श्रम के बीच अंतरविरोध में ही

निहित है, इसलिए उसे अलग से बताने की जरूरत नहीं है. पूर्ववर्ती भाकपा (मा–ले) पार्टी यूनिटी ने 1987 में केंद्रीय अधिवेशन को आयोजित की. उस अधिवेशन ने यह समझदारी दी कि दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग एक विशेष दर्जा वाला वर्ग है, वह साम्राज्यवाद की सिर्फ यांत्रिक कटपुतली नहीं है, देश में साम्राज्यवादी शोषण के लिए वह प्रधान वाहक है और क्रांति के लक्ष्यों (निशानों) में एक है और दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग एवं व्यापक जनसमुदायों के बीच अंतरविरोध को भारत देश के समाज के प्रधान व मौलिक अंतरविरोधों में एक अंतरविरोध के रूप में शामिल किया. इस तरह वह (पार्टी यूनिटी–पीयू) सीबीबी की सौदेबाजी शक्ति के बारे में और उसके सापेक्षिक स्वतंत्रता के बारे में बढ़चढ़कर बताने की वजह से भारत देश के राज्य के बारे में पीयू की समझदारी पर कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों में शक पैदा हुई. यह पूर्ववर्ती पीयू, पीडब्ल्यू एवं एमसीसीआई के बीच एक प्रधान अंतर बन गया. लेकिन क्रांतिकारियों की एकता को महत्व देने की समझदारी के साथ इस मामले पर पीयू ने लचीले रुख अपनाने का फैसला लिया. अगस्त 1998 में पीयू एवं पीडब्ल्यु के बीच संपन्न एकता वार्ता में इस अंतरविरोध को छोड़ने का पीडब्ल्यु के प्रस्ताव से पीयू ने सहमति जतायी.

2001 में पूर्ववर्ती पीपुल्स वार पार्टी की 9वीं कांग्रेस में सीबीबी के बारे में गहरी बहस हुई. इस बहस के बाद दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग एवं व्यापक जनता के बीच अंतरविरोध को भारत देश के समाज का स्वभाव को निर्धारित करने के मौलिक अंतरविरोधों में शामिल करने का निर्णय उस कांग्रेस ने किया. कांग्रस ने यह तर्क दिया कि चूंकि सामंतवाद एवं साम्राज्यवाद के साथ गठजोड़ होने वाले दलाल नौकरशाह पूंजीवाद हमारा भारत देश के समाज एवं भारत देश के राज्य के तत्व या स्वभाव को निर्धारित करता है और उसे हमारी क्रांति के वर्तमान चरण में ही उखाड़ फेंकना है, इसलिए मौलिक अंतरविरोध के कामरेड माओ की परिभाषा के अनुसार ही उसे एक मौलिक अंतरविरोध के रूप में शामिल करना ठीक होगा, ऐसा कहते हुए यह प्रस्ताव पारित किया: ''..... साम्राज्यवाद एवं भारत देश की जनता के बीच और पूंजी एवं श्रम के बीच के इन दो अंतरविरोधों में ही दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग एवं व्यापक जनता के बीच अंतरविरोध निहित है, ऐसा कहना पर्याप्त नहीं है. भारत देश के शासक वर्गों के गठजोड़ को नेतृत्व करने वाले दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग का महत्व के बारे में वह नहीं बताता है और जनता के हितों को साम्राज्यवादियों को बेचते हुए, देश की उन्नति के लिए अवरोध होने वाली उसकी अत्यंत विश्वासघाती भूमिका के बारे में वह विवरण पर्याप्त नहीं है. दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग में विस्तारवादी स्वभाव है. वह साम्राज्यवाद के

साथ मिलकर देश के राष्ट्रीयताओं को ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई इलाके की जनता को प्रत्यक्ष रूप से उत्पीड़ित करने वाले शोषक है. साम्रजयवाद के अधीन होने के बावजूद, वह एक अलग वर्ग के रूप में अस्तित्व में है. वह सिर्फ कटपुतली नहीं है. वह साम्राज्यवाद की सेवा करते हुए ही, अपने हितों का भी पूरा कर रहा है.'' .... ''साम्राज्यवाद एवं सामंतवाद के साथ दलाल पूंजीपति वर्ग को भी अलग–थलग कर उखाड़ फेंकने की जरूरत है. ....''

भाकपा (एम–एल) [पीपुल्स वार] एवं एमसीसीआई के बीच 2003 में आयोजित एकता वार्ता (unity talks) के तहत द्विपक्षीय समझौता (bilateral agreements) करने के संदर्भ में, दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग एवं भारत देश की व्यापक जनता के बीच अंतरविरोध को शामिल करने पर एमसीसीआई ने यह तर्क दिया कि उसे एक अंतरविरोध के रूप में शामिल करने से ऐसा खतरा बना रहेगा कि साम्राज्यवाद के खिलाफ शासक वर्गों के एक तबके के साथ गठजोड़ बना सकते हैं और वह तबका सीबीबी का ही प्रतिनिधित्व करती है और इस अंतरविरोध को शामिल करने से भारत देश की क्रांति की रणनीति एवं कार्यनीति बनाने में गलतियां कर सकते हैं, इसलिए दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग एवं भारत देश की व्यापक जनता के बीच अंतरविरोध को मौलिक अंतरविरोधों में शामिल नहीं करना चाहिए, यह अपना मौलिक भिन्नमत (basic defference) है. इसके बाद, अन्य कई मामलों में एकमत हासिल करने की स्थिति में, एकता (unity) का महत्व को देखते हुए पीपुल्स वार का प्रतिनिधि मंडली (deligation) ने इस अंतरविरोध को वापस लेने पर अपनी सहमति जतायी.

सितंबर 2004 में आयोजित एमसीसीआई एवं भाकपा (मा–ले) [पीपुल्स वार] की संयुक्त (joint) सीसी बैठक में, अन्य कुछ मतभेदों के अलावा सीबीबी पर मतभेदों को बाद में आयोजित होने वाले एकता कांग्रेस में हल करने के लिए दोनों पार्टियों के केंद्रीय कमेटियों द्वारा अलग–अलग नोट बनाए गए, जिन्हें निचले पार्टी अधिवेशनों में कैडरों को देकर बहस चलायी गयी. इन मुद्दों पर 2007 में आयोजित एकता कांग्रेस–9वीं कांग्रेस में गहराई से बहसें हुईं. बहस के बाद सीबीबी संबंध में कांग्रेस ने विस्तार से एक प्रस्ताव पारित किया. प्रस्ताव में यह बताया कि भारत देश में साम्राज्यवादी शोषण के लिए दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग एवं बड़े सामंती वर्ग दोनों प्रधान वाहक है, भारत देश के राज्य इन बड़े पूजीपति एवं बड़े सामंती वर्गों के साझा तानाशाही है, जो साम्राज्यवाद के आज्ञाकारी सेवक हैं और यह फैसला लिया कि भारत देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग (सीबीबी) के बारे में गहराई से अध्ययन करना है.

लेकिन कांग्रेस के उपरांत के काल में देश में घटित राजनीतिक व आर्थिक परिणामों के परिप्रेक्ष्य में देश में साम्राज्यवादी शोषण के लिए दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग को एक प्रधान वाहक (principle vehicle) के रूप में और भारत देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपति एवं बड़े सामंती वर्गों के राज्य में दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग का नेतृत्वकारी भूमिका (leading role) को मान्यता देने की जरूरत सामने आयी. इसी तरह कांग्रेस के बाद पिछले 17 वर्षों से देश में हो रहे राजनीतिक व आर्थिक परिणामों के मुताबिक, भारत देश की जनता पर सीबीबी के शोषण व उत्पीड़नों की तीव्रता के मुताबिक, उसके शोषण व उत्पीड़नों से शिकार हो रही जनता को उसके खिलाफ वर्ग संघर्ष में फौरन व्यापक रूप से गोलबंद करने की जरूरत के मुताबिक, उसके खिलाफ राष्ट्रीय पूंजीपति समेत मजदूरों, किसानों एवं निम्न पूंजीपति वर्ग को कार्यनीतिक एवं रणनीतिक संगठनों में व्यापक रूप से गोलबंद करने की जरूरत के मुताबिक, साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों को व्यापक व तेज करने की जरूरत के मुताबिक सीबीबी को निशाना बनाने के अलावा सीबीबी एवं व्यापक जन समुदायों के बीच अंतरविरोध को एक प्रमुख एवं मौलिक अंतरविरोध के रूप में शामिल करने की स्थिति सामने आयी.

इसे ध्यान में रखकर अक्टूबर 2018 में संपन्न सीसी की 6वीं बैठक में यह निर्णय लिया गयाः ''2007 में संपन्न एकता कांग्रेस–9वीं कांग्रेस में भारत देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग (सीबीबी) की भूमिका के बारे में चर्चा करने के बाद बहुमत के आधार पर एक निर्णय लिया गया. पिछले 12 वर्षों से उस निर्णय को अमल कर रहे हैं. लेकिन देश में हो रहे बदलावों को ध्यान में रखकर विभिन्न स्तरों के कुछ कामरेड सीबीबी के बारे में पुनर्विचार कर उचित निर्णय लेने का सुझाव दिया.वर्तमान में 12 वर्षों के आंदोलन की समीक्षा करने (सीसी पीओआर बनाने) के संदर्भ में, सीसी ने इस विषय पर चर्चा कर, भारत देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग की भूमिका के बारे में एक नोट (मसविदा) तैयार करने का निर्णय लिया है''.

वैश्विक वित्तीय पूंजी के हितों एवं देश के सीबीबी के हितों के पूरा करने के मुताबिक केंद्र व राज्य सरकारें उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण (एल.पी.जी.) नीतियों को अमल करने के तहत विभिन्न सुधारों को अमल करने, दुनिया में कई आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिणाम घटित होने, उनके प्रभाव हमारा देश पर उल्लेखनीय रूप से होने, सामंती संबंध कुछ हद तक कमजोर होने, पूंजीवादी संबंध क्रमशः बढ़ने–विस्तार होने, आदि कारणों से सामाजिक संकट तेज होते हुए भारत देश में उत्पादन संबंधों में उल्लेखनीय बदलाव तेजी हुए हैं.

नगरीकरण (urbanisation) बढ़ रहा है. आबाद के वर्गीकरण में–वर्गों की संरचना में बदलाव हो रहे हैं. बेरोजगारी आरक्षित सेना बढ़ रही है. गांवों में खेतहर मजदूरों का प्रवासन बढ़ रहा है. स्थायी रोजगार कम हो रहा है. उनुत्पादक, अस्थायी एवं मौसमी (seasonal) श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है. इससे किसानों के ग्रामीण लक्षण कम होते हुए अर्ध–मजदूर लक्षण बढ़ रहे हैं. प्राकृतिक संसाधनों के खोज में रणनीतिक जंगली एवं पहाड़ी इलाकों का स्वभाव में बदलाव हो रहे हैं. बाजार, शासन तंत्र, राज्यतंत्र एवं न्यायिक व्यवस्था पर देश के तमाम वर्गों की जनता की निर्भरता विभिन्न अंतरों के साथ बढ़ रही है. उच्च मध्यम वर्ग पर साम्राज्यवादी नयी उदारवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा है. देश की जनता पर वैश्विक वित्तीय पूंजी, उसकी दासता करने वाले सीबीबी एवं पुराने–नये सामंती शक्तियों का गठजोड़ के शोषण व उत्पीड़न बढ़ गए हैं. इससे लुटेरी सरकारों की नीतियों के खिलाफ जनता का असंतोष बढ़कर स्वतःस्फूर्ती से एवं संगठित रूप से जनांदोलन उभर रहे हैं. इन बदलावों को गहराई से समझना, इसके अनुसार कार्यनीति में बदलाव करना एवं उन्हें अमल करने के लिए पूरी ताकत को केंद्रित करना आज भारत देश के समाज का परिवर्तन चाहने वालों का कर्तव्य है.

इस परिप्रेक्ष्य में साम्राज्यवाद पर मार्क्सवादी महान शिक्षक कामरेड लेनिन की शिक्षाओं, दलाल नौकरशाह पूंजीपति पर कामरेड माओ की शिक्षाओं, फिलिप्पींस, पेरू एवं नेपाल देशों की क्रांतिकारी भाईचारे पार्टियों की दस्तावेजों का अध्ययन करने के अलावा हमारी पार्टी – भाकपा (मा–ले) [पीपुल्सवार], एमसीसीआई, भाकपा (मा–ले) नक्सलबाड़ी, भाकपा (माओवादी) – दस्तावेजों का अध्ययन कर सीबीबी पर इस मसविदा दस्तावेज को हमारी पोलिट ब्यूरो ने बनाकर, हमारी सीसी सदस्यों के लिए दिसंबर 2024 में जारी कर रही है. इस दस्तावेज पर चर्चा कर इसे अंतिम रूप देना बाकी है.

2. साम्राज्यवाद–पूंजीवाद की चरम अवस्था–सर्वहारा क्रांतियों का युगः

ऐतिहासिक तौर पर देखा जाय, पूंजीवाद के शुरूआती चरण – 'मुफ्त व्यापार' चरण में विकासशील भूमिका निभाई थी. सिथिल अवस्था में रही सामंती सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए पूंजीपति वर्ग स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे के नारों को लेकर किसान, श्रमिक जनता एवं कारीगरों को गोलबंद कर बुर्जुआ जनवादी क्रांति का नेतृत्व किया. राष्ट्रीय राज्यों एवं मुफ्त बाजारों को स्थापित किया. सांप्रदायिक पूंजीवादी देशों में सामंतवाद को पूरी तरह सफाया किया गया. ब्रिटेन जैसे देशों में राजशाह मात्र औपचारिक बन गया. यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों में पूंजीवाद का प्रभुत्व स्थापित हुआ.

पूंजीवाद का ऐतिहासिक परिणाम मुफ्त व्यापार चरण से 20वीं सदी की शुरूआत में इजारेदार चरण में हुआ. इसी को ही लेनिन ने साम्राज्यवादी चरण के रूप में परिभाषित किया. इसपर और विवरण देते हुए इस तरह सूत्रबंद्ध किया कि ''सामाज्यवाद पूंजीवाद का एक विशेष ऐतिहासिक चरण है. इसका विशेष स्वभाव तीन प्रकार का हैः साम्राज्यवाद का मतलब है 1) इजारेदार पूंजीवाद; 2) पराश्रयी या जर्जर होने वाली पूंजीवाद; 3) मरणावस्था में चटपटा रहा पूंजीवाद'' एवं ''साम्राज्यवादी युग–सर्वहारा क्रांतियों का युग''. यह आज भी सही है. सर्वहारा नेतृत्व में विश्व समाजवादी क्रांति के जरिए इस भूमंडल से साम्राज्यवाद को संपूर्ण रूप से सफाया करने तक इस युग में बदलाव नहीं होगा. माओ ने बताया कि ''साम्राज्यवादी युग, सर्वहारा क्रांतियों का युग में किसी भी नयी पूंजीवादी राज्य उभर नहीं सकता'', ''साम्राज्यवादी युग में किसी भी देश में कोई भी दूसरा वर्ग (मजदूर वर्ग को छोड़कर) एक सच्ची क्रांति को विजय तक नहीं ले जा सकता. यह बात इस तथ्य से अच्छी तरह साबित हो जाती है कि अनेकों क्रांतियां, जिनका नेतृत्व चीन के निम्न–पूंजीपति वर्ग और राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग ने किया था, असफल हो गई'' (संकलित रचनाएं–4, जनता के जनवादी अधिनायकत्व के बारे में, 30 जून, 1949, पृष्ठ 714–715).

साम्राज्यवादी चरण असमान आर्थिक व राजनीतिक विकास नियम को अपने साथ लेकर आया. साम्राज्यवादी शक्तियां समूचे दुनिया में विस्तार करने एवं दुनिया को पुनर्विभाजन करने के लिए विभिन्न गठजोड़ बनाएं और भीषण संघर्ष किया. इससे दो विश्व युद्ध करने में मजबूर हुए. युद्धों की सिलसिले से 20वीं सदी के पूरे पहला अर्ध भाग हिलता रहा. एक के बाद एक के रूप में समाजवादी क्रांतियां एवं नवजनवादी क्रांतियां चलती रही. दूसरी विश्व युद्ध के बाद समाजवादी शिविर अस्तित्व में आयी. इससे पूंजीवादी–साम्राज्यवाद एवं समाजवाद के बीच आमने–सामने की स्पर्धा तेज हो गयी. खतरनाक समस्याओं से पूंजीवादी–साम्राज्यवादी व्यवस्था जूझती रही. दूसरी विश्व युद्ध द्वारा पैदा हुए संकटों के साथ, नवजनवादी क्रांतियां सफल होने की वजह से साम्राज्यवाद बहुत कमजोर हो गयी और अमेरिका महाशक्ति बन गयी. उपनिवेशवाद के खिलाफ राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं मुक्ति संग्राम एवं क्रांतियां उभर कर आयीं. इनसे भयभीत होकर साम्राज्यवाद पिछड़ हुए एशिया, अफ्रीका एवं लातीन अमेरिका में पूरानी उपनिवेशवाद को बदल कर उसकी जगह पर नयी–उपनिवेशवाद को लेकर आयी और परोक्षा शासन, शोषण एवं नियंत्रण चलाती रही. सोवियत संघ कामरेड स्टालिन के निधन के उपरांत राज्य पूंजीवाद के रूप में बदल गया और एक दशक के अंदर ही

सामाजिक–साम्राज्यवादी महाशक्ति बन गयी. वैश्विक राजनीति 1970 एवं 1980 दशकों के पूरे समयकाल में वैश्विक आधिपत्य के लिए, विश्व बाजार का पुनर्विभाजन के लिए दोनों महाशिक्तयों के बीच तीखी स्पर्धा, गठजोड़ एवं शीतयुद्धों से भरी हुई थी. 1990 में 'सोवियत' महाशक्ति का पतन से अमेरिका ने एक मात्र साम्राज्यवादी महाशक्ति के रूप में निकलकर दुनिया की जनता के लिए बहुत बड़ा खतरे रूप में उभर कर आया.

पूंजीवाद के सार्वजनिक संकट तीन चरणों से गुजरता गया – पहला चरण पहला विश्व युद्ध से शुरू होकर 1923 तक, दूसरा चरण दूसरा विश्व युद्ध से लेकर 1950 के दशक के बीच तक चलते रहे. तीसरा चरण 1973 से शुरू होकर आज भी चलने वाली लंबे आर्थिक मंदी एवं संकट है. पहला विश्व युद्ध के अपरांत वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में 1923 से 1929 तक अस्थायी स्थिरता स्थापित हुई. इसी तरह दूसरा विश्व युद्ध के बाद 1950 के दशक के बीच से लेकर 1973 तक लगभग दो दशकों तक वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में आंशिक स्थिरता बनी हुई. 1973 से लंबे संकट के दौर में प्रवेश करने के बाद पूंजीवादी–साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था लगातार विकास होने का भ्रम चकनाचूर हो गया. पूंजीवादी व्यवस्था में निहित तमाम अंतरविरोधों एवं संकटों का हल करने के नाम पर अर्थशात्री कींस द्वारा सामने लायी गयी कल्याणकारी राज्य भावना घोर विफलता का सामना किया. कुल मिलाकर, वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में संकट स्थाई एवं निरपेक्ष है, जबकि स्वस्थ होना अस्थाई और सापेक्ष है.

1973 से वैशिक पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पन्न गंभीर संकट को हल करने के दौरान नयी उदारवादी आर्थिक नीतियां या वित्तीय सिद्धांत सामने आए. व्यवहार में 1980 के दशक से 1990 की शुरूआत तक साम्राज्यवाद ने विश्वभर में ढांचागत समायोजन कार्यक्रम (structural adjustment programes) चलाए. साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी ने नयी उदारवादी नीतियों को लेकर उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण (एल.पी.जी.) को अमल करते हुए दुनियाभर में मजबूर, किसान, मध्यम वर्ग आदि उत्पीड़ित जनता पर, उत्पीड़ित देशों पर/औपनिवेशिक एवं अर्ध–औपनिवेशिक देशों पर नया आक्रमाण करने लगे. समाचार उपग्रह व्यवस्था का विकास में एवं समाचार को प्रसारित करने वाली प्रौद्योगिकी में अनोखा विकास की वजह से यह संभव हो पाया है. यह आक्रमण पिछले तीन दशकों के अधिक समय से अभी भी जारी है.

2008 में अमेरिका में शुरू हुआ आर्थिक एवं वित्तीय संकट ने यूरोप समेत विश्वभर में विस्तर हुआ. विश्वव्यापी संकट के रूप में बन कर अभी भी जारी है.

1976 में माओ के निधन के बाद चीन में पूंजीवाद की वापसी हुई इन लगभग चार दशकों में यानी 2014 तक चीन एक समाजिक–साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में एवं विश्व पूंजीवादी–साम्राज्यवादी व्यवस्था का हिस्से के रूप में तब्दील हो गया. एक तरफ साम्राज्यवादियों के बीच होड़ और दूसरी तरफ दुनिया के मजदूर, किसान आदि उत्पीड़ित जनता एवं उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं का प्रतिरोध के फलस्वरूप घटित परिणामों से 21वीं सदी के दूसरी दशक की शुरूआत तक अमेरिका अपनी एकध्रुवीय महाशक्ति का दर्जा खो दिया. बहुध्रुवीय विश्व अस्तित्व में आया. फिर भी अमेरिकी साम्राज्यवाद अभी भी विश्व की उत्पीड़ित जनता एवं उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं का नंबर एक दुश्मन बना हुआ है.

वर्तमान में विश्व समाजवादी क्रांतिकारी शिविर अस्थायी रूप से हार जाने के बावजूद, वह रणनीतिक रूप से पीछे हटने के बावजूद, लेनिन की शिक्षा के मुताबिक, साम्राज्यवादी, सर्वहारा क्रांतियों का युग अभी भी जारी है. साम्राज्यवादी लंबे संकट, विध्वंसकता एवं युद्धों का विस्तार तेज होता जा रहा है, साम्राज्यवाद शिथिल होता जा रहा है, विश्व समाजवादी क्रांति का उभार देहलीज पर पहुंच गया. वस्तुगत परिस्थितियां साम्राज्यवाद के लिए प्रतिकूल और जनवादी व समाजवादी संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल बनी हुई हैं. साम्राज्यवादी संकट को इस्तेमाल कर एक तरफ जनता की निराशा–हताशा को भुनाने में लगे रहने वाली फासीवादी पार्टियों एवं संस्थाओं के नेतृत्व में प्रतिक्रियावादी दक्षिणपंथी आंदोलन विश्वभर में मजबूत होकर विस्तार कर रहे हैं. दूसरी तरफ विश्वभर में विभिन्न जनवादी संगठन एवं संस्थाओं के नेतृत्व में परमाणु हथियारों एवं युद्धों के खिलाफ, पर्यावरण का संरक्षण के लिए, नागरिक अधिकारों के लिए साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन; विभिन्न देशों में सर्वहारा/माओवादी पार्टियों के नेतृत्व में क्रांतिकारी आंदोलन एवं दीर्घकालीन लोकयुद्ध; विभिन्न राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों के संस्थाओं के नेतृत्व में उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के मुक्ति संघर्ष मजबूत हो रहे हैं या उसके लिए तैयारियां कर रही हैं. इन्हें आगे बढ़ाने के लिए विश्व सर्वहारा वर्ग द्वारा किए जाने वाले प्रयास विश्व समाजवादी क्रांति के लिए भरोसा देता है.

3. भारत देश में पूंजीपति वर्ग का उद्भव–परिणाम क्रम–जातिप्रथा की भूमिकाः

भारत देश में औपनिवेशिक व अर्ध–सामंती व्यवस्था के गर्भ से ही जन्म लेने वाले पूंजीपति वर्ग का बहुत लंबा इतिहास रहा है. इस पर भारत देश के समाज में आर्थिक बुनियाद में और ऊपरी ढांचा में जारी जाति व्यवस्था का प्रभाव अविभाज्य है. इसलिए हमारा देश में कारीगारों से व्यापारियों के रूप में बदलने का क्रम लगभग गायब है. इससे विपरीत, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के समर्थन, जाति आधारित

सामंतवाद से जीवंत संबंध होने वाले पीड़क जातियों के दलाल व्यापारियों, सामंती राजाओं, बड़े सूदखोरों से 'पूंजीपति वर्ग' का उद्भव हुआ. फलस्वरूप जन्म से लेकर उसमें पूंजीवादी लक्षण से अधिक प्रतिक्रियावादी सामंती लक्षण अधिक होने के अलावा साम्राज्यवादी दलाल होने का स्वभाव भी निहित है.

भारत देश में व्यापार पूंजी के संचयनों में, श्रम नियंत्रण में, शोषण व प्रबंधन के स्वरूपों में, अर्थव्यवस्था के आधुनिक क्षेत्रों में भी दिखायी देने वाले सामंती अंश पीड़क जाति एवं सामंती प्रभुत्व के सबूत हैं. उनके प्रतिबिंब हमेशा सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में दिखायी देते हैं. हालांकि वे पुराने जातिगत सामंतवाद या पुराने ब्राह्मणवाद के अंश नहीं हैं. उनके आकार साम्राज्यवाद एवं दलाल नौकरशाह पूंजीवाद से प्राप्त हैं और उनसे संवार कर लिपट गए हैं. औपनिवेशिक काल से ही पीड़क जाति के सामंती जमींदारों को औद्योगिक एवं व्यापारिक हित होते रहे हैं. इसी तरह बड़े दलाल पूंजीपति वर्ग को भी जमीन संबंधित हित होते रहे हैं. हाल ही में ये एक दूसरे से मिश्रित होने का रुझान बढ़ा है. तद्वारा ही वे वर्तमान शासक वर्गों – दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों, पीड़क जाति के पुराने–नए सामंतियों की जरूरतों को सक्षम रूप से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. इस तरह संवार करने वाले ब्राह्मणवाद भारत देश के दलाल शासक वर्गों – पीड़क जातियों के सामंतवादियों एवं दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों दोनों के विश्व दृष्टिकोण, मूल्यों की व्यवस्था तमाम तबकों की जनता के नस–नस में मौजूद है. जैसाकि महान शिक्षक मार्क्स ने बताया कि शासक वर्गों के विचार ही जनता के विचार होंगे. इस तरह भारत देश में बुनियादी तौर पर साम्राज्यवादी एवं सामंतवादी विचार का ही बालेबाला है.

मध्ययुग के अंत में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब एवं बंगाल में गुजराती बिनया/जैन, राजस्थानी मारवाड़ी, सिंधी (लोहाना), भाटिया एवं पारसीयों ने स्थानीय व्यापार एवं सूदखोरी करते हुए विभिन्न राजपूत राज्यों के लिए, उसके बाद ब्रिटिश वालों के लिए मोदीयों (सैनिक साजो–सामान आपूर्ति करने वाले) के रूप में, बैकरों के रूप में काम करते थे. वे उत्पादन से नहीं व्यापार वर्ग से विकसित हुए. इसी वजह से सामंती राजाओं की तरह पैसे के लिए विश्वासघात करने में उन्हें कोई सीमाएं नहीं रहती थीं. इसमें जगतसेठ कुख्यात थे. वे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का हार के लिए और देश को बिटिश वालें कब्ज करने के लिए मुख्य जिम्मेदार थे. बनिया, मारवाड़ी, खत्री जैसे सांप्रदायिक व्यापार समुदायों से विकसित होने वाले दलाल पूंजीपति वर्ग का देशव्यापी विस्तार के लिए ब्रिटिश शासन में ही जोश मिला था. एक क्रम में विशेषकर बनिया एवं मारवाड़ीयों ने बंगाल, असम, मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र में अन्य इलाकों में विस्तारित हुए. पूर्वी भारत

देश में प्रधानतया ब्रिटिश वालों के दलालों के रूप में सेवाएं दिलायीं. इसी तरह ब्रिटिश के औपनिवेशिक शासन में दक्षिण गुजरात में व्यापार वर्ग के रूप में विकसित होने वाले पारसीयों ने मुंबई, उसके बाद पूरे देश में विस्तारित हुए. पारसीयों के व्यापार का विकास के साथ मुंबई का विकास जुड़ा हुआ था. खत्रीयों के व्यापार मारवाड़ियों के अनुषंगी व्यापार के रूप में पंजाब से दिल्ली, आगरा, लखनऊ एवं पटना शहनों में स्थायी निवास बनाने के बाद ही विकसित हुए. उत्तर भारत देश के उद्योगों एवं व्यापारों समेत तमाम आर्थिक ताने–बाने मुख्य रूप से बनिया, मारवाड़ी या खत्रीयों के हाथों में ही हैं.

मारवाड़ीयों ने देशीय व्यापार करते थे. बनिया व्यापारी पर्शियन खाड़ी, लाल समुंदर के बंदरगाहों में व्यापार करते थे, जबकि पारसीयों ने चीन से विदेशी व्यापार करते थे. वे ब्रिटिश वालों से मिलकर मिश्रित पूंजीवाले (joint stock) बैंक भी चलाते थे. टाटा, पित्ति व वाडिया जैसे पारसीयों ने इस समय में ही प्रगति हासिल की. पारसीयों के नक्शेकदम लोहाना व भाटियों ने मुंबई में मजबूत हुए. कच (गुजरात) भाटियों ने मध्य एशिया देशों से विदेशी व्यापार करते थे. उसे दक्षिण भारत देश एवं बर्मा (म्यानमार) में विस्तारित किया. लोहाना व्यापारी मध्य एशिया में, सिंधी व्यापारी उत्तर अमेरिका, लातीन अमेरिका, यूरोप, पूर्व–दक्षिण–पूर्व एशिया तक अपने व्यापार विस्तारित किया. तमिलनाडु के नट्टुकोट्टाई चेट्टियारों ने अपनी पूंजी हमारा देश में मुख्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र में लगायी. दक्षिण–पूर्व एशिया के श्रीलंका, बर्मा (म्यानमार) जैसे विभिन्न देशों के विभिन्न क्षेत्रों में भी उन्होंने बहुत अधिक पूंजी लगायी. इस सांप्रदायिक व्यापार जातियों से आए हुए ये तमाम व्यापारी ब्रिटिश आदि साम्राज्यवादी कंपनियों के स्थानीय दलालों, मुंशीयों, कमिशन एजेंटों, बैंकरों एवं डीलरों के रूप में काम करते हुए क्रमशः व्यापार क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र में ('साप्रदायिक बाजार से फैक्टरी' में) परिवर्तित हुए.

व्यापार से उत्पादन क्षेत्र तरफ लौटने वालों में से पारसी व्यापारी पहले व्यापारी (टाटा, पित्ति, वाडिया) थे. उसके बाद भाटिया, बाद में गुजराती बनिया, जैन (साराभाई, लालभाई, मंगलदास गिरिधरदास) एवं नट्टुकोट्टाई चेट्टियार शामिल थे. पहला विश्व युद्ध के बाद ही मारवाड़ी उत्पादन क्षेत्र में लौटे थे. सत्ता हस्तांतरण के बाद प्रवासी भारत देश के दलाल कार्पोरेटों के रूप में स्वराजपाल, लक्ष्मी मित्तल, अनिल अगरवाल आगे आए. एक क्रम में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी से बिड़ला, मित्तल, अगरवाल, गोयंका, सिंघानिया, लालभाई, साराभाई, बजोरिया, सूरजमुल नागरमुल, डीसीएम (लाला श्रीराम ग्रुप कंपनियां), बंगुर, दाल्मिया, बजाज, मोदी, श्रीराम, थापर परिवारों से लेकर जिंदल, महिंद्रा, मंजल, गोद्रेज, इसके अलावा नरेश

गोयल, किशोर बियानी, गोवन भाइयों तक दलाल उद्यमी विभिन्न पीड़क जातियों से उद्भव हुए.

ब्रिटिश शासन में मेकाले उपनिवेशिक आधुनिक शिक्षा उनकी जरूरतों को पूरी करती थी और प्रबंधन एवं शासन के लिए आवश्यक कर्मचारियों को तैयार करती थी. वह सांप्रदायिक रूप से सीढ़ीदारी सामाजिक व्यवस्था को पुनःपरिभाषित करने एवं लपेटने द्वारा खत्री, ब्राह्मण (तमिल ब्राह्मण, गौड़ा सारस्वत ब्राह्मण (GSB) समेत), कायस्थ, बंगाली भद्रलोक समुदाय (पीड़क जाति के ब्राह्मण, कायस्थ, स्वास्थ्य संबंधी समुदाय) आदि पीड़क जातियों को अपने विकास के लिए वैकल्पिक क्षेत्र खोजने में विवश की. उन्होंने व्यापारों, उद्योगों एवं सरकारी विभागों में प्रवेश किया. सत्ता हस्तांतरण से पहले बिटिश साम्राज्यवादियों, उसके बाद तमाम साम्राज्यवादियों ने ब्राह्मणीय जाति आधारित सामंतवाद को अपने सामाजिक आधार बनाया. इसके फलस्वरूप कई परिणाम हुए. औपनिवेशिक एवं अर्ध–औपनिवेशिक भारत देश में इन गैर–व्यापारीय पीड़क जाति के समुदायों से विश्वसनीय दलाल बनाना आसान बन गया. इसी तरह इन पीड़क जाति के समुदायों में से राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अवसर प्राप्त करने वालों को यह ऐहसास लगा कि उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक हित साम्राज्यवादियों से लगे हुए हैं, तो वे उन साम्राज्यवादियों पर निर्भर होने लगे. आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से इस तरह की दलाल मानसिकता बढ़ी. प्रांतीय स्तर पर एवं समूचा देश में भी सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से अपनी आधिपत्य पर आधारित होकर सौदेबाजी करने में निपुणता हासिल करते हुए इन जातियों से उच्च अधिकारियों (bureaucrats) के रूप में बढ़ने वालों में से एक तबका औद्योगिक वर्ग में शामिल होने लगे. मुख्य रूप से वे प्रांतीय उद्यमियों के रूप से विकासित हुए. उनमें से उल्लेखनीय संख्या में ही बड़े दलाल व्यापारी/औद्योगिक वर्ग के रूप में परिवर्तित हुए. इस सिलसिले में थापर भाइयों एवं नारंग परिवार सबसे पहले खत्री दलाल पूंजीपति बन गए. इन खत्री परिवारों में से दो खत्री (थापर भाइयों एवं महिंद्रा परिवार) दलाल पूंजीपति समुदाय प्रमुख स्थान हासिल कर लिए. कुछ खत्री सिख व्यापारी विभिन्न क्षेत्रों में आगे आए. ब्राह्मणों में से पहले टी.वी. सुंदरम अय्यंगार, किर्लोस्कर परिवार, उसके बाद नंबर 2 साफ्टवेयर निर्यातक इनफोसिस नारायणमूर्ति, आदि विकसित हुए. उत्तर भारत देश में ब्राह्मणों में से जयप्रकाश गौड़ा (जेपी ग्रुप), नरेंद्रनाथ मोहन (शराब) को छोड़कर उल्लेखनीय स्तर पर कोई नहीं हैं. पश्चिम व दक्षिण भारत देश के ब्राह्मणों से तुलना किया जाय, उत्तर भारत देश के ब्राह्मणों ने औद्योगिक क्षेत्र में विकास नहीं कर पाया. इसका कारण है, वे

आधुनिक शिक्षा एवं धर्मनिरपेक्ष विचारों से प्रभावित नहीं होना, पूजारी पेशा से उबर नहीं पाना और सामंतवादी रीति–रिवाज ही उनके लिए सुविधानक होना. केरल में नंबूद्री ब्राह्मणों को भी यह लागू होता है.

ब्रिटिश आक्रमण के बाद शिक्षा प्राप्त कर, कार्ल मार्क्स, ठागोर एवं सत्यजित रे के क्रांतिकारी एवं प्रगतिशील विचारों से प्रभावित होने वाले बंगाली भद्रलोक समुदाय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से पश्चिम बंगाल में मुख्य शिक्त के रूप में विकसित हुई. ऐसे स्थानीय बंगाली उद्योगपतियों में से सत्ता हस्तांतरण से पहले विभिन्न क्षेत्रों में बीरेंद्र मुखर्जी जैसे लोग प्रमुख दलाल उद्योगपतियों के रूप में आगे आए. लेकिन 20वीं सदी की शुरूआत में यूनिलिवर, जनरल इलेक्ट्रिकल्स, फिलिप्स जैसे ब्रिटन व अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं अन्य विदेशी कंपनियां भारत देश में अपनी अनुषंगी कंपनियों की स्थापना करने के कारण, उनसे प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाने की वजह से स्थानीय बंगाली उद्योग बहुत हद तक धक्का खाया या तो एमएनसीयों द्वारा उन्हें खरीदा गया या तो ब्रिटिश वालों द्वारा हथिया लिया गया. मारवाड़ियों के आधिपत्य के कारण बंगली भद्रलोक समुदायों में शक्तिशाली दलाल पूंजीपति वर्ग विकसित नहीं हो पाया. सत्ता हस्तांतरण के बाद कोलकता अपनी प्रधानता खो जाने और कोलकता के शेयर बाजार एवं बुर्राबाजार में मारवाड़ियों का आधिपत्य होने के कारण परिस्थिति और ढलान पर चला गया. प्रवासी भारतीयों के रूप में रहने वाले प्रणय राय, अमर गोपाल बोस, बिकी चक्रबोर्ति, पूर्णेंदु चटर्जी जैसे बंगालियों के कार्यकलापों से मात्र 1980 के दशक से ही पश्चिम बंगाल में मजबूत दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग का उद्भव होने लगे. वर्तमान में बंगालियों में से सुब्रतो राय (सहारा), बर्मन्स (डाबर) आदि प्रमुख दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के रूप में हैं.

15 अगस्त, 1947 के सत्ता हस्तांतरण से पहले और बाद में भी इसी तरह सांप्रदायिक व्यापारी जातियों की आधिपत्य व्यवस्था को तोड़ते हुए पश्चिम एवं दक्षिण भारत देश के ग्रामीण इलाकों में आधिपत्य में होने वाले कृषि–प्रधान जातियों में से कुछ दलाल पूंजीपति विकसित हुए. दक्षिण भारत देश में कबिलाई समाज सामंतवाद समाज के रूप में बदलने के क्रम में अलग–अलग नामों से सूदखोरी, वाणिज्य व व्यापार करने वाले वैश्य होते थे. पर मारवाड़ी, पश्चिम व उत्तर भारत देश के बनिया नहीं होने के प्रांत में कम्मा, राजु, रेड्डी, वेलमा, गौड़ा, नाड़ार जैसे कृषि–प्रधान जातियों से, सिरियन इसाइयों व मुस्लिमों से सपेक्षिक रूप से निजी उद्योग एवं व्यापार विकसित हुए. मुख्य रूप से सत्ता हस्तांतरित होने के बाद सिलसिलेवार लागू की गयी पंचवर्षीय योजनाओं के तहत सिंचाई, बिजली, परिवहन,

खदान, अन्य मुख्य क्षेत्रों में सरकारी पूंजी बढ़ी थी. विभिन्न जातियों के पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों से उल्लेखनीय संख्या में ठेकेदारों एवं नए उद्योगपतियों के रूप में विकसित हुए. इसके विपरीत पश्चिम भारत देश के गुजरात एवं महाराष्ट्र में सरकारी योजनाओं को इस्तेमाल कर मराठा एवं पाटीदार जातियां सफलतापूर्वक चीनी एवं दुग्ध सहकारी संगठनों को स्थापित कीं. इससे उन्हें राजनीति में आने के लिए मदद मिली. समूचा देश में देखा जाय, कम्मा, रेड्डी, राजु, गौड़ा, नाड़ार, जाट, पाटीदार, मराठा जैसे जमीन होने वाले कृषि–प्रधान जातियों से इस तरह के कुछ लोग 'कृषि क्षेत्र से फैक्टरी में' परिवर्तित हुए.

1940 के दशक में अविभक्त आंध्रप्रदेश में आगे आने वाले ज्यादातर पहले कम्मा दलाल उद्योगपति सामंतवादी वर्ग से आए थे. पहला चरण में डेल्टा क्षेत्र में, उसके बाद के चरण में नेल्लूर, खम्मम, रायलसीमा जिलों में भी कम्मा दलाल उद्योगपति विकसित हुए. चल्लापल्ली राजा यारलागड्डा शिवराम प्रसाद सबसे पहला दलाल नौकरशाह पूंजीपति थे. कम्मा दलाल उद्योगपतियों में से प्रमुख हैं रायपाटि सांबशिवराव (तंबाकू, वस्त्र), देविनेनि सुब्बाराव (मिश्रम लोह, चीनी, शराब), रामोजीराव (चिटफंड, होटल, प्रिंट–इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं सिनेमा) आदि. सिनेमा क्षेत्र में कम्मा एवं कापु जातियों के बीच तीखा अंतरविरोध जारी हैं. 1980 के दशक से नयी पीढ़ी के कम्मा उद्योगपति निम्मालागड्डा प्रसाद, मुल्लापूडि हरिचंद्र प्रसाद आदि ने औषधीय क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी आगे आए. रेड्डी जाति में बोम्मिरेड्डी नागिरेड्डी (सिनेमा, चंदामामा पत्रिका, अस्पताल), एल. जैपाल रेड्डी जैसे दलाल नौकरशाह पूंजीपति प्रमुख हैं. राजु जाति में पूसापाटि रामस्वामी (सिमेंट, आस्बेस्टास, साफ्टवेयर, वस्त्र), और कुछ उद्योगपति दलाल नौकरशाह पूंजीपति के रूप में बदल गए. पर कम्मा, रेड्डी एवं राजु जाति के तरह वेलमा, कापु, अन्य आधिपत्य कृषि–प्रधान जातियों से औद्योगिक क्षेत्र में विकसित नहीं हो पाए. वेलमा जाति में सिनेमा क्षेत्र में वेंकटरामैया, अप्पाराव, और कुछ लोग ही दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के रूप में बदल गए. कापु जाति में मुख्य दलाल नौकरशाह पूंतिपति के रूप में बी. वासुदेवराव (मुर्गी पालन) जैसे बहुत कम लोग ही विकसित हो पाएं.

आंध्रप्रदेश में कम्मा, रेड्डी, अन्य कृषि–प्रधान जातियों के संबंध में दो विषय स्पष्ट हो जाते हैं. पहला विषय, ये कृषि–प्रधान जातियां औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न विविधतापूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश कर लिया. वे इस दौरान सांप्रदायिक व्यापार जातियां कोमटी एवं प्रवासी मारवाड़ियों को भी बाजू में रख दिया. इसके लिए राजनीतिक सत्ता मददगार साबित हुई. कोमटी दलाल नौकरशाह उद्योगपतियों में मात्र ग्रंथि

मल्लिखार्जुनराव (जूट, मिश्रिम लोहें, चीनी, बिजली प्लांट, निर्माण) और तंबाकू निर्यातकों में बोम्मिडाला, पोलिसेट्टी, मद्दि लक्षमैया ही रहे. दूसरा विषय, कम्मा एवं राजु जातियों के तमाम मुख्य उद्योग समुदाय तटीय आंध्रप्रदेश से संबंधित हैं. इनके विकास के पीछे गोदावरी बांध मुख्य भूमिका निभाई. इसलिए अकेले नामा नागेश्वरराव ही तेलंगाना से संबंधित है. तटीय आंध्रप्रदेश पूंजी ही बड़े पैमाने पर हैदराबाद गयी. तेलंगाना में भरपूर प्राकृतिक संसाधनों को लूटने एवं राजधानी पर आधिपत्य अपने हाथ में सुस्थिर बनाने के लिए जाने वाली ऐसी पूंजी आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना इलाकों के बीच राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर गंभीर अंतर पैदा की. यह तटीय आंध्रपेदेश के दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों एवं सामंतियों के खिलाफ असंतोष बढ़ाया और पृथक तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन को फिर से सुलगा दिया. उसके बाद तटीय आंध्रप्रदेश के दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों एवं सामंतियों के मनमानी लूट के खिलाफ, पानी, निधियों एवं नौकरियों को मुख्य बिंदु बनाकर दुबारा पृथक तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ.

भारत देश के मुख्य तैयारी केंद्र (manufacturing hub) के रूप में, दक्षिण भारत देश के मांचेस्टर के रूप में एवं भारत देश के हलका इंजीनीरिंग पॉवर हाउज के रूप में प्रसिद्ध पश्चिमी तमिलनाडु के कोयमबत्तूर इलाके को नट्टुकोट्टाई चेट्टियारों या अन्य सांप्रदायिक व्यापारियों ने नहीं विकसित किया. बल्कि, मुख्य रूप से कृषि ही पेशा के रूप में लेकर, आंध्रप्रदेश से प्रवास किए कम्मावार (कम्मा नायुडू) एवं कोंगु वेल्लाल जाति के लोग उसके लिए अपने योगदान दिए. नायुडू लोग 1905 से ही विकसित हुए. नायुडू जाति में पीएसजी, कुप्पुस्वामी नायुडू, वी. रंगास्वामी नायुडू आदि मुख्य समुदाय हैं. प्रमुख उद्योगपति एल.आर. गोविंदराजुलू के नेतृत्व में एलजी ग्रुप बड़े हलका इंजीनीरिंग समूह (conglomarate) के रूप में विकसित हुई. गौड़ा लोग 1906 से सामंती वर्ग से दलाल उद्योगपतियों के रूप में विकसित हुए. इनमें से प्रमुख हैं वी.सी. वेल्लिंगिरि गौड़ा, ए.वी. रमण गौड़ा, आदि. इन गौड़ा लोग इतने विकसित हुए कि वे नायुडू लोगों से प्रतिस्पर्धा लेने में सक्षम हुए. गौड़ा लोग के पूंजी वस्त्र तैयारी (cotton kitwear) उद्योग से बहुत तरक्की की. उस इलाके के तिरुपुर शहर भारत देश के 'बनियन राजधानी' के रूप में प्रसिद्ध हो गया. सांप्रदायिक वस्त्र तैयारी निर्यातों के लिए प्रसिद्ध मुंबई, लूधियाना एवं दिल्ली से भी तरक्की कर उसने प्रथम स्थान हासिल कर लिया. इसमें गौड़ा जाति के दलाल नौकरशाह उद्योगपति एस. रामस्वामी (बेस्ट इंटरनेशनल) आदि मुख्य उद्योगपतियों के रूप में विकसित हुए. वैश्वीकरण के समय में पहले बेसिक टी शर्ट तैयारी, बाद में और अधिक फैशन

वाली खेल वस्त्र, जाकेट, स्वेटशर्ट, बेरमुड़ास, बच्चों के वस्त्र, घाघरा (स्कर्ट), लेड़ीज इनरवेअर तैयारी विकसित हुईं. ये बड़े पैमाने पर सी एंड ए, वाल–मार्ट, जेसी पेन्नी, सारा ली, मार्क्स एंड स्पेन्सर, टोम्मी हिलफिगर, जीएपी जैसे विश्व विक्रेताओं (global buyer) के लिए आपूर्ति की जा रही हैं.

दक्षिण तमिलनाडू के नाड़ार एवं केरल के मलयाली एझवा जाति के लोग 'छूआछूत वाली जाति' नहीं है, फिर भी छूआछूत से बहुत परेशानी झेलते हुए ताड़ी शराब पेशा से जीवनयापन करते थे. 20वीं सदी की शुरूआत तक इसाई धर्म अपनाना, शिक्षा के अवसर मिलना, यूरोपीय पूंजी काफी व चाय प्लांटेशनों के साथ पहुंचना, इसी वजह से रोजगार मिलना, ताड़ी पेशा को छोड़कर मिर्चा, प्याज, सुपारी जैसे व्यापार फसल लगाना, ब्रिटिश शासकों एवं इसाई मिशनरियों की सहयोग से प्लांटेशनों में पूंजी लगाना, इन सभी कारणों से वे पहले व्यापार क्षेत्र में, उसके बाद उद्योगों में प्रवेश कर दलाल पूंजीपतियों के रूप में परिवर्तित हुए. इसमें प्रमुख नाड़ार दलाल उद्योगपति थे प्लांटेशनों के मालिक पी.डी. देवसहायम एवं आल्फ्रेड वेदम थामस. कई नाड़ार दलाल परिवार शिवकासी इलाके में प्रवास करने के बाद ताड़ी गुड़ व्यापार, कपास, मूंगपल्ली एवं तंबाकू व्यापार फसलों के जरिए तरक्की की. किसानों एवं यूरोप के निर्यातक संस्थाएं हार्वेस, वोलकार्ट्स एवं रालीस के बीच बिचौलियों के रूप में काम करते हुए कपास आपूर्ति करने में इजारेदार व्यापारी परिवार बन गए. इसी तरह रामनाड़ नाड़ार भी मजबूत दलाल व्यापारी वर्ग के रूप में विकसित हुए. यहां सांप्रदायिक व्यापार जाति – चेट्टीयार नहीं होने के नाते नाड़ार लोगों को इसका लाभ मिला. वे नाड़ार महाजन संगम के नेतृत्व में नाड़ार बैंक को स्थापित किया. पी. अय्या नाड़ार एवं ए. शनमुगा नाड़ार शिवकासी इलाके में माचिस उद्योग की स्थापना एक मोड़ था. वहां की परिस्थितियां, संसाधन, सस्ती मानव श्रम अनुकूल होना, केंद्र सरकार ने 1973 में उस उद्योग को छोटे स्तर के उद्योग के रूप में मान्यता देकर 'आरक्षण' देने की वजह से वह क्रमशः देश में बहुत बड़े माचिस तैयारी केंद्र (hub) के रूप में विकसित हुआ. शिवकासी–सत्तूर–कोविलपट्टी इलाके में आधिपत्य होने वाले लगभग 20 नाड़ार दलाल नौकरशाह परिवारों एवं अन्यों को भी इसका लाभ मिला. इसमें पायनीर एशिया ग्रुप जैसे उद्योग प्रमुख हैं. माचिस उद्योग फिर भारी पटाका (फायर वर्क्स) उद्योग एवं पैरोटेक्नीक रसायनों का उद्योग विकसित होने के लिए मार्ग सुगम बनाया. देश में 90 फीसदी पटाका व्यापार करने वाले तमाम लोग नाड़ार दलाल नौकरशाह पूंजीपति ही हैं. बाद में आफसेट प्रिंटिंग उद्योग में एसएफए ग्रुप स्टेशनरी उत्पादनों के लिए देश में बहुत बड़ी दलाल नौकरशाह पूंजीपति

कंपनी के रूप में, बहुत बड़ी कागज व्यापार कंपनी के रूप में, बहुत बड़े इंक एवं पिगमेंट डीलर के रूप में विकसित हुआ. तिल का तेल उद्योग नाड़ारों के नेतृत्व में देश में बहुत बड़े सीबीबी उद्योग के रूप में विकसित हुआ. बाद में नए तौर पर कई सीबीबी मीडिया कंपनियां आगे आयीं. कई मुख्य नाड़ार दलाल नौकरशाह उद्योगपति संसदीय राजनेता बने.

केरल में एझवा एवं सिरियन इसाई जाति के लोग अविभक्त कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारी भूमि सुधारों के तहत जमीन प्राप्त कीं. उसमें वे व्यापार फासल, विशेषकर नारियल पेड़ लगाना, अलेप्पी शहर में यूरोप व्यापारी द्वारा स्थापित किया गया नारियल की जटा उद्योग के लिए जटा की आपूर्ति करना, इसके लिए वातावरण एवं भौगोलिक परिस्थिति अनुकूल होने के कारण के.सी. करुणाकरन जैसे कुछ एझवा किसान दलाल व्यापारी के रूप में और जटा तैयारी करने वाले दलाल उद्योगपति के रूप में विकसित हुए. दलाल पूंजीपति करन ग्रुप एशिया में बहुत बड़ी जटा निर्यातक के रूप में विकसित हुई. इस क्षेत्र में अन्य मुख्य एझवा दलाल पूंजीपति के रूप में वी.आर. प्रसाद एवं सी.आर. देवराज आगे आए. सत्ता हस्तांतरण के बाद केरल में वेल्लपल्ली नटेशन जैसे एझवा दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों को ही शराब व्यापार में एवं नारियल शराब व्यापार में मजबूत पकड़ है. इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में अनेक एझवा लोग दलाल नौकरशाह पूंजीपति बन गए.

कर्नाटक में तेलुगु बोलने वाले इड़िगा जाति के लोग भी सांप्रदायिक ताड़ी शरबा पेशा से नारायण स्वामी, दासप्पा, बसवराज, रामुलू जैसे लोग सीबीबी बन गए. बंगारप्पा, जनार्धन पुजारी, जालप्पा जैसे मुख्य संसदीय राजनेता भी इड़िगा जाति से आए हैं. हालांकि इड़िगा लोग ऐसा विकसित नहीं हो पाए जैसाकि एझवा लोग कर पाएं.

कृषि–प्रधान जातियों से संबंधित मराठा एवं पाटीदार जातियों के लोग 19वीं सदी से पश्चिम भारत देश में अपनी आर्थिक पिछड़ेपन से उबरते हुए, बनिया, मारवाड़ी, पारसी जैसे सांप्रदायिक जातियों के आधिपत्य को तोड़कर, उद्योगों एवं व्यापारों में लौटने में चीनी सहकारी समितियों (co-operatives) को स्थापित करना ही विकल्प बन गया. इसके लिए तत्कालीन परिस्थतियों से मदद मिली. सहकारी समितियों को महाराष्ट्र में पहले यश्वंतराव बलवंतराव चवान, बाद में वसंतदादा पाटिल, उसके बाद शरत पवार मुखिया बनकर चलाए थे. ये तीनों ने मुख्यमंत्रीयों के रूप में काम किए थे और सीबीबी का हिस्सा है. महाराष्ट्र में ये व्यापार विजय होने की वजह है कांग्रेस सरकारें सहकारी समितियों के लिए साम्राज्यवादी वित्तीय

पूंजी से एक बड़ी रकम रुण के रूप में उपलब्ध कराते हुए संपूर्ण मदद दीं और नव–औपनिवेशिक शोषण से उन्हें बांध लीं. इस तरह सहयोग देने के नाम पर साम्राज्यवादी पूंजी ने अधिक मुनाफें आर्जित की. महाराष्ट्र सरकार ने 1961 में भूमि सुधारों के तहत गन्ने बागानों को जब्त करना जमींदारों एवं उनके नेतृत्व में स्थापित निजी चीनी मिलों के लिए बड़ा झटका था. 1990 से पहले सरकारी नीति के तौर आयातों पर नियंत्रण लगाना, लैसेंसों में सहकारी समिति क्षेत्र के चीनी मिलों एवं दुग्ध डयरीयों के लिए आरक्षण देना, गन्ना उगाने वाले इलाकों एवं दुग्ध शेडों को प्रत्याशित रूप से उपलब्ध करना बड़े जमींदारों के लिए नुकसानदेह है, जबकि दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग को उससे मदद मिली.

सत्ता हस्तांतरण से पहले गुजरात में चीनी सहकारी समितियों के मिलों पर सांप्रदायिक कच भाटिया व्यापरियों ने सघन विरोध जताया. पर पाटीदार पीछे नहीं हटें. सत्ता हस्तांतरण के बाद गुजरात में 25 लाख किसानों के बहुत बड़े दुग्ध समूह (कंगलोमरेट) के रूप में गुजरात कोआपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF) का उद्‌भव हुआ. चूंकि दुग्ध सहकारी समितियां पाटीदार किसानों को लाभदायक रही, इसलिए वे निरंतर विस्तार किया. पांच मुख्य दुग्ध सहकारी समितियों के तमाम संस्थापक पाटीदार ही थे. वे सहकारी समितियों को इस्तेमाल कर आर्थिक रूप से न सिर्फ मजबूत हुए, बल्कि सीबीबी का हिस्सा बने. सहकारी समितियां देखने के लिए तमाम हिस्सेदारों की सहभागिता से चल रही हो, लेकिन वास्तव में वे निजी परिवारों द्वारा संचालित की जाने वाली व्यापार संस्थाओं के अलावा और कुछ नहीं.

इसी तरह गैर–व्यापारी पीड़क जातियों से संबंधित नायर, उत्तर भारत देश के कायस्थ, राजपूत जैसे लोगों से भी दलाल पूंजीपति विकसित हुए. नायरों में, टीपीजी नंबियार (बीपीएल), सीपी कृष्णन नायर (लीला होटल्स), राजन पलनी (बिस्कट्स, काजू), के. रवींद्रनाथन नायर (काजू के नंबर एक निर्यातक), शुभाष मीनन (टेलीकाम साफ्टवेयर), पीएनसी मीनन (रियल एस्टेट), राम मीनन (आटो उपकरण) आगे आए. कायस्थ जाति से, जेपी श्रीवास्तवा (कपड़ा मिल), एसपी सिन्हा (जान्सन एवं निकोल्सन), जगदीश सक्सेना (औषधीय कंपनी) जैसे लोग को छोड़कर दलाल पूंजीपतियों के रूप में विकसित होना बहुत कम है. राजपूत लोगों में, मात्र चौहान भाइयों (बिसलेरी, फ्रूटी, बिस्केट्स) ने ही देखने को मिलते हैं.

सांप्रदायिक दलाल पूंजीपति वर्ग की आधिपत्य के कारण उत्तर भारत देश में अन्य मध्यम जातियों से संबंधित जाट, यादव, गुर्जर आदि लोगों में से व्यापारी एवं उद्यगपति उतना विकास नहीं कर पाया. वे गन्ना, धान, गेहूं, कपास, तेल निकालने

वाली फसल एवं दूध बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं. लेकिन चीनी मिलों एवं ब्रांडेड चावल मिलों के मालिकों के रूप में, धान के निर्यातकों के रूप में, संपन्न वस्त्र उद्योगपतियों/व्यापारियों और धनी खदान मालिकों एवं दुग्ध प्रासेसरों के रूप में इन जातियों से बहुत कम लोग दिखायी पड़ते हैं. उस इलाके में 2008 तक दस बहुत बड़ी चीनी कंपनियों में से जाट सिख मालिकाना में मात्र एक ही कंपनी (सिंभावोली सुगर मिल्स) है. गुज्जरों के दुग्ध डायरी कंपनी मात्र एक ही वीआरएस फुड्स (पारास) है. शक्तिशाली मीडिया को स्थापित करने की ताकत इन (उत्तर भारत देश के पिछड़े) जातियों में नहीं है. इस तरह इस मामले में उत्तर भारत देश में जाति एवं वर्ग लगभग एक समान हो गया है.

देश में सांप्रदायिक मुस्लिम व्यापारी वर्गों में हिंदू व्यापार जातियां – लोहाना आदि जातियों से मुस्लिम धर्म स्वीकार करने वाले मेमन, खोजा, दाऊदी बोहरा, इनके अलावा चिनोटी शेक एवं कोंकण मुस्लिम शामिल हैं. पुराने गुजराती–सिंधी व्यापार समुदायों के बुनियाद से अन्सारी एवं खुरेशी समुदायों के मुस्लिम व्यापारी आगे आए. कोंकण मुस्लिमों से 18वीं सदी की शुरूआत में ही प्रसिद्ध मुल्ला अब्दुल गफार बड़े दलाल व्यापारी के रूप में विकसित हुआ. 19वीं सदी की शुरूआत में ये मुस्लिम समुदाय और पारंपरिक व्यापार समुदाय – पारसी एवं हिंदू वैश्य समुदाय ज्यादातर विषयों में एक समान रहते थे. मुस्लिम समुदाय 19वीं सदी के पहले अर्धभाग में पूरे भारत देश के उपमहाद्वीप में सुदूर व्यापार संबंध बनाए थे. इन्हें बंबई (मुंबई), कोलकता एवं अन्य सुदूर प्रांतों में दुकान होते थे. मुंबई प्रेसिडेंसी, मध्य, पूर्व भारत देश एवं बर्मा में व्यापार करते थे. ओडिशा से बंगाल–बर्मा अरका समुद्रीय तट तक पूरे पूर्वी भारत देश के चावल व्यापार पर आधिपत्य हासिल किए थे. 19वीं सदी के अंत तक मेमन एवं खोजा समुदाय भारत देश से विदेशों में – लाल सागर, पर्शियन खाड़ी के बंदरगाहों, पूर्वी व दक्षिणी अफ्रीका, श्रीलंका, चीन एवं सुदूर पूर्वी इलाकों के बंदरगाहों तक अपने व्यापार विस्तार किए थे. 1930 के दशक में हैदराबाद निजाम ने ज्वाइंट वेंचरों (संयुक्त उद्यमों) के जरिए आधुनिक मुस्लिम उद्योगपति विकसित हुए. इस तरह सत्ता हस्तांतरण के पहले मुस्लिम उद्योगपति विकसित हुए. फिर भी, उनमें से ज्यादातर उद्योगपति में यह डर था कि मारवाड़ी, गुजराती हिंदू/जैन बनिया पूंजी उन्हें निगल सकता है, तो अपने व्यापारों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर, जब देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान की तरफ अपने राय बनाए थे. सत्ता हस्तांतरण के बाद मुस्लिम खोजा समुदाय के आजीम हश्म प्रेमजी, दाऊदी बोहरा समुदाय के हबिल फकृद्दीन खोराकिवाला, बोहरा व्यापारी सिराज लोखंडवाला, मेमन समुदाय के अब्दुल रजाक अल्लाना आदि ने

सीसीबी के रूप में विकसित हुए. अन्सारी एवं खुरेशी समुदायों के मुस्लिम व्यापार मांस एवं चमड़े के उद्योगों में आधिपत्य चलाते हुए सीबीबी उद्योगों के रूप में बदल गए. सांप्रदायिक रूप से बुनकर काम करने वाले अन्सारी समुदाय ने 1960 के दशक से महाराष्ट्र के भिवांडी, मालेगांव आदि शहरों में विकेंद्रीकृत पॉवरलूम उद्योग को विकसित कर मुस्लिम सीबीबी के रूप में ज्यादातर व्यापार चला रहे हैं. उत्तरप्रदेश के वारणासी–माउ हथकरघा गलियारा में 1970 के दशक के अंत से दलालों एवं इजारेदार व्यापारियों के रूप में विकसित हुए.

उत्तर कन्नड जिले के भक्तकाल के नवयत समुदाय ने दक्षिण भारत देश के राज्यों में एवं मुंबई में छोटे व्यापारों पर आधिपत्य हासिल करने के अलावा कई स्कूल–कालेज चलाते हुए सीबीबी बन गए. केरल के मलाबार मुस्लिम या मोपला समुदाय ने 1970 के दशक में जब तेल की कीमते बढ़ी, इन्होंने खायी प्रांत में प्रवास किया और खूब कमाया. इससे एक नयी पीढ़ी के मुस्लिम प्रवासी भारतीय सीबीबी के रूप में आगे आए. इसमें सरकारी मदद का भी योगदान रहा. इस समयकाल में घटित परिणामों में मोपला समुदाय के विरुद्ध हैदराबाद जैसे पुराने केंद्रों में मुस्लिम सीबीबी बहुत कमजोर हुए. हालांकि मुस्लिमों में संसदीय पार्टियों एवं सरकार में पदासीन कुछ नौकरशाह उच्च अधिकारियों से सीबीबी में शामिल लोग हैं.

पंजाब में आधुनिक काल में गैर–सांप्रदायिक रामगढ़िया जाति के लोग बनिया समुदाय जो ग्राम स्तर से सूदखोरी, बुनियादी स्तर के उत्पादन, थोक व्यापार, बिल डिस्काउंटिंग, अंतिम उत्पादनों की तैयारी, मार्केटिंग, इस तरह पूरी व्यापार श्रृंखला पर आधिपत्य रखता है, उससे प्रतिस्पर्धा लेते हुए व्यापारी दक्षता विकसित की. साइकिल, आटो कलपुरजें, मशीन उपकरण (टूल्स), वस्त्र उद्योग के सामग्री, कृषि यंत्र तैयारी क्षेत्रों में विकसित हुए. लेकिन बनिया आधिपत्य को चुनौती देते हुए, वस्त्र उद्योग के यंत्र, ब्रांडेड साइकिल, ट्रेक्टर तैयारी को नियंत्रित करने वाली अगले चरण में वे आगे नहीं बढ़ पाया.

दलितों से मात्र एक बहुत ही छोटी तबका बड़े दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग के रूप में विकसित हुई. इन जातियों से देशभर में सरकारी योजनाओं, शिक्षा व रोजगारों में आरक्षण को इस्तेमाल कर, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि उच्च पढ़ाई होने वाली तबके से बहुत ही छोटी तबका इस तरह परिवर्तित हुई. इनमें से ज्यादातर लोग छोटे व मध्यम स्तर के व्यापारी एवं उद्योगपति ही हैं. लेकिन वे अपने अस्तित्व के लिए दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग से संबंध बनाकर, आर्थिक एवं वैचारिक रूप से साम्राज्यवादी नयी उदारवादी नीतियों का समर्थन

करते हैं. इनमें से बहुत कम लोग दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग में शामिल हो रहे हैं.

इसी तरह आदिवासी समुदायों से एक बहुत छोटी तबका दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग में शामिल हो रही है.

भारत देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग का उद्‌भव, वृद्धि एवं विकास को समझने के लिए इस क्रम को तीन विस्पष्ट चरणों में विभाजित किया जा सकता है: 1. उपनिवेश काल से 15 अगस्त, 1947 तक; 2. 15 अगस्त, 1947 से 1991 तक; 3. 1991 से 2024 तक.

4. पहला चरण उपनिवेश काल से 15 अगस्त, 1947 तक:

भारत देश में प्राचीन काल से वर्णव्यवस्था और उसके उपरांत सामंतवादी समाज काल के सीढ़ीदारी जाति व्यवस्था के बुनियादवाला स्थायी श्रम विभाजन हो गया. पहले कृषि काम करने वाले वैश्य समुदाय से बनी चौथी वर्ण–शूद्र वर्ण से कृषि काम करने वालों एवं कारीगरों के साथ अलग कई 'शूद्र' जातियां बन गयीं. बहुत कम संख्या में वैश्य समुदाय व्यापार तक सीमित हो गया. जिन्हें संपदा एवं जमीन से वंचित किया गया, उन्हें छूआछूत से दूर रखकर एवं निचले पायदान वाले कहकर पंचम वर्ण के रूप में वर्गीकृत किया गया. शूद्र समुदायों में कुछ कारीगर समुदायों को भी पंचम वर्ण में धकेल दिया गया. जाति व्यवस्था के रीति–रिवाज के चलते, शूद्र एवं पंचम वर्णों में अनगिनत कारीगर जातियां व्यापारियों के रूप में बदलने का अवसर, व्यापारी कारीगर पेशों में प्रवेश कर उत्पादन में हिस्सा लेने का अवसर नहीं रह गया. कर्म सिद्धांत से शूद्रों एवं छूआछूत जातियों को दबाने में कामयाब हुए. मात्र वैश्य समुदाय ही व्यापार करने के जातिगत रिवाज के चलते उसी जाति के लोगों (कुछ मुस्लिम एवं पारसी समुदाय को छोड़कर) से ही लगभग तमाम व्यापारी वर्ग एवं सूदखोर बन गए. ये उत्पादन में हिस्सा नहीं लेते थे, ये बैंकरों के रूप में रुण देते थे, पैसे के लेन–देन करते थे, शुल्क वसूली करते हुए सामंती राजाओं की सीवा करते थे, विदेशी व्यापारियों का कमिशन एजेंट के रूप में काम करते थे, इस तरह पैसे कमाते थे. नवाबों एवं राजाओं को युद्धों में रुण देते थे. इस तरह सामंतवादी व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था को संरक्षण देते हुए ही व्यापारी पूंजी का संचयन हुआ था. भारत देश में 16वीं सदी तक ही यानी ब्रिटिश के आगमन के पहले ही सामंतवादी व्यवस्था पर निर्भर होने वाले व्यापारियों का उद्‌भव हुआ था. व्यापारी एवं सूदखोरी पूंजी, नवाबों, राजाओं, जमींदारों की पूंजी, कुछ हद तक कारीगरों से आयी पूंजी से पहले उद्योग विकसित हुए थे. मुगल

भारत देश में बहुसंख्यक लोगों का मुख्य पेशा कृषि ही था. इसके बावजूद यह देश वस्तु उत्पादन के एक संमृद्ध देश भी है. वह अंतरराष्ट्रीय एवं देशीय जरूरतों पूरा करता था. ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में गैर–कृषि वस्तु उत्पादन व्यापक रूप से होता था. पुराने एवं कमजोर हो रहे सामंती समाज के गर्भ में, कमजोर रूप में ही सही, पूंजीवादी शक्तियों की पैदाईश शुरू हुआ.

ऐसी स्थिति में पहले पुर्तुगाल, उसके बाद डच एवं अंग्रेजी लोग भारत देश में व्यापार करने के लिए आए थे. समुद्र इलाकों पर आधिपत्य हासिल करने के लिए उनके बीच तीखी प्रतिस्पर्धा होती थी. तब तक नवाबों, जमींदारों के व्यापारियों, भारत देश के बड़े–बड़े व्यापारियों एवं बैंकरों के रूप में होने वाले पारसी व्यापारी, गुजराती व्यापारी, राजस्थानी व्यापारी आदि कई लोग यूरोप वालों के एजेंट बन गए. मात्र एक छोटी तबका ही स्वतंत्र रह गयी. एजेंट बननेवाले व्यापारी उत्पादन से संबंध नहीं होने एवं कमिशनों पर निर्भर होकर उनकी तरक्की होने की वजह से, इस व्यापारी वर्ग में राष्ट्रीय स्वभाव नहीं उभरा. विदेशी व्यापारी देश को लूटने के बावजूद उन्होंने फिक्र नहीं किया.

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत देश में व्यापार करने में पहला उद्देश्य मात्र यह था कि भारत देश के वस्तुवों एवं फसलों के व्यापार में एकाधिकार हासिल कर बड़े पैमाने पर मुनाफें आर्जित करना. उनका आशय था जो मसाले, धागा (सूत), रेशम कपड़े वगैरा वस्तुवों के लिए इंग्लंड एवं यूरोप के बाजार में मांग होती थी, भारत देश में मिलने वाले उस माल को बहुत कम दाम पर खरीद कर अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक दाम पर बेच कर इजारेदार मुनाफें प्राप्त करना. भारत देश के सामंती राजाओं में से एक तबके को यूरोपीय व्यापारिक इजारेदारों से आर्जित भरपूर मुनाफें में एक हिस्सा मिलता था. कई दलाल विदेशी व्यापारी संस्थाओं में काम करते हुए ही, स्वयं अपने व्यापार भी चलाते हुए अधिक मात्रा में पैसे कमाएं. सामंती राजाओं की सेनाओं में काम करने वाले कई नौकरशाह अधिकारी भी विदेशी व्यापारों में अधिक मुनाफें आर्जित किए थे. ब्रिटिश वालों के लिए दलाली काम करते हुए कई मारवाड़ी 17 व 18वीं सदियों में बंगाल, बिहार एवं ओडिशा इलाकों में मुख्य व्यापारियों के रूप में बसे.

17वीं सदी में डच एवं इंग्लिश वाले मिलकर पुर्तुगाल वालों को हराए थे. उसके बाद बिटिश वाले डच वालों को हराए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था. ब्रिटिश उपनिवेशवादी 1757 में प्लासी की युद्ध में जीत हासिल कर प्रत्यक्ष रूप दुराक्रमण करने तक भारत देश में गुजरात, राजस्थान, बंगाल, मैसूर एवं तमिलनाडु इलाकों में व्यापार पूंजी एवं सूदखोर पूंजी का संचयन

अधिक मात्रा में हुआ था. ब्रिटिश वाले बंगाल को जीतने के लिए रची साजिश में जगतसेठों, ओमिचंद जैसे भारत देश के बैंकर देशद्रोही भूमिका निभाई थी. इसी तरह देश के अन्य हिस्सों में मारवाड़ी, गुजराती, पारसी व्यापारी एवं बैंकर भी सामंती राजाओं के खिलाफ ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा चलाए गए युद्धों के लिए आर्थिक सहायता समेत तमाम तरीके की परोक्ष सहायता दी थी. देश के विभिन्न इलाकों में ब्रिटिश शासन को विस्थारित करने में कई तरीकों में उन्होंने सहायता दी. ब्रिटिश उपनिवेशवादी भारत देश में अपने सामने झुकने वाले सामंती राजाओं, जमींदारों, अपने दलाल बनने वाले सूदखोरों एवं व्यापारियों से सांठगांठ होकर, न सिर्फ अपनी सत्ता को कायम रखा, बल्कि अपने पिछलग्गू बनने वाले दलाल व्यापारियों की वृद्धि के लिए, तद्वारा मांचेस्टेर एवं लांकाशैर में औद्योगिक उभार का रास्ता सुगम बनाए थे. अपने दलाल नहीं बनने वाले स्वतंत्र एवं राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग को ध्वस्त किए थे. ब्रिटिन आधिपत्य एवं दुराक्रमण का डटकर मुकाबला करने वाले झांसी लक्ष्मीबाई, तांतिया तोपे, टिप्पु सुलतान जैसे देशभक्त शक्तियों को, गदर वीरों, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सूर्यसेन जैसे राष्ट्रीय क्रांतिकारियों को, आदिवासी बगावतों का नेतृत्व करने वाले सिदो–कानो, सड्मेक बाबूराव, गुंडाधुर, अल्लूरि सीतारामराजू, बिरसा मुंडा, कोमुरम भीम जैसे साहसिक आदिवासी नेताओं को, उत्पीड़ित जनता की मुक्ति के लिए लड़ने वाले सच्ची कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को सफाया किया था. लगभग दो सदियों तक हमारा देश को अपना उपनिवेश बनाया था और उसे ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादनों के लिए कच्चे माल का स्त्रोत के रूप में एवं अपने औद्योगिक तैयारी वस्तुओं का बाजार के रूप में तब्दील किया था, तद्वारा भारत देश में पूंजीवाद का स्वतंत्र विकास को अवरुद्ध किया था. इससे भारत देश के सामंती समाज औपनिवेशिक एवं अर्ध–सामंतवादी समाज के रूप में बदल गया था. इस समयकाल को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता हैः व्यापारी पूंजी का चरण, औद्योगिक पूंजी का चरण एवं वित्तीय पूंजी का चरण.

व्यापारी पूंजी का चरणः यह 1757 से 1813 तक जारी रहा. इस चरण में शोषण करने के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा अपनायी गयी तमाम तरीकें मुख्य रूप से असमान व्यापार एवं बुनियादी पूंजी संचयन से संबंधित थे. आज भारत देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग में आधिपत्य तबके के रूप में होने वाले पारसी, बनिया एवं मारवाड़ी में ज्यादातर लोग ब्रिटिश के शासन काल में ही महाराष्ट्र से पूर्वी भारत देश के असम तक विस्थारित हुए. मारवाड़ियों में अधिक लोग पहले से विदेशी उत्पादकों एवं भारत देश के उपभोक्ताओं के बीच विदेशी निर्यातकों एवं हमारे देश के आयतकों के विचौलियों के रूप में व्यवहार करते हुए मजबूत घास

फूस की तरह पीड़ा के रूप में बने रहे. इस चरण में शोषण करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनाए गए तरीकें – असमान व्यापार के जरिए शोषण करना, बलप्रयोग के जरिए कारीगरों एवं छोटे व्यापारियों को नष्ट करना, भारी अतिरिक्त शुल्क लगाना, प्रत्यक्ष रूप से सेना के साथ हमला कर देश की जनता को एवं संपदा को लूटना और नील बागान मालिकों का उत्पीड़न. लेकिन 1813 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया.

ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन ने भारत देश में ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में कुछ बदलावों के साथ संरक्षित करते हुए, सामाजिक एवं धार्मिक अज्ञान एवं अमानवीय छूआछूत को बढ़ावा दिया और सामंतवादी संबंधों को पुनरुद्धार कर, जाति–आधारित सामंतवाद को अपनी सामाजिक बुनियाद बनायी. देश में औपनिवेशिक उत्पादन संबंधों (colonial mode of production) शुरू किया. विभाजन करो–राज करो के दुष्टनीति को लागू कर औपनिवेशिक शासन के जंजीरों को मजबूत किया. जमीन एक माल बन गया. माल–पैसे के संबंधों की घुसपैठ हुई. देश के स्वतंत्र उद्योग एवं व्यापार ध्वस्त हो गए. स्वयंपोषक ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट हो गया. किसान एवं कारीगर दिवालिया हो गए. कर भार आदि ब्रिटिश सरकार की जनविरोधी नीतियों से कई पुराने स्वतंत्र बड़े व्यापारी एवं बैंकर दिवालिया हो गए. ब्रिटिश वालों के लिए दलाल बनने वाले व्यापारी एवं सूदखोर दलाल व्यापारी वर्ग के रूप में परिवर्तित होकर मजबूत हुए. देशीय बाजार नष्ट हो गया.

औद्योगिक पूंजी का चरणः इस चरण 1813 से 20वीं सदी की शुरूआत तक चलता रहा. इस चरण में एक उपनिवेश के रूप में पराधीन हैसियत से भारत देश की अर्थव्यवस्था विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के अभिन्न अंग बन जाना बहुत मुख्य बदलाव था. औद्योगिक वस्तुवों को निर्यात करने की स्थिति से आयात करने की स्थिति में उसका पतन हुआ. सामंती संबंध अर्ध–सामंती संबंधों के रूप में बदल गए. भारत देश के दलाल व्यापारी दलाल पूंजीपति वर्ग के रूप में परिवर्तित होना शुरू हुआ. आधुनिक सर्वहारा वर्ग का उद्‌भव हुआ.

भारत देश से लगातार शोषण कर ले जायी गयी संपदा से उनके देश में औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाना ब्रिटिश की औद्योगिक नीति रही थी. उसकी अनुषंगी विभाग के रूप में भारत देश की उपनिवेश व्यवस्था को तब्दील कर दी. भारत देश में विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों के बीच संतुलन को नष्ट किया. उसके प्राकृतिक संसाधनों को लूट कर उत्पादक शक्तियों का विकास को रोक दिया. इसीलिए मार्क्स ने यह राय दिया कि ''उपनिवेश शासन ने पूंजीवादी व्यवस्था के

लिए वस्तुगत आधारभूत अंश बनाना नहीं, बिल्क अस्तित्व में होने वाली उत्पादक शक्तियों को नष्ट कर, नयी उत्पादक शक्तियों के विकास में अवरोध पैदा कर कर भारत देश को पिछड़ेपन में धकेल दिया था'' (भारत देश पर लेख, पृष्ठ 1).

1850 के दशक से पहले भारत देश में पारसी, बनिया एवं मारवाड़ी दलालों के हाथों में अपार संपदा जमा हुई थी. लेकिन उससे आधुनिक उद्योगों में लगाया गया निवेश बहुत कम था. इस दौरान ब्रिटिश पूंजी भी यहां फैक्टरी उद्योग लगाना में बिलकुल ध्यान नहीं दिया. कपास के बीज निकालने वाले कारखानें (cotton ginning mills), प्रेस, आटे के मिल, बिटिश पूंजी से बंगाल में दो वस्त्र उद्योग, फेंच वालों की पूंजी से पुडुचेरी में एक वस्त्र उद्योग, इस तरह बहुत कम उद्योग लगाए गए. वस्त्र उद्योग उतना सफल नहीं हो पायी. कपास के बीज निकालने वाले काटन जिन्निंग मिल एवं काटन प्रेसिंग मिल मौसमी–वार काम करते थे. इनकी स्थापना के पीछे उद्देश्य है कच्चे कपास से बीज निकाल कर कपास को आसानी से निर्यात करने में सहयोग देना.

1850 के दशक से पहला विश्व युद्ध के बीच भारत देश के उद्योगपतियों के मालिकाना में मुख्य तौर पर दो उद्योग थे – वस्त्र उद्योग एवं इस्पात उद्योग. बंबई एवं अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग लगाने वाले तमाम लोग लंबे समय से ब्रिटिश पूंजी के लिए दलालों के रूप में और उसके स्थानीय बिचौलियों के रूप में काम किया. वे नकदी पूंजी एवं अन्य सहायता के लिए राजाओं पर आधारित थे.

1890 के दशक के अंत में ब्रिटिश सरकार भारत देश में लोहा–इस्पात फैक्टरी लगाने के लिए तैयार हुई. टाटा द्वारा लगाए गए लोहा–इस्पात उद्योग के लिए पूंजी ज्यादातर भारत देश के सामंती राजाओं से ही आयी. उदाहरण के लिए ग्वालियर महाराजा (सिंधिया) ने कार्यकारी पूंजी रकम जुटायी. इससे यह उजागर होता है कि एक तरफ साम्राज्यवाद एवं दलाल पूंजीपति वर्ग बीच, दूसरी तरफ साम्राज्यवाद एवं सामंती वर्ग के बीच कितना नजदीकी सबंध थे. टाटा समुदाय के जल विद्युत परियोजना भी इस तरह की पूंजी से ही लगायी गयी.

सासन ग्रुप, करीमभाई ग्रुप, पित्ति ग्रुप, वाडिया ग्रुप, टाटा ग्रुप जैसे प्रमुख वस्त्र उद्योगपतियों के हित ब्रिटिश वालों के हित नजदीकी से जुड़े हुए थे. वे दलालों के रूप में लांकशैर को निर्यात करने के लिए कच्चे कपास इकट्ठा करते थे. लांकशैर मिल कपड़ों को लाकर इस देश के बाजार में, लांकशैर धागा एवं तैयारी वस्तुओं को चीन एवं अफ्रीका में बेचते थे. यंत्र के कलपुरजें, तकीनीकी ज्ञान एवं बाजार के लिए वे भारत देश के वस्त्र उद्योग पूरी तरह ब्रिटिश उत्पादकों पर निर्भर

थे. इससे भारत देश के सस्ते श्रम द्वारा पैदा हुई अतिरिक्त मूल्य में अधिक हिस्सा ब्रिटिश वालों को ही भुगतान करना पड़ता था.

ब्रिटिश एवं भारत देश के बड़े पूंजीपती आपस में बांटे जाने वाले आपार मुनाफें भारत देश के मजदूरों एवं कपास किसानों के भयानक शोषण द्वारा मिलते थे. ब्रिटिश–भारत देश के उद्योगपतियों, नीचे से ऊपर तक के बिचौलियों, सूदखोरों एवं जमींदारों, ये तमाम लोगों के गठजोड़ ने भारत देश की जनता को धोखा दिया और शोषण किया.

टाटा ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के देखरेख में विकसित हुए बड़ा व्यापारी, उद्योगपति, समूचा बंबई के सबसे बड़ा जमींदार एवं सूदखोर था. जमीन क्रय–विक्रयों में अपार पूंजी लगाकर बड़े पैमाने पर सूदखोरी करता था. टाटा की तरह गोयंका, बिड़ला जैसे भारत देश के दलाल साम्राज्यवादी पूंजी से गठजोड़ बनाने की वजह से बहुत कम समय में ही अपार संपदा जुटा पाईं.

भारत देश में ब्रिटिश मेकाले शिक्षा नीति से प्रभावित होने वाली दलाल एवं सामंती शक्तियों द्वारा शुरू किया गया पश्चिमीकरण आंदोलन भी उपनिवेश शासन के जंजीरों को मजबूत किया. मेकाले शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य मात्र यह था कि साम्राज्यवादी देश एवं उपनिवेश देश के बीच दास संस्कृति एवं बुद्धिमत्ता होने वाली बिचौलियों के वर्ग को पैदा करना. इस तरह पैदा हुए शिक्षित समुदाय, बड़े दलाल एवं जमींदार अपने अस्तित्व एवं वृद्धि के लिए उपनिवेश शासन पर निर्भर हुए. इससे जाति आधारित सामंतवाद एवं अर्ध–सामंतवाद को कायम रखना ब्रिटिशों के लिए आसानी हो गया.

भारत देश में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा निर्मित रेलवे एवं सड़क आधुनिक उद्योग के लिए रास्ता नहीं बनाया, बल्कि देश को ब्रिटेन के लिए एक कृषि अनुषंगी के रूप में एवं उसके औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार के रूप में बदलने वाले साधन के रूप में साबित हो गया. पश्चिम यूरोप एवं अमेरिका में रेलवे ने औद्योगिक क्रांति के उत्प्रेरक का काम किया. इसके विपरीत भारत देश में वे पूरी उपनिवेशीकरण के उत्प्रेरक का काम किया. चाय, रबड़ एवं काफी बागान, खदान एवं जूट उद्योग लगभग पूरी तरह ब्रिटिश पूंजी के अधीन में रहते थे. इसी तरह पहला विश्व युद्ध के पहले भारत देश में संगठित उद्योग पर लगभग ब्रिटिश पूंजी का प्रभुत्व होता था. लेकिन ब्रिटेन में विकसित पूंजीवाद ने अपने हितों के लिए इस उपमहाद्वीप की व्यापक अर्ध–सामंती व्यवस्था के अंदर ही उसपर आधारित होने वाले कुछ औद्योगिक इलाकों की वृद्धि को बढ़ावा दिया.

उस समय भारत देश में पूंजीपति वर्ग दो वर्गों के रूप में अलग–अलग रहते थे. एक वर्ग साम्राज्यवादी विदेशी पूंजीपतियों के हितों को पूरा करने वाले एवं उनसे चयनित बड़े दलाल पूंजीपति वर्ग था. दूसरा वर्ग स्वतंत्र विकास के लिए प्रयास करने वाले राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग था. बड़े दलाल पूंजीपति वर्ग पीड़क जातियों, विशेषकर व्यापारी जाति समुदाय के जड़ें होने की वजह से एवं ब्रिटिश उपनिवेश शासन में साम्राज्यवादी इजारेदार पूंजी से गठजोड़ बनाने की वजह से वह पूंजी, प्रबंधन के कौशल, बाजार एवं तकनीकी ज्ञान हासिल करने एवं बढ़ाने तथा प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनुकूलताएं प्राप्त कर पायी है. इसके विपरीत राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग ने विदेशी पूंजी से गठजोड़ बनाने का विरोध किया और बताया कि विदेशी पूंजी देश के आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं प्रगति के लिए अवरोध है. ब्रिटिश साम्राज्यवादी दलाल पूंजीपति वर्ग को पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए, अपने हितों के लिए खतरा होने वाले राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग को नष्ट करने के लिए हरसंभव प्रयास किया.

वित्तीय पूंजीपति चरणः 20वीं सदी की शुरूआत में साम्राज्यवाद का उद्‌भव के साथ इस चरण की शुरूआत हुई. पहला विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद कमजोर हो गया. ब्रिटिश साम्राज्यवाद से प्रतिस्पर्धा लेते हुए नए तौर पर अमेरिका एवं पहला विश्व युद्ध के हार का संभाल कर फिर से जर्मनी की साम्राज्यवादी शक्तियां सामने आयी. रूस में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने अक्टूबर क्रांति को सफल बनाने के साथ विश्व में पहला समाजवादी राज्य का उद्‌भव हुआ एवं विश्व उत्पीड़ित जनता को एक मुक्ति का रास्ता दिखाया. वह साम्राज्यवादी व्यवस्था के अस्तित्व को ही खतरा बन गया. ब्रिटिश–इंडिया साम्राज्यवादी सरकार ऐसे आर्थिक, सैनिक एवं राजनीतिक कारणों की वजह से अपनी औद्योगिक नीति में बदलाव किया. उसी समय में भारत देश की जनता में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के खिलाफ तेज होते जा रहे आक्रोश को बुझाने के लिए एवं भारत देश के हितों से साम्राज्यवादी हितों को प्राधमिकता देते हुए भारत देश के बड़े पूंजीपति वर्ग द्वारा दी जा रही विश्वसनीय सेवाओं को मान्यता देते हुए, भारत देश में अपनी सामाजिक बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए उन्हें कुछ रियायतें दी.

इसके तहत ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने अपने हितों को एवं ब्रिटिश–इंडिया सरकार को बचाने एवं मजबूत करने के लिए ही उपनिवेश भारत देश में कुछ उद्योगों को विकसित किया. भारत देश के औद्योगिक आयोग (1916–1918) को गठित किया और लोहा–इस्पात, धागा, कागज, माचिस, सिमेंट, जूट, चीनी, भार रसायन जैसे उद्योगों के लिए सब्सिडियों एवं प्रतिभूतियों (securities) की मंजूरी

दी. ये बिड़ला, सिंगानिया, श्रीराम, गोयंका, दाल्मिया जैन, सूरजमल नागरमल, रूइया, पोद्दार, थापर, वालचंद, चेट्टियार, नायुडू जैसे भारत देश के नए बड़े पूंजीवादी ग्रुप उभरने में रास्ता बनाया. भारत देश के बड़े दलाल पूंजीपतियों एवं सामंतियों को प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस पार्टी ने 1920 के दशक की शुरूआत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी विरोधी जनांदोलन पर पानी फेर दिया.

ब्रिटिश–इंडिया सरकार के कानून–1935 के तहत देश में 2 प्रतिशत मतदाताओं से संसदीय व्यवस्था अस्तित्व में आयी. इसमें ब्रिटिश वालों से मिलकर भारत देश के बड़े दलाल पूंजीपति एवं सामंती वर्ग ने सत्ता का हिस्सा बने. साम्राज्यवादी पूंजी एवं भारत देश के बड़े दलाल पूंजीपति वर्ग की पूंजी दोनों ने इसका लाभ उठाया. विभिन्न साम्राज्यवादी देशों के बड़े इजारेदार संस्थाएं – इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज, यूनिलिवर, डनलप, ब्रिटिश ऑक्सिजन, गेस्ट कीन विलियम्स, बाटा, अल्युमिनियम लिमिटेड, यूनियन कारबाइड एवं स्वीडिश माचिस कंपनी भी उतर कर भारत देश के उद्योग पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए वस्तु उत्पादक यूनिटों को स्थापित की. दो विश्व युद्धों के बीच के समय में ब्रिटिन से भारत देश में आने वाले निर्यातों का स्थान गैर–ब्रिटिश साम्राज्यवादी देशों के निर्यातों ने ले लिया. टाटा ग्रुप ने उस समय ब्रिटिश पूंजी एवं अमेरिकी पूंजी से नजदीकी संबंध स्थापित किए. बंबई एवं कोलकता के मारवाड़ी पोद्दार, बजाज, बिड़ला एवं रूइया की ग्रुप जापान के मिट्सुई और कई अन्य व्यापार संस्थाओं के साथ संबंध बनाए. पहला विश्व युद्ध के समय में युद्ध के मुनाफों से समृद्ध बननेवाली कई मारवाड़ी संस्थाएं उद्योग में पूंजी लगाना शुरू किया. नौका निर्माण यार्ड, आटोमोबाइल्स एवं विमान उद्योग को स्थापित करने के मामले में ही नहीं, बल्कि कई उद्योगों को स्थापित करने में भी साम्राज्यवादी पूंजी पर असीमित निर्भरता भारत देश के बड़े पूंजीपति वर्ग का ही लक्षण है.

भारत देश की बड़ी पूंजी ने भारत देश के अंदर विदेशी पूंजी की दासता करना ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश कब्जे में होने वाले अन्य उपनिवेशों को भी उसका सहयोग से शोषण करने लगे. सूदखोरी एवं व्यापार करने वाले तमिलनाडु के नट्टकोट्टाय चेट्टियारों ने 1930 तक श्रीलंका, मलया, सिंगपुर, बर्मा जैसे दक्षिण–पूर्व एशिया देशों में अपने कार्यकलाप विस्तारित किए. चेट्टियार निजी बैंकिंग संस्थाओं एवं ब्रिटिश विनिमय बैंकों के लिए स्थानीय बिचौलियों के रूप में काम किया. इसी तरह चेट्टियार की सूदखोरी की वृद्धि के लिए उपनिवेशी व्यवस्था से बहुत मदद मिली. चेट्टियार दक्षिण भारत देश में बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में रहते थे. उद्योगों की तरह बैंकिंग में भी ब्रिटिश एवं भारत देश की पूंजी का मेलमिलाप

हुआ. इनमें ब्रिटिश पूंजी की ही मुख्य भूमिका रही. उदाहरण के लिए, बंगाल, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय से 1921 में गठित इंपीरियल बैंक आफ इंडिया भारत देश में सबसे बड़ा बैंक था. इसे ब्रिटिश वालों ने ही नियंत्रित किया. इस बैंक में सरकार की तमाम खजाना निधियों को डिपाजिट किया जाता था. सरकारी रुण भी इसका प्रबंधन में ही होता था. वह सरकारी बैंक के रूप में भी काम करता था. इस तरह विदेशी पूंजी एवं भारत देश की बड़ी पूंजी और अधिक लपेटा गया. भारत एवं ब्रिटेन देश के मालिकाना वाले सिमेंट कंपनियां दो इजारेदार संस्थाओं के रूप में स्थापित हुईं.

दूसरा विश्व युद्ध के समय में भारत देश की बड़ी पूंजी एवं ब्रिटिश पूंजी की उपनिवेशवादी राज्यतंत्र के बीच गठजोड़ पहले के मुकाबले घनिष्ट हुआ. सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध आरंभ होने के साथ–साथ बड़े दलाल पूंजीपति वर्ग के लिए प्रोत्साहक अवसर मिले. वे अपने स्वभाव के अनुसार युद्ध को सम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के अवसर के रूप में नहीं देखा, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों या जरूरत पड़े तो जापान साम्राज्यवादियों को सहयोग देने एवं देश की जनता को और गरीबी में धकेल कर अपने हितों को पूरा करने का रास्ता के रूप में देखा. इस युद्ध से उन्हें अपार मुनाफें प्राप्त हुए एवं करोड़ो जनता को अकथनीय कष्ट–तकलीफों से जूझना पड़ा एवं लाखों जनता की मौत का कारण बना.

सत्ता हस्तांतरण के समय तक भारत देश के उद्योग क्षेत्र का बहुत मुख्य लक्षण यह था कि यंत्रों का उत्पादन (capital goods or producer goods) लगभग न कि बराबर था. वह यंत्रों के लिए लगभग पूरी तरह विदेशी आयातों पर निभार होता था. कृषि क्षेत्र को पिछड़ेपन में ही रख कर एवं संकट में धकेल कर, उद्योगों की वृद्धि का गला घोंठ कर, व्यापक जनता को भुखमरी, बीमारी एवं अज्ञान में धकेलने वाली साम्राज्यवादी व्यावस्था शोषण एवं दमन पर भारत देश के बड़े दलाल पूंजीपति वर्ग कभी सवाल नहीं उठाया. इसके विपरीत 1857–58 के भारत देश के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के समय में, उसके बाद उपनिवेश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए चलाए गए जनांदोलनों में भारत देश के बड़े दलाल पूंजीपति वर्ग ने विश्वासघाती भूमिका निभाई. वह उपनिवेशवादी शासनतंत्र में कुछ सुधार करने की मांग करते हुए, उसे जारी रखना चाहा और साम्राज्यवादी शासन के ढांचे में ही सिर्फ विशेष अधिकार विस्तारित करने के लिए कोशिश किया.

1885 में ब्रिटिश उपनिवेशवादी हितों एवं भारत देश के बड़े दलाल पूंजीपति एवं बड़े सामंतवादी वर्गों के हितों को पूरा करने के लिए, साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलनों को रोकने के लिए, ब्रिटिश वालों के देखरेख में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व

में भारत देश की राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित की गयी. इसीलिए कांग्रेस पार्टी ब्रिटिश वालों से मात्र रियायत प्राप्त करने के लिए ही प्रयास किया, साम्राज्यवादी आधिपत्य को उखाड़ फेकने का प्रयास कभी नहीं किया.

कुल मिलाकर, भारत देश के बड़े दलाल पूंजीपति वर्ग अपने स्वाभाविक तौर ही ब्रिटिश साम्राज्यवादी पूंजी से गठजोड़ बनाने अलावा वह कभी आंदोलनों में नहीं उतरा था. शोषण के हिस्सें बांटने में शुल्क, प्रतिभूति (security), स्टेर्लिंग–रुपया का विनिमय मूल्य, सरकार द्वारा खरीदी गयी वस्तुएं आदि मामलों को दूसरी स्तर की समस्याओं के रूप में ही देखा. इसीलिए वह वर्ग निरंतर साम्राज्यवादी आधिपत्य एवं शोषण को बचाने के लिए साम्राज्यवादी पक्ष लेते हुए संघर्षरत जनता को विरोध किया. साम्राज्यवाद से उसका गठजोड़ मूल विषय था. राष्ट्रीय जनवादी क्रांति से इस वर्ग की गद्दारी से यह स्पष्ट हो गया.

1925 में ही भारत की कम्युनिस्ट पार्टी गठित होने के बावजूद, उसे अनगिनत अवसर मिलने के बावजूद, पार्टी के नेतृत्व की गलत लाइन के कारण राष्ट्रीय मुक्ति–जनवादी आंदोलन में उसने नेतृत्वकारी भूमिका नहीं निभा पायी. वह सैद्धांतिक एवं राजनीतिक रूप से कमजोर होने, क्रांतिकारी नेतृत्व नहीं होने एवं राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग को नेतृत्व करने की ताकत नहीं होने की वजह से कांग्रेस पार्टी के गांधीवादी, दलाल पूंजीपति एवं सामंतवादी नेतृत्व का असली वर्ग स्वभाव को पहचानने में, अंत में वह ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के सामने झुककर, स्वतंत्र संग्राम की गद्दारी कर सकती है, इस आकलन पर पहुंचने में वह विफल रही. साम्राज्यवादियों एवं भारत देश के बड़े पूंजीतिपयों की साजिशों को हरा नहीं पायी. कांग्रेस पार्टी के पूंछ पकड़ कर चलते हुए सार्वजनिक सिद्धांत मार्क्सवाद–लेनिनवाद को भारत देश की क्रांति की ठोस परिस्थितियों से जोड़ने एवं सही रणनीति एवं कार्यनीति अपनाने पर विमुख रही. कामरेड माओ त्सेतुंङ एवं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक अग्रेसर चीनी क्रांति से सीखने, उसके द्वारा अपनायी गयी दीर्घकालीन लोकयुद्ध की लाइन एवं उसके महान अनुभवों को स्वीकार करने के लिए उसने इनकार किया. दरअसल जनता के साम्राज्यवाद विरोधी जुझारू आंदोलन को भटकाने में पूंजीपति वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व योगदान रहा. वह कांग्रेस से अवसरवादी गठजोड़ बनाया, संयुक्त मोर्चा में अपनी स्वतंत्रता को कायम नहीं किया, एकता से सबकुछ हासिल कर सकते हैं, ऐसा सोच कर क्रांतिकारी जनता को गांधीवादी नेतृत्व के पीछे घसीटता गया. अंत में भारत देश के स्वतंत्र संग्राम एवं भारत देश की जनता को गद्दारी की.

दूसरा विश्व युद्ध के समय में और उसके बाद में भी घटित परिणामों से विश्व

में शिक्ति संतुलन में नए बदलाव आए. विशेषकर महान नेता स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ की लालसेना एवं विश्व की जनता द्वारा फासीवादी शक्तियों को पूरी तरह हराया गया. युद्ध के फलस्वरूप साम्राज्यवाद उल्लेखनीय तौर पर कमजोर हुई. पूर्वी यूरोप के देशों में जनता की जनवादी सत्ता का उदय हुआ. कामरेड माओ के नेतृत्व में चीन में क्रांति ने विजय पथ पर आगे बढ़ते हुए विश्वभर में उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं एवं जनता की मुक्ति का मार्ग दिखाया एवं पूरी दुनिया को हिला दिया. विश्व में राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों का उभार आया. ऐसी कठिन स्थिति में साम्राज्यवाद पिछड़े देशों में अपने पुराने प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद को छोड़कर, परोक्ष शासन, शोषण एवं नियंत्रण चलाने के लिए उसके द्वारा चयनित एवं शिक्षित दलालों पर निर्भर होकर, नयी शैली में नयी उपनिवेशवाद को अपनायी.

भारत देश में तेभागा एवं बकाश्त आंदोलन, डाक एवं तार कर्मचारियों की हड़ताल; बंबई में भारत देश के नौ–सेना के सैनिकों की गौरशाली सशस्त्र बगावत, थलसेना एवं वायुसेना में उभरते असंतोष, बिहार का पुलिस विद्रोह; मजदूर वर्ग के बिरादराना संघर्ष; तेलंगाना के ऐतिहासिक सशस्त्र किसान–संघर्ष की शुरूआत आदि ने देश में साम्राज्यवादी शासन को पतन का कगार पर ला खड़ा कर दिया. ऐसी स्थिति में ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत देश की जनता के क्रांतिकारी उभार को नष्ट करने एवं अपने शोषण, नियंत्रण एवं अप्रत्यक्ष शासन को बनाए रखने के लिए अपने वफादार दलालों – कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के नेताओं का इस्तेमाल किया. बड़े दलाल पूंजीपति एवं सामंती वर्गों के साथ सांठगांठ होकर सत्ता हस्तांतरण का नाटक रचा.

इसी का हिस्सा है, 1944 में बनायी गयी बंबई योजना. टाटा, बिड़ला जैसे सामंती एवं दलाल पूंजीवति वर्ग के प्रतिनिधि ही यह योजना बनायी. इस योजना में सामंतवाद को समाप्त करने की योजना नहीं है. कृषि समस्या एवं जमीन समस्या का समाधान निकाल कर, नयी उद्योगों के लिए बाजार उपलब्ध कराने हेतु जनता की क्रयशक्ति बढ़ाने के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया. कम से कम जमीन, उद्योग, बैंक आदि ब्रिटिश संपत्ति का राष्ट्रीयकरण के बारे में भी नहीं बताया गया. इसके बजाय उसने और अधिक विदेश पूंजी को आह्वान किया. वह ब्रिटेन एवं अमेरिका साम्राज्यवादियों की रणनीति एवं भारत देश के बड़े पूंजीपति एवं बड़े सामंती वर्गों के हितों के अनुरूप है. इन समझौतों के मुताबिक भारत देश में महत्वपूर्ण बड़े उद्योगों को नहीं लगाना चाहिए. इसके बजाय ब्रिटेन एवं अमेरिका में तैयार हुए कलपुरजों के असेंब्लिंग यूनिटें स्थापित करना चाहिए. बिड़ला–स्टुडेबेकर, वालचंद–क्रिस्लर, नेशनल रेयान कार्पोरेशन आदि कई

भारत–अमेरिकी देश की व्यापार समझौतें इसी तरह किए गए. भारत देश के दलाल पूंजीपति वर्ग एवं साम्राज्यवादी एकाधिकार संस्थाओं के बीच इस तरह के समझौतें करने के बाद ही 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ. इसने ब्रिटिन के औपचारिक साम्राज्य कई साम्राज्यवादी शक्यिां विभाजित करने का अनौपचारिक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित होने का रास्ता बनाया.

5. दूसरा चरण 15 अगस्त, 1947 से 1991 तकः

दूसरा विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति बनने वाले अमेरिका अपने रणनीतिक आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक आधिपत्य के हितों के अनुसार नयी औपनिवेशिक नीतियां बनायी. युद्ध के दौरान युद्धभार एवं संकट के कारण ब्रिटेन के साथ अन्य यूरोप देशों के मुद्राओं का अवमूल्यन हुआ. इस परिप्रेक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय तौर पर वित्तीय नियंत्रण के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका एवं ब्रिटेन की साम्राज्यवादी सरकारें 44 देश के प्रतिनिधियों के साथ ब्रिटेन ऊड्स में एक अधिवेशन आयोजित कर एक समझौता किया. तत्कालीन कठिन स्थिति से उबरने के लिए डालर मूल्य के साथ विभिन्न देशों के मुद्राओं की मूल्य को जोड़ने की अमेरिकी शर्त पर प्रतिनिधियों ने अपनी सहमति जतायी. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कोष (आईएमएफ) एवं विश्व बैंक की स्थापना की गयी. अमेरिकी नयी औपनिवेशिक नीतियों का लक्ष्य है अमेरिकी डालर के आधार पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को गठित करना. ब्रिटेन ऊड्स समझौता के जरिए वह अपना लक्ष्य हासिल किया. कपटतापूर्ण कागजी डालरों से वास्तविक वस्तुओं, संसाधनों एवं श्रम का विनिमय करना अंतरराष्ट्रीय नीति बन गयी. नयी उपनिवेशिकवाद के अनुसार साम्राज्यवादी पूंजी एवं अर्ध–औपनिवेशिक–अर्ध–सामंती देशों के बड़े दलाल नौकरशाह पूंजी के बीच शोषण एवं उत्पीड़न के आपसी आधारित संबंध मजबूत करने में साम्राज्यवादी सरकारों के साथ आईएमएफ एवं विश्व बैंक प्रमुख भूमिका निभाई. अमेरिकी डालर का प्रभुत्व रुणग्रस्त देशों की संपदा रुणदाता देशों में स्थानांतरित करने के लिए रास्ता बनाया. यानी गरबी देशों को धनी देश मनमानी तरीके से लूटने का अवसर दिलाया. यह पूरी तरह असमान एवं अन्यायपूर्ण संबंध है.

इसके अनुसार, भारत देश की अर्थव्यवस्था को विश्व पूंजीवादी–साम्राज्यवादी हितों के अधीन/अनुरूप तब्दील करने के लक्ष्य से किए गए समझौतों के तहत ही हुआ था 15 अगस्त, 1947 का सत्ता हस्तांतरण. दलाली कांग्रेस सरकार द्वारा अपनायी गयी मिश्रम आर्थिक नीति अप्रत्यक्ष रूप से कई साम्राज्यवादी शक्तियों का आधिपत्य सुस्थिर बनाते हुए, देश को अर्ध–औपनिवेशिक एवं अर्ध–सामंती व्यवस्था बना दी. सत्ता हस्तांतरण के साथ सत्तारूढ़ दलाल पूंजीपतियों की पूंजी

राज्य पूंजी से मेलमिलाप हुई और भारत देश के बड़े पूंजीपति वर्ग दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग (comprador bureaucratic bourgeoisie-CBB) के रूप में तब्दील हो गया. देश में दलाल नौकरशाह पूंजीपति एवं सामंती वर्गों के राज्य इजारेदार पूंजीवाद अमल में आया. यही है भारत देश के प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों की आर्थिक बुनियाद. विभिन्न देशों की साम्राज्यवादी शक्तियां भारत देश पर अपने शोषण एवं नियंत्रण चलाने के लिए इन दलाल नौकरशाह पूंजीपति एवं बड़े सामंती वर्गों को अपने मुख्य सामाजिक आधार बनाया. इसलिए ये दलाल नौकरशाह पूंजीपति एवं सामंती वर्ग साम्राज्यवाद के बगैर स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं कर सकते. साम्राज्यवाद एवं दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग द्वारा जिस पूंजीवाद का विकास किया गया है, वह स्वाधीन राष्ट्रीय पूंजीवाद नहीं, बल्कि दलाल नौकरशाह पूंजीवाद है, जो साम्राज्यवाद एवं सामंतवाद के साथ बंधा हुआ है.

भारत देश के राज्य का वर्ग–चरित्रः लेनिन ने बताया कि ''राज्य एक वर्ग दूसरे वर्ग को कुचलने के लिए होने वाले तंत्र है'' (संकलित रचनाएं, ग्रंथ 29, पृष्ठ 380), ''अत्यंत जनवादी पूंजीवादी गणतंत्र भी, पीड़तों को कुचलने के लिए पूंजी के तंत्र के बजाय, पूंजी के राजनीतिक शासन के साधन एवं पूंजीपति वर्ग के तनाशाह के साधन के बजाय और कुछ नहीं हो सकता और नहीं होगा'' (चयनित रचनाएं, ग्रंथ 10, पृष्ठ 35–36). इसी तरह 'गणतंत्र' एवं 'संसदीय जनवाद' के नाम से प्रचारित होने वाला भारत देश नया उपनिवेश स्वरूप के परोक्ष शासन, शोषण और नियंत्रण के मातहत, मुट्ठीभर दलाल नौकरशाह पूंजीपति एवं सामंती शासक वर्गों द्वारा देश की जनता की विशाल बहुसंख्या पर लागू किए जाने वाले अर्ध–औपनिवेशिक एवं अर्ध–सामंती राज्य के साझा तानाशाह के अलावा और कुछ नहीं है. सशस्त्र बल इस राज्यतंत्र का प्रधान अंग है. उनके वर्गीय शासन, वर्गीय शोषण तथा वर्गीय उत्पीड़न का औजार है. उत्पीड़ित जनता के शोषण, उत्पीड़न एवं दमन को सुगम बनाने वाली वैचारिक एवं सामाजिक व्यवस्था के तौर पर जाति व्यवस्था भारत देश के राज्य के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ी हुई है. ब्राह्मणवादी विचारधारा से लैस भारत देश के राज्य मात्र 10 प्रतिशत के अल्पमंत वाले दलाल शोषक वर्गों–आधिपत्य पीड़क जातियों के लिए अनुकूल है और 90 प्रतिशत के बहुमत वाले उत्पीड़ित वर्गों एवं उत्पीड़ित सामाजिक तबकों एवं उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं की जनता के खिलाफ है. उसने भारत देश के राज्य 27 प्रतिशत होने वाले दलितों को छूआछत प्रथा से कुचल रहा है. प्रतिक्रियावादी 'राष्ट्रीय एकता' एवं राष्ट्रीयताओं का दमन के लिए, महिलाओं के प्रति पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर, विशेषकर मुस्लिमों पर, दलितों एवं आदिवासियों पर आधिपत्य के लिए और

विद्वेष एवं भेदभाव के लिए ब्राह्मणवादी भारत देश का राज्य ही आधार है. उसने उत्पीड़ित जनता से अधिशेष को हड़प कर साम्राज्यवादियों, दलाल नौकरशाह पूंजीपति एवं सामंती वर्गों के बीच बंटवारा करता है. इसके लिए पारंपरिक रूप से प्राप्त हथियार के रूप में जातिप्रथा उन्हें मदद करती है. वे देश के संसाधनों को लगातार बेरोकटोक लूटने का मार्ग सुगम बनाता है. अधिशेष के बंटवारे में उनके बीच अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाले अंतरविरोधों को भी हल करने के एक उपकरण के रूप में काम करता है.

इस तरह के भारत देश के राज्य के बल के समर्थन एवं प्रोत्साहन से ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा निर्मित सड़क, रेलवे, हवाई आड्डों, बंदरगाहों आदि बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्थाओं, खदान एवं उद्योगों को इस्तेमाल कर भारत देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग क्रमशः मजबूत हो गया. यह बुनियाद विश्व के अत्यधिक पिछड़े देशों के दलाल पूंजीपति वर्ग से भी मजबूती से विकसित होने में उसे योगदान दिया. वह बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष पूंजी एवं रुण पूंजी को आयात करने में साम्राज्यवादियों के लिए बुनियादी तौर पर स्थानीय बिचौली बन गए. उसने देश को विभिन्न साम्राज्यवादी देशों के इजारेदार संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले शोषित क्षेत्र रूप में तब्दील कर दिया. इसी तरह साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच अंतरविरोधों को इस्तेमाल करते हुए अपने हितों का भी पूरा कर रहा है.

सत्ता हस्तांतरण के बाद टाटा ग्रुप ने स्टील, आटोमोबाइल्स, पॉवर, टेलिकॉम, रसायन, इंजीनीरिंग, चाय, घड़ी, होटल क्षेत्रों में निवेश कर नंबर एक कंगलोमरेट बन गए. गोद्रेज एवं वाडिया ग्रुप अपने उद्योगों को विस्तारित किए. पारसीयों की आबादी कम होने एवं उनके औद्योगिक कार्यकाप नहीं विस्तारित होने के कारण कुछ पुराने एवं नए उद्योगपतियों का महत्व काम हो गया. इसी तरह भाटिया ग्रुप के ताकत एवं क्षमता भी कम हो गयी. लोहाना ग्रुप खाद्य पदार्थों के व्यापार में मजबूत बुनियाद होने के बावजूद विदेश व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं ले पाया. चेट्टियार एक जमाने में मारवाड़ियों से बराबर होने के बावजूद दक्षिण–पूर्व एशिया में उनकी पूंजी धक्का खा जाने की वजह से मात्र कुछ चेट्टियार संस्थाएं ही बच पायी.

मारवाड़ी, गुजराती बनिया/जैन एवं सिंधी ग्रुप अत्यंत मजबूत शक्तियों के रूप में बन पाए. मारवाड़ी एवं गैर–गुजराती बनिया के बारे में बात किया जाए, बिड़ला, टाटा ग्रुपों के बाद विकोस ग्रुप ताकतवर बन गए. उसने फाइबर, अल्युमिनियम, तांबा, सिमेंट, कार्बन ब्लाक, इन्सुलेटर, रेडीमेड कपड़ा, रसायन उर्वरक, वस्त्र, टायर, टेलिकॉम, बीमा, पाम आयल रिफायनरी, लकड़ी का गूदा (pulp), चीनी, मीडिया, रेल वागन तैयारी, कार, आटोमोबाइल्स, पेपर, आसबेस्टास शीट, भवन निर्माण के

अन्य सामग्री एवं केबल क्षेत्रों में देश में ही नहीं, विभिन्न देशों में भी विशाल दलाल कार्पोरेट साम्राज्य के रूप में विकसित हुए. बाकी प्रमुख पूराने व्यापारी परिवार – श्रीराम, सिंघानिया, गोयंका, बजाज, बंगुर, मोदी एवं दाल्मिया ग्रुप के दलाल कार्पोरेट कंपनियां विभाजित हो गए. विभाजित होनी वाली कंपनियों में से कुछ कंपनियां फिर से पूर्ण स्तर संभाल कर चलता रहा. जूट क्षेत्र में चौथी स्थान में होने वाली बंगुर ग्रुप अन्य क्षेत्रों में भी कार्यरत है. कुछ कंपनियों को छोड़कर बाकी कंपनियां क्रमशः धक्का खा लिया.

गुजराती बनिया/जैन ग्रुपों में साराभाई ग्रुप चली गयी. सिर्फ लालभाई ग्रुप चलता रहा. इन सभी कंपनियों से आगे चल कर बड़े कंगलोमरेटों के रूप में रिलयेंस, टोरेंट एवं अडानी ग्रुप आगे आयीं. रिलयेंस अंबानी ग्रुप ने वस्त्र, तेल रिफायनरी, तेज–प्राकृतिक गेस उत्पादन, अनुसंधान, पेट्रो रसायन, पॉवर, टेलि कम्युनिकेशन्स क्षेत्रों में बड़ी दलाल कार्पोरेट संस्था बन गयी. टोरंट कंपनी फार्मास्युटिकल्स एवं पॉवर क्षेत्रों में विकसित हुई. अडानी ग्रुप वस्त्र व्यापार, कृषि उत्पादन, खाद्य तेल, कोयला, रसायन उर्वरक, स्टील रद्दी, पेट्रो रसायनों का व्यापार में बड़े व्यापारी ग्रुप के रूप में और मुंद्रा बंदरगाह के मुखिया के रूप में आगे आयी. गुजराती जैन ग्रुप हीरा प्रोसेसिंग व्यापार में विश्व स्तर के एकाधिकार ग्रुप है. इस तरह और कुछ लोग विभिन्न क्षेत्रों में दलाल नौकरशाह उद्योगपतियों के रूप में विकसित हुए.

सिंधियों में हिंदूजा ग्रुप गैर–आवासीय भारतीयों (NRI) के तौर पर लंडन में स्थायी निवास बनाकर खरबपति (billionaire) बन गयी. और कुछ सिंधियों ने विदेशों में उद्योगपतियों के रूप में थे, जबकि देश में कई सिंधियों ने नए उद्योगपतियों के रूप में आगे आए. मारवाड़ियों में, हिंदी प्रांतों में अन्य बनिया व्यापारियों में, गुजराती बनिया/जैन व्यापारी एवं कुछ सिधियों में ऐसा विशिष्ट लक्षण है कि कुछ व्यापारी धक्का खाने, कुछ परिवार अलग होकर उनके उद्योग भी विभाजित होने के बावजूद, फिर से एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी अपनी संस्थाओं को पुनरजीवित करना एवं कई नयी संस्थाओं को स्थापित करना. पारसी एवं चेट्टियारों में यह लक्षण उतना नहीं दिखता. सत्ता हस्तांतरण के बाद 1960 एवं 1970 के दशकों में कई गैर–गुजराती/मारवाड़ी उद्योग विकसित हुए. इसमें जिंदल, रुइया, दूत, शाहरा, सेकसारिया एवं नियोटिया ग्रुप उल्लेखनीय है. इनके अलावा अन्सल, बन्सल, बिंदल, बजोरिया, भोरुका, भुवाल्का, धनुका, गर्ग, हिमटसिंगका, जजोड़िया, जलन, जयपुरी, काबरा, कजरिया, केदिया, खैतान, खेमका, महेश्वरी, मनकसिया, मोहनाट, मोरारका, परशरामपुरिया, पटोडी, पित्ति,

पोद्दार, रंका, गुंगटा, संगनेरिया, सिंधी, सेथिया, सोमनी, सूरना एवं टायल ग्रुप देश के विभिन्न नए केंद्रों में विकसित हुईं.

भारत देश के व्यापारी आधुनिक भाषा बोलता है, लेकिन उसके सोच एवं व्यवहार में मध्ययुगीन के सोच होते हैं. वह ऐसा नहीं सोच सकता कि अपने द्वारा स्थापित व्यापार को अपने वारिश के बजाय अन्य लोग उसे संभाल कर विकसित कर सकते हैं. भारत देश के बड़े पूंजीपति वर्ग का दृष्टिकोण ब्राह्मणवाद से भारा रहता है. इसिलए वे हिंदुस्तान को एक हिंदूराष्ट्र के रूप में एवं हिंदू धर्म को सरकारी धर्म के रूप में मान्यता देना चाहते हैं.

1980 में देश के 11 व्यापार परिवार उद्योग क्षेत्र को नियंत्रित कर रहे हैं. फिर भी उसमें स्वयं उनकी पूंजी सिर्फ रु. 148 करोड़ थे. सरकारी आर्थिक संस्थाएं रु. 27,000 करोड़ पूंजी लगायी थी. उन 11 परिवारों द्वारा उस पूंजी से आए आर्थिक मुनाफें में एक बड़ा हिस्सा स्वयं अपने हितों के लिए और रु. 25,000 करोड़ कालेधन को विदेशी बैंकों में छिपा दिया. भारत देश के बनिया व्यापारियों में तकनीकी आविष्कारों के प्रति अभिरुचि हो एवं उत्पादन के क्रम में उत्साह हो, नहीं होने का प्रमाण यही है.

साम्राज्यवाद के साथ सांठगांठ होने वाले भारत देश के बड़े दलाल पूंजीपति वर्ग को देश के उद्योग क्षेत्र पर एकाधिकार होने के अलावा हजारों एकड़ स्वयं अपने कब्जे में लेकर जमींदारी वर्ग के रूप में हैं. उनमें से कई लोग सूदखोर भी हैं. इस कारण से यह वर्ग हमेशा बुनियादी जमीन सुधारों एवं उनके अमल को विरोध करता आया है. इसीलिए दलाली सरकारें जमीन सीलबंदी कानूनों को ठीक से अमल नहीं किया. इसके अलावा आय के बढ़ती असमानाएं, व्यापक गरीबी एवं कृषि क्षेत्र का पतन के कारण तैयारी क्षेत्र के उपभोक्ता वस्तुओं का बाजार मुख्य रूप से भारत देश के अर्ध–औपनिवेशिक एवं अर्ध–सामंती समाज में मात्र उच्च वर्गों तक ही सीमित हो गया.

बंबई योजना के अनुसार पंचवर्षीय योजनाओं के नाम पर, 1948–55 के बीच केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों के वार्षिक बजटों के तहत भारत देश में मुख्य रूप से अमेरिका आदि साम्राज्यवादी एकाधिकार संस्थाओं के आधिपत्य में होने वाले आईएमएफ एवं विश्व बैंक ने निवेश किया. केंद्र सरकार ने घोषणा की कि इस निवेश का लक्ष्य है कृषि क्षेत्र को बेहतर करना, उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मानदंड बढ़ाना, खनिज विकास, बांधों, बिजली परिलयोनाओं, जनता के लिए जरूरी सुविधाओं, सड़कों आदि का निर्माण के लिए बुनियादी स्तर पर आर्थिक स्त्रोत

उपलब्ध कराना. उस समय साम्राज्यवादियों की केनीसियनवादी नीतियों पर आधारित होकर वार्षिक बजटों में बड़े पैमाने पर घाटा वित्तपोषण किया गया था. कार्पोरेट कर में रियायत देने, बड़े पैमाने पर रुण उपलब्ध कराने, बट्टे खातों की माफी, सस्ते में प्राकृतिक संसाधनों को हवाला करने की वजह से साम्राज्यवादी एवं दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के कार्पोरेट उद्योगों ने हजारों करोड़ रुपयों के जनधन को लूट लिए. 1951 के औद्योगिक नियंत्रण कानून के अनुसार इस्पात, माइनिंग, पूंजी वस्तु (capital goods), जैसे विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उद्योगों एवं पानी, परिवहन, कम्युनिकेशन, बीमा, बिजली जैसे बुनियादी सुविधाओं को विकास करने का लक्ष्य देश का औद्योगिकीकरण करना नहीं था, बल्कि साम्राज्यवादी एवं दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों की कार्पोरेट कंपनियों को तमाम किस्म के सुविधाएं उपलब्ध कराना था. कुछ हद तक औद्योगिकीकरण करने के बावजूद वह मात्र अर्ध–सामंती बुनियाद पर ही, साम्राज्यवादियों एवं दलाल शासक वर्गों के हितों के लिए ही होने की वजह से वह पूरा विकास विक्रीकृत हुआ एवं उल्टा रूप ले लिया. रुण पर आधारित इस विकास नीति देश को पराधीन बना दिया. इस तरह साम्राज्यवादी विकास नमूने पर निर्भरता देशीय उद्योगों का विकास के लिए अवरोध बन गया. फलस्वरूप कृषि क्षेत्र पर अतिरिक्त श्रमशक्ति भार अधिक हो गया एवं अतिरिक्त ग्रामीण गरीबों को पैदा किया. इससे बजार और अधिक सिमट गया.

राजाओं एवं सामंतियों ने अधिशेष को हड़पने के लिए अमल करते आ रहे पुरानी जातिगत सामंती शोषणमूलक तरीकें सत्ता हस्तांतरण के बाद क्रमशः परिवर्तित होते गए. दलाल नौकरशाह पूंजी का उद्भव के साथ, वह सीधा उद्योगों, रेलवे एवं बागानों की स्थापना में पत्यक्ष रूप से शामिल हो गयी. तमाम दलाली शोषण–शासक वर्ग की पार्टियों, संशोधनवादी व नयी संशोधनवादी पार्टियों ने बंधुवा मजदूरी पर आधारित बागान अर्थव्यवस्था को समूचा देश में निर्लज्जता से प्रोत्साहन देने में सक्रिय भूमिका निभाई. विश्व बैंक के आदेशों को लेकर केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले रबड़ बोर्ड द्वारा रबड़ पर जोर दिया गया. ग्रामीण इलाकों में ठेकेदरों, शराब माफिया, खदान माफिया, रियल एस्टेट माफिया आदि के उद्भव के साथ दलाली पूंजी के साथ जुड़े हुए नयी सामंतवादी वर्ग आकार लेना शुरू हो गया. इस तरह के बदलावों के जरिए जातिगत सामंतवाद साम्राज्यवाद के लिए और अधिक मजबूत सामाजिक बुनियाद बन गया. दलाल नौकरशाह पूंजीवाद में और अधिक विकास हुआ.

1958 में सरकारी भुगतान संतुलन (balance of payments) पतन होने की वजह से अमेरिका साम्राज्यवाद आगे आया. दलाली शासक वर्ग अमेरिका का पक्ष

ले लिया. अमेरिकी निवेश तेजी से बढ़ गए. 1957–61 के बीच भारत देश के दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग के नए निवेश के रूप में, उनके साथ सांठगांठों (collaborations) के रूप में एफडीआई आयी. इस तरह साल दर साल ये सांठगांठ बढ़ते गए. सरकार की घाटा बजट नीति के कारण वाणिज्यक घाटा बढ़ता गया. फलतः आईएमएफ से लिए कर्ज बढ़ाता गया. 1962 में चीन के साथ युद्ध, गंभीर अकाल, घाटे बजटों (deficit budjeting), मुद्रस्फीति में व्यापक वृद्धि की वजह से भारत देश की सरकार आईएमएफ एवं विश्व बैंक से बड़े पैमाने पर कर्ज लिए. उनके द्वारा लगायी शर्तों से सहमति जताने के कारण ही 1947 में एक डालर के लिए एक रुपया होने वाली रुपये की मूल्य, पहली बार जून 1966 में एक डालर के लिए 7.5 रुपए तक घटाया गया. हमारा देश के निर्यात सस्ते हो गए.

सोवियात संघ में पूंजीवादी वापसी होकर 1969 में वह सामजिक–साम्राज्यवादी देश बनने के बाद 1970 के दशक में पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों के निवेश एवं 'सेवियत संघ' की सामाजिक–साम्राज्यवादी निवेश के बीच भारत देश की अर्थव्यवस्था पर आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा चली. 1970 के दशक की शुरूआत में किए गए 'सोवियत' रूस एवं भारत देश के रणनीतिक रक्षा समझौते के जरिए भारत देश के शासक वर्ग ने अमेरिकी महाशक्ति से 'सोवियत' रूसी महाशक्ति का पक्ष लिया. मात्रा में नहीं होने के बावजूद नियंत्रण करने में 'सोवियत संघ' मजबूत स्थिति हासिल कर ली. पश्चिमी देशों के साथ सौदेबाजी करने में भारत देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग के लिए अधिक अवसर मिला.

585 संस्थानों (princly states) के राजाओं को वर्ष में रु. 5 करोड़ के हिसाब से भुगतान करने वाली रकम (privy purse) के कारण जीडीपी में एक बड़ा हिस्सा खर्च होता था. इससे अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर होता था. इस भुगतान पर रोक लगाने की वजह से सामंती वर्ग ने पहले हमला का शिकार हुआ. उसके बाद बैंकों, कोयला, तेल, भारी उद्योगों जैसे क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया गया. इससे शासक वर्गों में अलग–अलग गुटों के बीच संघर्ष तेज हो गया. उस समय ग्रामीण जनता में व्याप्त गंभीर असंतोष एवं 1967 के नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान बगावत इसमें मुख्य भूमिका निभाई. राजाओं के भरण–पोषण की समाप्ती एवं बैंकों की राष्ट्रीयकरण के साथ बड़े सामंती एवं दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्गों के गठजोड़ में दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग ने नेतृत्व की भूमिका में आना शुरू हो गया. सरकारी क्षेत्र की व्यापकता बढ़ी. राजकोष से और अधिक राशी आवंटित की गयी. सरकारी क्षेत्र व्यापार में उतर गया. बैंकों, बीमा, तेल, कोयला, भारी उद्योगों जैसे

क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण, औद्योगिक क्षेत्र का पुनर्गठन, वस्त्रों से लेकर होटलों तक तमाम उत्पादन क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र का प्रवेश के करण राजकोष से (यानी जनता पर परोक्ष कर लगाने से आनेवाली राशी) आने वाली राशी से भारी रकम जमा होने लगे. दलाली इजारेदार पूंजी का सरकारी पूंजी के साथ मेलमिलाप एवं सामंतियों से सांठगांठ होने वाली एवं साम्राज्यवाद की आज्ञाकारी दलाल नौकरशाह पूंजी और विकसित हुई. सरकारी क्षेत्र एवं राज्यतंत्र के अलावा दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग की असाधारण तौर पर तेजी वृद्धि दर्ज की.

साम्राज्यवादियों, दलाल नौकरशाह पूंजीपति एवं सामंतीयों के शोषण एवं उत्पीड़नों से 1960 के दशक के अंत में आर्थिक एवं राजनीतिक संकट, इसके बाद 1974 में और एक संकट देश को हिला किया और राजनीतिक वातावरण को अस्थिर बना दिया. दूसरी तरफ नक्सलबाड़ी के सशस्त्र किसान बगावत के बाद महाराष्ट्र में दलित पांथर, गुजरात में नवनिर्माण, बिहार में जयप्रकाश नारायण (जेपी) के आंदोलन हुए. 26 जून, 1975 को आपात्काल लागू किया गया. दलाल नौकरशाह पूंजीवादी वर्ग को यह वरदान साबित हुआ. उदाहरण के लिए, 1966–67 में बिड़ला ग्रप के पास रु. 447 करोड़ों की संपत्ति, टाटा ग्रुप के पास रु. 521 करोड़ों की संपत्ति थी. 1975–76 तक बिड़ला ग्रुप की संपत्ति रु. 1,085 करोड़ों तक एवं टाटा ग्रुप की संपत्ति रु. 975 करोड़ों तक बढ़ोत्तरी हुई. इस तरह यह वर्ग शासक वर्गों के गठजोड़ में अपनी आधिपत्य स्थान को सामंती वर्गों से तुलना करने से और मजबूत किया. इस वृद्धि के कारण अधिकारियों (bureaucrats) में उच्चश्रेणी के एक छोटी तबका और शासक वर्ग में शक्तिशाली राजनेताओं ने करोड़ो रुपये आर्जित किए. दूसरी तरफ वे विभिन्न तरीकों में सरकारी पैसे निगल कर अतिरिक्त और कुछ करोड़ हड़प लिए. ये पराश्रयी तबकें दलाल नौकरशाह पूंजीवादी वर्ग का ही हिस्सा है. दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग एवं साम्राज्यवाद के लिए प्रत्यक्ष रूप से दासता करने वाले एवं साम्राज्यवाद द्वारा भारत देश की जनता पर किए जाने वाले शोषण को जायज ठहराते हुए उसका गुनगान करने वाले (बुद्धिजीवियों एवं उच्च स्तर के प्रोफेशनल्स) भी इसी वर्ग का हिस्सा है.

1960 के दशक के बीच हरित क्रांति के समय से ही दलाली सरकारों ने नौकरशाह पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद के जरूरतों को अनुसार कृषि क्षेत्र को तब्दील करना शुरू किया. बदली हुई परिस्थितियों में सामंतवादी राजाओं ने अतीत की तरह अपने शोषण एवं आधिपत्य को चला नहीं पाए. ऐसी स्थिति में अत्यधिक शोषण एवं ग्रामीण आधिपत्य एवं नियंत्रण चालने के लिए व्यापारों एवं अन्य आर्थिक संसाधनों में अवसर प्रदान कर सामंती शक्तियों को बरकरार रखा गया. उदाहरण

के लिए, सहकारी चीनी मिलें एक तरफ संपत्ति एवं उत्पादन तकनीकों के मामले में आधुनिक रहते हैं, दूसरी तरफ शोषण के स्वरूप अत्यंत पुराने वाली प्रतिक्रियावादी तरीकों पर निर्भर रहते हैं. इस वर्ग के ऐसे द्वंद्व चरित्र की वजह से यानी शोषण के स्वरूप में बदलाव है (वेतन श्रम), नए स्वरूपों में (सहकारी संगठन आदि) उत्पादन कर रहे हैं, पूंजीवादी उत्पादन के साधन (बोरिंग नल विभिन्न कृषि उपकरण, ट्राक्टर, थ्रेशर, हारवेस्टर), रसायन उर्वरक, कीटनाशक एवं तकनीक विस्तारित हुए, फिर भी ये नए कृषि संबंध सामंतवाद का उन्मूलन या उत्पादक शक्तियों की मुक्ति का रास्ता नहीं बनाया. बाजार उपलब्ध कराना, बजट आवंट, तमाम नए कृषि संबंधों एवं व्यापार पेकेजों पर आधारित होकर अमल हो होने लगे. ये मात्र साम्राज्यवादियों एवं सीबीबी के हितों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके अनुसार नयी ग्रामीण सामंती शक्तियों को विकसित कर, उनके हितों के लिए भी योगदान दिया.

भारत देश में उत्पादक पूंजी से अनुत्पादक पूंजी बहुत अधिक है. यंत्र, यंत्र उपकरण, गैर–लोहे के धातु, विद्युत, इंजनीरिंग, मोटार वाहन – ट्रेक्टर, प्राइम मूवर (शक्तिशाली ट्रक), भारी रसायन आदि बुनियादी उद्योग यहां अस्तित्व में नहीं है या प्रारंभिक चरण में हैं. इसीलिए 1975 में भारत देश की सरकार ने ऐसा ऐलान किया कि ''भारत देश अभी भी मुख्य रूप से ग्रामीण एवं छोटे किस्म के उद्योग वाला देश है''. इस तरह के उत्पादन प्रणाली को दिखाते हुए भारत देश के दलाली शासक वर्ग देश में तेजी से पूंजीवादी विकास होने का ढिंढोरा पीटते हैं. दरअसल यह साम्राज्यवादी नयी उपनिवेशवादी शोषण के तहत मात्र अर्ध–औपनिवेशिक आर्थिक प्रणाली है, स्वतंत्र पूंजीवादी प्रणाली नहीं है. इसमें विदेशी निजी पूंजी, विदेशी रुण पूंजी, भारत देश के दलाली पूंजी एवं सरकारी पूंजी नामक चार किस्म की पूंजी अभूतपूर्व ढंग से लपेट हुई हैं और भारत देश के किसी भी बड़े उद्योग में ये आपस में मिली हुई हैं.

1970 के दशक से अमेरिका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी देश नयी उदारवादी नीतियों के नाम पर मनमानी शोषण की नीतियों को लाकर पिछड़े देशों पर थोपने की वजह से हमारी देश की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण (ढांचागत बदलाव करना) शुरू हुआ. बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वस्तुओं से देश के बाजार भरे पड़े. निजी व्यापार को लाभदायक बदलने के लिए साम्राज्यवादी कार्पोरेट कंपनियों एवं देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के कार्पोरेट कंपनियों को सरकार ने रियायतें एलान किया. रोजगार उद्योगों में संगठित क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र से कृषि अनुषंगी क्षेत्रों में बदलता गया. उद्योगों का बंद होना बढ़ा है. फलतः औद्योगिक

एवं कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ी है. उद्योगों, सेवा क्षेत्र, व्यापार, साम्राज्यवादी निवेश, तकनीकी ज्ञान का हस्तांतरण, राजस्व, एकाधिकार कीमतें, बौद्धिक प्रवासन, और कई अन्य मार्गों के जरिए भारत देश से साम्राज्यवादी देशों में अपार संपदाएं ले जाया जा रही हैं. इसी वजह से भारत देश की अर्थव्यवस्था पूर्वी एवं दक्षिण–पूर्वी एशिया से और पड़ोसी दशों से भी पिछड़ गयी.

अगस्त 1990 में खायी युद्ध के समय में तेल का दाम आसमान छूया; वित्तीय घाटा और अधिक हो गया; मुद्रास्फीति बेरोकटोक बढ़ती गयी. विदेशी रुण रु. 1,32,000 करोड़ो तक पहुंच गया. अगर आपात्कालीन राशी जुटा नहीं पातें, तो भुगतान संतुलन (रुणों का भुगतान) में संकट ढाह जाने की स्थिति पैदा हुई. इस संकट से उबरने के लिए, दलाली शासकों ने 67 टन सोना को अप्रैल, 1991 में अत्यंत गुप्त रूप से लंडन ले गए, आईएमएफ की शर्तों पर उसे गिरवी लगाए. इससे 1991 तक रुपया और पतन हो गया, एक डालर के लिए 24.58 रु. हो गया और रु. 1,40,000 करोड़ों का विदेशी रुण एकाएक रु. 2,10,000 करोड़ तक पहुंच गया. देश रुणों का दलदल में फंस गया. मुद्रास्फीति एवं बेरोजगार और अधिक हो गए. मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग, राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग पर, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे उत्पीड़ित तबकों पर, कश्मीर एवं उत्तर–पूर्व भारत देश की राष्ट्रीयताओं पर साम्राज्यवादियों एवं दलाल सरकारों के शोषण, उत्पीड़न, दमन एवं भेदभाव तीव्र रूप ले लिया.

जब 1970 के दशक के अंत एवं 1980 दशक की शुरूआत में उत्पीड़ित जनता में तीव्र असंतोष की स्थिति व्याप्त थी, इसी को इस्तेमाल कर विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां उभर कर आयी और शक्तिशाली बन गयी. यह भारत देश के दलाल शासक वर्गों के 'महात्वकांक्षी हिंदुत्व' एवं 'अखिल भारतीय बाजार' निर्माण के लिए बड़ा झटका है. इन नयी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों में अत्यधिक पार्टियां पीड़क जाति की नयी सामंती एवं धनी किसान तबकों एवं विभिन्न राज्यों में नए तौर पर विकसित हो रहे दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों द्वारा बनायी गयी. ये क्षेत्रीय और अन्य राष्ट्रीय अस्तित्वों में भी जातिगत संबंधों से लपेट कर रहना एक वास्तविक विषय है. इस तरह नए तौर पर उद्‌भव होने वाले क्षेत्रीय दलाल पूंजीपति वर्ग अपनी ठोस वृद्धि के चरण में इस अवधारणा से कि अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को इस्तेमाल करना, क्षेत्रीय राजनीतिक संस्थाओं में निवेश करना फायदामंद होगा, इसके लिए योजनाएं बनाकर अमल किया. तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेट्र कजगम (डीएमके), अन्ना द्रविड़ मुन्नेट्र कजगम (अन्ना डीएमके), आंध्रप्रदेश में तेलुगु देशम (टीडीपी), पंजाब में अकाली दल, कर्नाटक में जनता दल, ओडिशा में

बीजेडी, आखिर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कांग्रेस, पंश्चिम बंग में तृण मूल कांग्रेस (टीएमसी), आंध्रप्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस आदि क्षेत्रीय पार्टियां एवं गुजरात में कांग्रेस भी इस रुझान का ही व्यक्तीकरण है. इसी तरह पिछड़ी कृषि–प्रधान जातियों से उबरी एक छोटी तबका ने क्षेत्रीय दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग के रूप में विकसित हुआ. इसका प्रतिनिधित्व करने वाली समाजवादी पार्टी (एसपी), जनता दल (यू) (बिहार) आदि बनकर विकसित हुईं. इनमें से कई पार्टियों का विकास विभिन्न राज्य सरकारों की सत्ता दुरुपयोग करने द्वारा हुआ. इन्ही सरकारों से मिलने वाले कांट्रैक्टों एवं बिनामी राशी पर वे निभर्र हैं. अपने अस्तित्व एवं वृद्धि के लिए सिनेमा क्षेत्र या विभिन्न किस्म के माफिया, अन्य व्यापारों, विभिन्न राज्यों से नए तौर पर विकसित हो रहे दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों से पूंजी का संचयन किया. संसद में बहुमत हासिल करने के लिए होने वाली शक्ति परीक्षण में वे सौदेबाजी करने लगे और अपनी हिस्सा हासिल करने लगे. 1990 के दशक के बीच, उनमें से कुछ लोग और आगे बढ़ा. उदाहरण के लिए टीडीपी चंद्रबाबु नायुडू, बीजेडी नवीन पट्नायक आदि.

6. तीसरा चरण 1991 से 2024 तकः

यही है वैश्वीकरण का चरण. इस चरण में केनीसियन सिद्धांत का कोई मतलब ही नहीं रह गयी. इसके स्थान पर चिकागो स्कूल में बनाया गया नया उदारवादी सिद्धांत के रूप में प्रचारित मिल्टन फ्रीडमैन के वित्तीयवादी (moniterist) सिद्धांत को सामने लाया गया. इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन एवं ब्रिटेन प्रधान मंत्री थाचर सिकंदर के रूप में आगे आए. वित्तीय पूंजी को आसानी से एक प्रांत से दूसरे प्रांत में ले जाने के लिए 1980 के दशक में ही कई किस्म के रुकावटें हटाना शुरू हुआ था. एशिया, अफ्रीका एवं लातीन अमेरिका बाजारों में विदेशी पूंजी, विशेषकर वित्तीय पूंजी की बाढ़ आयी. इसी वजह से 1991 के बाद पिछड़े देशों में ज्वाइंट वेंचरों में (संयुक्त उद्यम) और तेजी आयी. 'सोवियत' महाशक्ति का पतन के बाद अमेरिका महाशक्ति के साथ भारत देश के संबंध और मजबूत हुए. भारत देश को भी नयी उदारवादी नीतियों के फंदे में फंसाया गया. अविनियमन (डीरेगुलेशन), बेलाइसेंस नीति (डीलाइसेंसिंग), विनिवेशीकरण (डिजिन्वेस्टमेंट), विऔद्योगिकीकरण (डीइंडस्ट्रियलाइजेशन) – (डी4) संकेत शब्द बन गए. समाज में समस्त अव्यवस्थाओं के लिए मूल कारण के रूप में नेहरू वाली समाजवाद को ही ठहराया गया. हर व्यक्ति नया उदारवादी सुधारों के बारे में कहने लगे. 'सेवियत संघ' का पतन से राष्ट्रीय हित के संरक्षण से संबंधित किसी भी छोटे विषय को पिछड़े, पुराने एवं छोड़ दिए जाने वाले विषय के रूप में सोचने लगे. कार्पोरेट मीडिया में उल्लेखनीय

तबका इसमें निपुणता हासिल की. इस चरण में साम्राज्यवादी विश्वभर के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं में ढांचागत बदलाव किए. ये नयी उदारवादी नीतियां दरअसल साम्राज्यवावादी वैश्वीकरण नीतियों के अलावा और कुछ नहीं हैं.

1970 के दशक की शुरूआत में फूट पड़े संकट से सामने आए ''स्टागफ्लेशन'' दलदल से उबरने के लिए महाकाय (giant) अंतरराष्ट्रीय इजारेदार संस्थाओं (एमएनसी–टीएनसी) ने इस नयी उदारवादी नीति, दरअसल यह साम्राज्यवादी वैश्वीकरण नीति है, इसके तहत अपने सांप्रदायिक उद्योगों को विदेशों में ले गए. नये किस्म के अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन को शुरू किया. एक वस्तु की तैयारी एक से अधिक देशों में करने द्वारा तमाम विश्व को अपनी फैक्टरी तब्दील कर दिया. एक–एक वस्तु की तैयारी को कई भागों में विभाजित कर, इन अलग–अलग भागों को अलग–अलग देशों/प्रांतों में उत्पादित कर, आखिर उन्हें एक जगह में लाकर पूरी वस्तु के रूप में एसेंबुल करने (जोड़ने) के तरीका अपनाया गया. इस प्रक्रिया में सस्ते में संसाधन एवं श्रम कहां मिलेंगे एवं कहां के कानून अनकूल हैं, इसे देखकर वे उस उत्पादक चैन (production chain) को बनाती हैं. वित्तीय पूंजी कभी भी, कहीं भी आसानी से प्रवेश कर, आसानी से वापसी कर सकती है, इस तरह वे समझौते किए. वे दीर्घकालीन स्वभाव वाले निवेश नहीं लगाती हैं. इस तरह हजारों एमएनसी–टीएनसी अपने उत्पादनों के अनुसार 'ग्लोबल वैल्यू चैन' के जाल बना कर ज्यादातर देशों एवं प्रांतों में विस्तारित की. विश्वभर में विभिन्न देशों में स्वयं अपनी शाखाएं एवं अनुषंगी कंपनियां लगायीं. विशेषकर पिछड़े देशों में दलाल कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर बनायी या उन कंपनियों को संबंधित उत्पादन के सब–कांट्रैक्ट दिए. दलाल कंपनियां निर्यात के लिए ही वस्तुओं का उत्पादन करता है. यह नीति मजदूरों का संगठित शक्ति पर चोट पहुंचाया. नयी आर्थिक नीतियों में यह अत्यंत मुख्य पहलू है. 2017 में विश्व के सबसे बड़े 100 गैर–वित्तीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी संपत्तियों में औसतन 60 प्रतिशत से अधिक संपत्तियों को विदेशों/पिछड़े देशों में स्थानांतरित की या बेच दी. इसके तहत ही वे 21वीं सदी के दूसरा दशक में तेजी से विकसित हो रहे आनलाईन, असेटलाईट नमूने के गिग अर्थव्यवस्था में हिस्सा बनता जा रहा है. यह बहुत हद तक अस्थायी, अंशकालीन, कांट्रैक्ट एवं स्वछंद (freelance) नीति पर आधारित है.

इस क्रम में विश्वभर में विभिन्न औद्योगिक एवं वित्तीय कंपनियों व संस्थाओं में बड़े पैमाने पर विलयन (mergers) एवं अभिग्रहण (acquisitions) हुए. नयी पीढ़ी के इन्फर्मेशन–कम्युनिकेशन्स टेक्नोलोजी की मदद एवं इंटरनेट के आविष्कार से सीमा पार (cross boarder) विलयन, निवेश एवं व्यापार का उभार आया. इसमें

मुट्ठीभर बहुराष्ट्रीय बैंक अपनी वित्तीय पूंजी से विश्व के आर्थिक जीवन में निर्णायक भूमिका निभाई. पूंजी का केंद्रीकरण, अंतरराष्ट्रीय प्रत्यक्ष निवेश, उत्पादन व बंटवारा का सामाजीकरण, अंतरराष्ट्रीयकरण, व्यापार वैश्वीकरण अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गए. विश्वभर में महाकाय बहुराष्ट्रीय इजारेदार कार्पोरेशनों (एमएनसी) का उद्भव हुआ. 2017 तक विश्व में बहुत बड़ी 737 एमएनसीयां विश्व के तमाम उत्पादन में 80 प्रतिशत नियंत्रित कर रही थीं. बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा 80 प्रतिशत विश्व व्यापार चलाया जा रहा था. इन परिणामों को कामरेड लेनिन ने पहले ही भांप लिए और बताया कि भविष्य में मात्र मुट्ठीभर महाकाय वित्तीय संस्थाओं द्वारा ही विश्व को शासित किया जाता है.

महाकाय एमएनसीयों की संपदा लगभग उनके पूरे देशों की संपदा से बराबर होती है. उदाहरण के लिए, 2017 में फार्च्युन 500 सूची में विश्व के सबसे बड़ी कंपनी के स्थान हासिल करने वाली वालमार्ट कंपनी द्वारा कुल 500 बिलियन डालर से अधिक आय आर्जित की गयी. यह बेल्जियम जीडीपी से अधिक था. वह 2020 तक विश्व के 161 देशों से बड़ी अर्थव्यवस्था बन गयी. एपिल कार्पोरेश का बाजार मूल्य (2.7 ट्रिलियन डालर) भारत देश के सकल घरेलू उत्पादन (2.6 ट्रिलियन डालर) से अधिक था. एमएनसीयों के वार्षिक आय के आंकड़ें को, उसी समय के विश्व के कुल लगभग 200 देशों के आय के आंकड़ें से तुलना किया जाए, सबसे बड़ी 100 अर्थव्यवस्थाओं की 70 प्रतिशत से अधिक आय एमएनसीयां आर्जित करती हैं. 2020 तक कुल कार्पोरेट संपदा में 69 प्रतिशत अमेरिका में ही जमा हुई थी.

2017 में विश्व के सबसे बड़ी 500 कंपनियों में आधे कंपनियां (यानी 250 कंपनियां) अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस एवं ब्रिटेन में थे. 100 सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय संस्थाओं में से लगभग दो तिहाई संस्थाएं इन देशों में ही थे. 2020 तक विश्व में 100 सबसे बड़े कार्पोरेशनों में 59 कार्पोरेशन अमेरिका में थे. चूंकि औद्योगिक वैश्वीकरण के तहत आर्थिक कार्यकलापों को और अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया है, इसलिए मुनाफें में अधिक राशी विकसित पूंजीवादी विश्व के मात्र मुट्ठीभर देशों द्वारा हड़प लिया जाता है. वर्ष 2017 में फार्च्युन ग्लोबल 500 सूची के मुताबिक विश्व के 500 सबसे बड़ी कंपनियों में (चीनी कंपनियों को छोड़कर) 380 कंपनियों की आय 22.83 ट्रिलियन डालर तक पहुंच गयी. मुनाफें का हिस्सा एवं मुनाफे का दर इन दोनों सूचीयों में वृद्धि साम्राज्यवाद का लुटेरा चरित्र को उजागर करती है.

वर्तमान में मुट्ठभर महाकाय एमएनसियां ही अंतरराष्ट्रीय तौर पर कई देशों एवं

उनकी सरकारों को शासित करती हैं. दिसंबर 2024 तक 835 खरबपतियों के साथ अमेरिका पहला स्थान में, 427 खरबपतियों के साथ चीन दूसरी स्थान पर हैं. 208 बिलियन डालर संपदा के साथ पहला स्थान पर टेसला मुखिया एलान मस्क, 205 बिलियन डालर संपदा के साथ जेफ बेजोस दूसरा स्थान पर एवं 199 बिलियिन डालर संपदा के साथ बेर्नार्ड आर्नाल्ड तीसरा स्थान पर हैं. कांटार ब्रांड्ज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के सबसे बड़े 100 ब्रांडों में अमेरिकी टेक्नोलोजी महाकाय, आईफोन तैयारी कंपनी ऐपिल (1,01,590 करोड़ डालर) पहला स्थान पर रहा, जबकि गूगुल, माइक्रोसाफ्ट, अमेजान, मेकडोनाल्ड्स क्रमशः अगले चार स्थानों पर रहे. एमएनसीयां अमेरिकी डालर एवं बौद्धिक संपत्ति पर एकाधिकार एवं असमान अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन के जरिए देशों की भागीदारी नीति, उत्पादन के तरीकें एवं मुनाफें के नमूने को व्यापक रूप से पुनःपरिभाषित किया. नए गठजोड़ों, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक–वैचारिक एवं सैनिक क्षेत्रों में आधिपत्य संबंधों को स्थापित किया एवं उन क्षेत्रों का कार्पोरेटीकरण किया. सैद्धांतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक–वैचारिक क्षेत्र को कार्पोरेटीकरण कर अर्थव्यवस्था में कार्पोरेटीकरण का मार्ग सुगम बनाया. प्रतिस्पर्धा लेने की क्षमता विस्तारित की. बाजारों के जाल, प्राकृतिक संसाधनों एवं वित्तीय संसाधनों को नियंत्रित करते हुए, संपदा को और अधिक संचयन कर रही हैं.

नयी उदारवादी विचारों की व्याप्ति के लिए साम्राज्यवादी फाउंडेशनों एवं प्रबुद्ध मंडलों (थिंकटैंक) ने मुख्य प्रेरक शक्ति के रूप में काम किया. इसमें मुख्य रूप से मिल्टन फ्रीडमैन, आर्नाल्ड हर्बेर्गर जैसे अर्थशास्त्री आगे रहे. उदाहरण के लिए, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर सेमिनारों एवं शैक्षणिक संस्थानों को पैसे देकर अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन, राकफेलर फाउंडेशन, मोंट पेलेरिन सोसाईटी, सेंटर फर इंटरनेशनल प्राइवेट एंटरप्राइज जैसी संस्थाएं नयी उदारवाद के नाम पर साम्राज्यवादी मुल्यों को प्रोत्साहित कर रही हैं. लातीन अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीपों से आने वाले अर्थशास्त्र के छात्रों को इन मूल्यों से लैस कर उन्हें ''शिकागो बोयस'' (Chicago boys) बना रही हैं. इनके साथ ही विश्वभर में विभिन्न देशों की खुफिया एवं सुरक्षा संस्थाएं एवं एमएनसियों के निदेशालय भरे पड़े हैं. वे ही लोग देश के प्रधान मंत्रियों, आर्थिक मत्रियों, अर्थशास्त्रियों, सरकारी बैंक अधिकारियों एवं कार्पोरेट वकीलों के रूप में बदल कर एमएनसीयों के लिए दरवाजें खोले हैं. उन नीतियों को थोप रहे हैं. मिल्टन फ्रीडमैन को नोबल पुरस्कार देने के बाद इन नयी उदारवादी नीतियों को और मजबूती मिली. इस तरह वित्तीय पूंजी राज्ययंत्र को नियंत्रित कर रही है. राज्य पूंजी के हाथों में साधन बन गयी

है. राज्य जनता पर, विशेषकर श्रमिक जनता पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष हिंसा अमल करते हुए पूंजी का मार्ग सुगम बनाया है.

साम्राज्यवाद अपनी शैक्षिक जीवन की उदारवादी साहित्य, कलाओं, मूल्यों को देश–विदेशों में मुख्य रूप से मीडिया चैनेलों, शिक्षा एवं प्रचार कार्यकलापों के जरिए विस्तारित करने द्वारा विश्व पर अपनी सांस्कृतिक आधिपत्य को स्थापित किया. माग्जिम, वेर्व, ओग, कास्मोपालिटन जैसी पत्रिकाओं, हालीऊड सिनेमाओं, अपने नियंत्रण में होने वाले लगभग 75 प्रतिशत विश्व टेलिविजन कार्यक्रमों, संगीत एवं साहित्य के जरिए पश्चिमी जीवन शैली के प्रति विश्वभर में जनता के अंदर भ्रम फैलाया. अमेरिकी मुख्य धारा वाले मीडिया द्वारा चलाए जाने वाले रीसर्च एवं रिपोर्टिंग के जरिए दुनियाभर में जनमत बना रहा है. इस साम्राज्यवादी वैचारिक बुनियाद पर आधारित होकर पिछड़े देशों में नयी उदारवादी नीतियों को अमल में लाया.

इसके मुताबिक भारत देश में जनमत को बनाने के उपलक्ष्य में देश के आजीम प्रेमजी, जिंदल, टाटा, रिलयेंस जैसे दलाल कार्पोरेट कंपनियां भी थिंक टैंक स्थापित की. छात्रवृत्ति आदि कार्यक्रमों के लिए राशी को मंजूरी देना, कला–साहित्य समारोह को संचालित करना, 'थिंक फेस्ट' एवं भावुक बहसें चलाना, शैक्षिणिक–स्वास्थ्य संस्थाओं का संचालन एवं पुरस्कार देना, इनके जरिए ये थिंक टैंक निरंतर पश्चिमी एवं उत्तराधुनिकतावाद आदि कम्युनिस्ट विरोधी विचारधारा की व्याप्ति करते हुए पूंजीवाद में 'विविधता' को ऊंचा उठा रही हैं. उदारीकरण नीतियों में जाति, राष्ट्रीयता एवं धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है, वह वास्तविक सामर्थ्य को मान्यता देती है, ऐसा प्रचार–प्रसार कर रही हैं. नए तौर पर (बहुत ही कम मात्रा में) उबरने वाले दलित खरबपतियों की इशारा करते हुए इसी को 'दलितों की उन्नति' कह रही हैं. दूसरी तरफ दलाल शासक वर्ग ने उदारीकरण के दुष्प्रभाव जनता को समझ में न आए, इसके लिए धर्मों के बीच, जातियों के बीच, राष्ट्रीयताओं के बीच नए नए संघर्ष पैदा कर रही हैं. बाबरी मस्जिद को गिराने से लेकर ज्ञानवापी तक कितने भी उदाहरण इसके लिए दिया जा सकता है.

वैश्वीकरण रणनीति के तहत साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी ने तमाम पिछड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बुलडोजिंग करते हुए तेजी से हमला शुरू किया. भारत देश के दलाली शासक वर्ग जो पहले से विदेशी पूंजी पर आधारित नीतियों को अमल कर रहे हैं, 1985 से, विशेषकर 1991 से, आईएमएफ, विश्व बैंक, उसके बाद विश्व व्यापार संगठन की शर्तों पर अमल करते हुए बड़े छलांग लगाएं और वैश्वीकरण (एलपीजी) नीतियों को मनमानी तरीके से अमल कर रहे हैं. इस चरण में मुख्य

रूप से दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग (सीबीबी) अपनी स्थिति को कई गुणा अधिक मजबूत किया है. इसके लिए पुराने भारत देश की अर्ध–औपनिवेशिक एवं अर्ध–साम्रती व्यवस्था को कायम रखा है. वैश्विक वित्तीय पूंजी से और अधिक लपेटते हुए, अपने हितों का भी पूरा करने के लिए विभिन्न चरणों में अर्ध–औपनिवेशिक एवं अर्ध–सामंती व्यवस्था में कुछ बदलाव कर रहा है. अपने शोषण एवं उत्पीड़न को जारी रखने, उत्पीड़ित जनता में विभाजन पैदा करने, मजदूर–किसान आदि उत्पीड़ित जनता, उत्पीड़ित तबकों एवं उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं द्वारा साम्राज्यवाद, सामंतवाद एवं दलाल नौकरशाह पूंजीवाद के खिलाफ किए जाने वाले वास्तविक संघर्ष पर चोट पहुंचाने के लिए जाति–आधारित सामंतवाद एवं जातिप्रथा को बढ़ावा देते हुए, जाति को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करता ही रहा है.

दलाली शासक वर्गों ने साम्राज्यवादी वैश्वीकरण (एलपीजी) नीतियों के तहत नयी आर्थिक नीति, नयी औद्योगिक नीति, नयी कृषि नीति, नयी व्यापार नीति, नयी बैंकिंग नीति, नयी जूट नीति, नयी कोयला नीति, पर्यटन नीति, आईटी नीति, एनीमेशन नीति, फार्मा नीति, स्टार्टप नीति – इस तरह एक–एक क्षेत्र को एक–एक विशेष नीति अमल में लाए. कई वित्तीय सुधार वगैरा शुरू किए. इसके लिए सैकड़ों कानूनों में संशोधन किए. राष्ट्रीयता के नाम पर अंधराष्ट्रवाद एवं धर्म के नाम पर हिंदू धर्मोन्माद बहकाते हुए सत्ता में आयी ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार वैश्वीकरण नीतियों को आक्रामक रूप से अमल कर रहा है. साम्राज्यवाद एवं दलाल नौकरशाह पूंजीवाद को लाल कालीन बिचा रहा है. ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी तरीकें आक्रामक रूप से अमल कर रहा है. किसी भी तरह के जन प्रतिरोध को दबाने के लिए भारत देश के संविधान को भी बाजू में रखकर, नाम मात्र जनतंत्र को भी कुचला जा रहा है. नागरिक जनवादी अधिकारों पर हमले तेज हो गए. मोदी सरकार ने मुट्ठीभर वालों की गैर–संवैधानिक तानाशाही व्यवस्था एवं एक व्यक्ति का शासन स्थापित करने पर तुली हुई है. चुनाव आयोग, न्यायिक व्यवस्था, आरबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीबीआई जैसे संस्थाओं को सीबीबी का जेब संस्था बना रही है. तमाम क्षेत्रों में विदेशी पूंजी को अनुमति देने के लक्ष्य से शत प्रतिशत निजीकरण एवं कार्पोरेटीकरण करने के लिए योजना आयोग की समाप्ती की. इसके स्थान पर नीति आयोग (नेशनल इंस्टिट्यूट फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया–NITI कमिशन) की स्थापना की. इससे पहले ही कई क्षेत्रों में शत प्रतिशत विदेशी पूंजी के लिए रास्ता बनाया. अर्थव्यवस्था को खतरे में धकेल दिया.

वैश्वीकरण के दौरान एमएनसीयां भारत देश में अपने लिए सूपर मुनाफें दिलाने वाले सेवा क्षेत्र के अलावा उत्पादन क्षेत्र में भारी पूंजी नहीं लगायीं. इसलिए विदेशी पूंजी लगाने वाले क्षेत्रों में उत्पादन क्षेत्र चौथी स्थान पर है. इसके अनुसार ही देश में सीबीबी का व्यवहार रहा. विश्व बैंक की एलपीजी नीतियों को अमल करने के लिए बनायी गयी 'ईज आफ डूइंग बिजनेस' नीति को 'मेक इन इंडिया' योजना के नाम से बड़े पैमाने पर प्रचारित करने वाले मोदी के 11 वर्ष के शासन में भी उत्पादन क्षेत्र उतना विकास नहीं कर पाया है. जीडीपी में तैयारी क्षेत्र का हिस्सा सिर्फ 17–18 प्रतिशत है. एक तरफ प्रधानतया अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी एवं एमएनसीयों के भारी यंत्रों एवं तकनीक पर निर्भर रहते हुए, उत्पादन क्षेत्र में देश को 'आत्मनिर्भर' बनाने के नाम पर बड़े पैमाने पर किए जाने प्रचार मात्र ढकोसला है. मेक इन इंडिया योजना के तहत 2014–2023 के बीच देश में कुल 900 बिलियन डालर से अधिक एफडीआई निवेश को तैयारी क्षेत्र में नहीं, बल्कि अनुत्पादक क्षेत्र एवं रोजगार सुरक्षा नहीं होने वाले व सघन श्रम शोषण करने वाले असंगठित क्षेत्र में लगाया है. फलस्वरूप ये क्षेत्र मुख्य क्षेत्र बन गए. रेलवे, बीमा, रक्षा, स्वास्थ्य उपकरण तैयारी क्षेत्र में भारी मात्रा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आए हैं. विदेशी पूंजी की सेवा करने के लिए 'इन्वेस्टर फेसिलिटेशन सेल' बनाया है. दिल्ली–मुंबई, अमृतसर–कोलकाता, चेन्नाई–बेंगलूरु, विशाखापट्टनम–चेन्नाई के औद्योगिक गलियारे और बेंगलरु–मुंबई आर्थिक गलियारा स्थापित की है. स्किल इंडिया, स्टार्टप इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्मार्ट सिटी, अमृतकाल, स्वच्छभारत अभियान, सागरमाला इस तरह कई योजनाओं से हासिल की गयी वृद्धि तैयारी क्षेत्र की नहीं, बल्कि सेवा क्षेत्र की है. एफडीआई, चार क्रूर मजदूर कानून, कृषि क्षेत्र के क्रूर कानून आदि कार्पोरेट प्रायोजित कानूनों से देश को देश–विदेशी कार्पोरेट कंपनियों को लूटने के लिए ही मदद मिली. वित्तीय पूंजी के सहयोग से, वित्तीय पूंजी के लिए एवं उसकी नियंत्रण में तमाम क्षेत्रों में अमल की जाने वाली नीतियां उत्पादक शक्तियों के विकास के लिए रुकावट बन गए. इसका कारण मात्र यह है कि देश में दलाली शासक वर्गों द्वारा अमल की जाने वाली साम्राज्यवादी विकास विध्वंसक नमूना.

वैश्वीकरण नीतियों के कारण राज्यतंत्र में उच्च अधिकारियों की एक तबका आम कर्मचारियों से कई गुणा अधिक वेतन लेता है, इसके अलावा अपने निरंकुश अधिकार को इस्तेमाल कर कई हवाले रास्तों में बड़ै पैमाने पर संपदाएं आर्जित की है. इनके अलावा विभिन्न दलाल कार्पोरेटों, आईटी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, निजी बैंकों के सीईओ, निदेशकों एवं उच्च अधिकारों के रूप में काम करते हुए

एक तबका करोड़ पैसे आर्जित अमीर बन गए. ये तबकें सीबीबी का हिस्सा है. वैश्वीकरण के समय में इन तबकों में भी कई उतार–चढ़ाव होने के बावजूद पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने वाली तबकें इसका अधिक लाभ उठाया है.

इस समयकाल में भारत देश विदेशी रुणों का दलदल में और अधिक फंस गया है. भारत देश के रुण दिसंबर 2023 तक एक करोड़ 61 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा था. यह 2023–24 में 56.9 प्रतिशत बढ़ा है. एक आकलन के मुताबिक 2024–25 में रुणभार जीडीपी में 56 प्रतिशत हो सकता हैं. हर रुपये में लगभग आधा हिस्सा ब्याज भुगतान के लिए खर्च किया जाता है. रुण भुगतान के लिए फिर से रुण लेने की बुरा हाल इस पूरे काल में जारी रही है.

भारत देश के उद्योगों का विलयन एवं कब्जा करने की वजह से एमएनसीयों का प्रभुत्व बढ़ा है. दिवालिया होने के नाम पर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों (बैंकों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों) को बंद किया जा रहा है. मुनाफें कमाने वाली कंपनियों के शेयर भी आधुनीकरण, विलयन एवं कब्जे के नाम पर कौडियों के दाम पर बेचा जा रहा है. दिवालिया होने वाले उद्योग एवं स्वस्थ होने वाले उद्योगों के बीच अंतर नहीं रह गया. बुनियादी सुविधाओं (infrastructure) की व्यवस्थाओं को निजी दलाल कार्पोरेट कंपनियों एवं साम्राज्यवादी एमएनसियों को हवाला किया जा रहा है. इससे रेलवे, एयर इंडिया, एमटीएनएल, बीएसएनएल, बीबीसीएल जैसे सरकारी क्षेत्र के संस्थाओं एवं प्लांटों के शेयर या संपत्तियां बड़े पैमाने पर दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग या साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निजी मालिकाने में चली गयी है. कई राज्यों में बिजली उत्पादन एवं वितरण को निजीकरण किया गया है. तमाम राज्यों में परिवहन एवं कम्युनिकेशन्स में निजीकरण का क्रम जारी है. बिजली, सड़क, टेली कम्युनिकेशन्स आदि में बड़े पैमाने पर रुण मजूरी करने के लिए अमेरिका ही नहीं, बल्कि यूरोपीय संघ, जापान, चीन, रूस आदि साम्राज्यवादी देश भी प्रतिस्पर्धा ले रहे हैं.

विमानन कंपनियों, तेल कंपनियों, प्रोजेक्टों एवं बैंकिंग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार कार्यक्रम लागू किया जा रहा है. मुख्य हवाई अड्डों, बंदरगाहों, रेलवे स्टेशनों को कब्जा करने में विदेशी पूंजी को अनुमति दी जा रही है. कोयला खदान क्षेत्र में शत प्रतिशत एफडीआई को अनुमति दी गयी है. विदेशी पूंजी पर लागू किए गए तमाम प्रतिबंधों को हटाकर, साम्राज्यवादी बैंकों एवं बीमा कंपनियों के लिए देश को खोल दिया गया है. 2009 में ही भारत देश के निजी बैंकों के लिए राष्ट्रीय/सार्वजनिक बैंकों से बराबर अधिकार दिए गए थे. इससे संगठित क्षेत्र घट रहा है. असंगठित क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र मुख्य क्षेत्र बन गए हैं.

देश के प्राकृतिक संसाधन भारत देश के सीबीबी के लिए मुनाफें का खजाना है. खनिज संपदा को हड़कने के लिए बड़ी दौड़ जारी है. झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंग, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आदि राज्यों में दसियों लाख करोड़ रुपये के खनन परियोजनाओं के लिए समझौते हो चुके हैं. एमएनसीयों एवं बेड़े पूंजीपतियों के भारी खनन कंपनियों (माईनिंग कार्पोरेटों) के लिए विशाल भूभाग आवंटित किए गए हैं. औद्योगिक गलियारे के लिए भू–बैंकिंग नीति के नाम पर छोटे एवं सीमांत किसानों की जमीन को सस्ते में हड़प लिया गया है. इसी वजह से अनाज के लिए कमी आ गयी.

विशेष आर्थिक मंडलों (सेज–SEZ) को स्थापित करने एवं राज्य सरकारों से सीधा समझौतें करने के लिए साम्राज्यवादियों, विशेषकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों को अनुमति दी गयी. इससे वे उद्योगों को स्थापित करने, जगमगाने वाले सड़कों, हाईटेक पार्कों, हैदराबाद, बेंगलूरु जैसे हाईटेक नगरों एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के प्रोजेक्टों को निर्माण करने के लिए शर्तों पर सीधा रुणों की मंजूरी दी जा रही है. ऐसे रुणों के लिए विभिन्न राज्य सरकारें होड़ में लगी हुई हैं. इसमें सीपीआई (एम) नेतृत्व वाली राज्य सरकारें भी शामिल हैं. इन प्रोजेक्टों के लिए लाखों एकड़ उपजाऊ कृषि जमीन को किसानों से सस्ते दरों पर सरकारें हड़प रही हैं. भारत देश के इतिहास में ही जमीन के सबसे बड़े कब्जे अभी हो रहे हैं. सेज, बांधों, सूपर–हाईवे, शहरी 'पुनर्विकास', मेट्रो प्रोजेक्ट जैसे बड़े 'विकास' प्रोजेक्टों एवं खनन परियोजनाओं के कारण जंगलों में आवास करने वाले लाखों आदिवासी को अधिक से अधिक विस्थापित किए जा रहे हैं. सेजों में अमल हो रहे आधुनिक गुलामी व्यवस्था में लाखों मजदूरों, विशेषकर महिला मजदूरों का तीव्र श्रम शोषण हो रहा है. अंतरराष्ट्रीय मजूदर संगठन के आंकड़ें के मुताबिक इस आधुनिक गुलामी व्यवस्था का फायदा उठाकर विश्वभर में एमएनसियां हर वर्ष 150 बिलियन डालर मुनाफें आर्जित कर रही हैं.

दलाली सरकारें सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता (पीपीपी) नामक शोषणकारी नीति को विस्तारित कर रही है. पीपीपी का मतलब है अंतरराष्ट्रीय इजारेदार संस्थाओं एवं सीबीबी संस्थाओं के एकाधिकार के अलावा और कुछ नहीं. यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं सीबीबी को समृद्ध बनाने वाले तरीकों में से एक है. लुटेरी सरकारें इस नमूने को इस्तेमाल कर विभिन्न प्रोजेक्टों को क्रमशः निजी नियंत्रण ले जा रही हैं. उदाहरण के लिए पिछले 30–40 वर्षों से हवाई अड्डे, नौका निर्माण केंद्र, सड़कें, शहरी परिवहन, आपूर्ति (पानी व बिजली), अस्पताल, रक्षा तैयारी आदि सरकारी नियंत्रण वाले कई क्षेत्रों को निजी कंपनियों के हाथों में हवाला किया जा

रहा है. कोयला, बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों को भी निजीकरण किया गया. कृषि क्षेत्र को साम्राज्यवादियों एवं भारत देश के बड़े कार्पोरेट कंपनियों को हवाला किया जा रहा है. इस तरह विभिन्न नामों पर उन्हें जनता की संपदा हवाला करने के लिए वैधानिक सभाओं में सीबीबी के लिए अवरोध होने वाले सैकड़ों कानूनों को रद्द किए जा रहे हैं (उदाहरण, 40 मजदूर कानूनों का रद्द) और सीबीबी के लिए उपयोग होने वाले कई कानून लाए जा रहे हैं. इसी का हिस्सा है 4 मजदूर संहिता, नोटबंदी, जीएसटी, वन सुरक्षा कानून–2023, केंद्रीय खनन कानून आदि.

मुख्य रूप से शेयर बाजार का विकास से सीबीबी ने खूब मुनाफें कमाया. वह बैंकों से भारी रुण लेकर, अपनी संपत्ति एवं शेयर क्रय–बिक्री करते हुए कृत्रिम मांग पैदा कर, उसके जरिए और अधिक निवेश को आकर्षित करते हुए, शयेरों को सबसे अधिक दरों पर बिक्री करते हुए मुनाफें आर्जित किया. बढ़ते शयरों की बुनियाद पर राष्ट्रीय/सार्वजनिक बैंकों, एलआईसी आदि वित्तीय संस्थाओं से और अधिक रुण प्राप्त कर पाया. इस चक्रीय क्रम से उनके व्यापार और विस्तारित हुआ. इस तरह सीबीबी सबसे कम पूंजी एवं प्रयास से भारी मुनाफें हासिल कर पाया. उदाहरण के लिए पतंजलि कंपनी.

गरीब जनता को निशाना बनाकर विश्वभर के खरबपति अत्यधिक ब्याज दर वसूल करते हुए माईक्रो फाइनांस कंपनियों में बड़ी राशी निवेश किए. यह रुझान विश्वभर में दावानल की तरह फैल गया. इसमें विश्व वित्तीय पूंजी ने भारत देश समेत पिछड़े देशों में हजारों गरीब जनता की बचत राशी को लूट कर सूपर मुनाफें कमाया, जबकि बड़ी संख्या में जनता आत्महत्याएं कीं. माइक्रो फाइनांसिंग जनता को राजनीतिक आंदोलनों से दूर किया.

दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग की कंपनियां बैंक रुण भुगतान करने से बचते हैं. सरकार उन्हें बट्टे खाते घोषित कर माफी करती है. ये बट्टे खाते दिसंबर 2022 तक रु. 11.17 लाख करोड़ो तक पहुंच गए. इन्हें मोदी सरकार 2022 के सर्दियों के संसदीय बैठकों के दौरान रद्द किया. बट्टे खातों से दिवालिया होने वाले बैंकों को बचाने एवं दलाल कंपनियों के वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ही मोदी सरकार नवंबर 2016 में कालेधन (black money) को समाप्त करने के नाम पर 'नोटबंदी' लागू की. जीएसटी एवं ई–वे बिल नीतियों को लागू कर हजारों एमएसएमई उद्योगों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों को दिवालिया करवाया, करोड़ों लोगों का रोजगार छीन कर, उन्हें सड़कों पर फेंक दिया. सीबीबी के हितों को पूरा कर लिया.

भारत देश के सीबीबी द्वारा मजबूती से कार्यरत और एक क्षेत्र है स्टार्टप. 2013 में 350 स्टार्टप थे, मार्च 2023 तक इनकी संख्या 2 लाख तक पहुंच गयी. 130 यूनिकार्न के रूप में विकसित हुए. मोदी सरकार के स्टार्टप कानून ने स्टार्टप कंपनियों पर वित्तीय पूंजीपतियों को अपार अधिकार दे दिया. भारत देश के सीबीबी का सपना है कि आलीबाबा, बाइडु जैसे एक भारत देश की एमएनसी को स्थापित करना.

सत्ता हस्तांतरण के 50 वर्षों तक दलाली शासक 'तकनीकी अनुसंधान' पर किसी भी तरह की नीति नहीं बनायी. बाद में नीतियां बनाने के बावजूद, वे मात्र प्रचार करने तक सीमित रही. भारत देश की बड़ी पूंजी के मालिकाना वाले फैक्टरी उद्योग दरअसल भारत देश के व्यापारियों के कौशल एवं विदेशी उत्पादन के इंजीनीयरों से पली–बड़ी है. इसीलिए हमारा देश की दलाली सरकारें साम्राज्यवादी देशों एवं उनकी एमएनसीयों की बौद्धिक संपदा से प्रतिस्पर्धा नहीं ले पाने एवं एमएनसीयों एवं सीबीबी के हितों को पूरा करने लायक पेट्रोलियम, टेलिफोन, बिजली, रेलवे जैसे क्षेत्रों में ही पूंजी लगायीं. उन्हें विदेशी रुणों से भरा दिया. आईएमएफ एवं विश्व बैंक के रुणों से निर्माण करने वाले प्रोजेक्टों एवं प्लांटों में विदेशी आधुनिक टेक्नोलोजी को ही इस्तेमाल किया.

फलस्वरूप देश में तकनीकी ज्ञान पर महाकाय बहुराष्ट्रीय संस्थाओं (एमएनसी–टीएमसीयों) का एकाधिकार जारी है. तकनीकी ज्ञान तेजी से बदलते हुए पुराना हो रहा है. ऐसे में भारत देश में फैक्टरी उद्योग तकनीकी ज्ञान एवं पूंजीगत वस्तुओं (capital goods) के लिए मुख्य रूप से विदेशी वित्तीय पूंजी पर निर्भर होने का रुझान जारी है. फलतः बहुत तेजी से उत्पादित वस्तु पुराने (out-dated) हो रहे हैं. तकनीकी ज्ञान को स्वतंत्र रूप से विकसित करने की नीति नहीं होना देश का विकास के लिए मुख्य अवरोध बना हुआ है.

साम्राज्यवादी थिंक टैंकों द्वारा किए जाने वाले इस प्रचार में थोड़ा भी सच्चाई नहीं है कि एमएनसीयों की स्थापना से उनके साथ नयी टेक्नोलोजी भी मिलती है, औद्योगिक विकास होता है, रोजगार अवसर बढ़ते हैं. क्योंकि एमएनसीयों ने मुनाफें के अलावा किसी भी दूसरे विषय पर ध्यान नहीं देता है. अपने जरूरतों के लिए पिछड़े देशों को टेक्नोलोजी बदली करने के बावजूद, वे द्वितीय स्तर की टेक्नोलोजी ही देती है. उस टेक्नोलोजी से आत्मसात करने के मामले भी भारत देश के उद्योग क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है. वास्तव में इस देश में हेंडसेटों समेत समस्त टेलिकाम क्रांति को आयातित सामग्री से ही चलायी गयी. हाल ही की 5 जी सेलफोन सेवाएं आयातित टेक्नोलोजी पर ही आधारित हैं. रिजर्व बैंक द्वारा

लाया गया ई–रुपया भी विदेशी टेक्नोलोजी पर ही निर्भर है. हमारा कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले हर एक चीज विदेशी बौद्धिक संपत्ति से ही उत्पादित है. सड़क निर्माण करने वाली कंपनियों एवं बहुउद्देशीय प्रोजेक्टों की निर्माण संस्थाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले समस्त उपकरण विदेशी उत्पादन ही हैं. भारत देश में महाकाय सोफ्टवेयर क्षेत्र अपना मालिकाना में विकसित किए गए सोफ्टवेयर बहुत कम है. वह मात्र आयातित किए गए सोफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहा है. देश में अनुसंधान और विकास (R and D) पर लगाए जाने वाले खर्च भी कम है. इसी तरह एमएनसीयों द्वारा लायी जाने वाली आधुनिक टेक्नोलोजी से रोजगार छीन जाता है, बढ़ता नहीं. वे कहीं भी नयी टेक्नोलोजी लाने से भी संबंधित विज्ञान एवं सूत्रों (formulas) को आम तौर नहीं देती हैं. वे अपने देशों को छोड़कर, पिछड़े देशों में निवेश करने का कारण है – वहां किसी को उद्धार करने का नहीं है, बल्कि मात्र वहां के कमजोर कानूनों, लाभदायक टैक्स नीतियों को इस्तेमाल कर, वहां की सस्ते से मिलने वाली प्राकृतिक संपदाओं एवं श्रमशक्ति को लूटना ही है. ऐसे कमजोर कानूनों एवं लाभदायक टैक्स नीतियों को स्वयं उनके द्वारा ही हाथ घुमा कर वैधानिक सभाओं में पारित करवाया जाता है.

वैश्वीकरण नीतियों के कारण पिछले तीन दशकों में देश की जरूरतों से संबंध के बगैर साम्राज्यवादियों को सूपर मुनाफें पहुंचाते हुए आयातित किए गए पुराने हाईटेक यंत्र एवं टेक्नोलोजी का इस्तेमाल बहुत बढ़ा है. इससे इस दौरान देश के इतिहास में तेजी से हुई तथाकथित 'बबूला वृद्धि' देश की अर्थव्यवस्था का विघटन, सामाजिक अशांति एवं पर्यावरण का विध्वंस की ओर ले गयी. फलतः मजदूरों एवं कर्मचारियों के रोजगार छिन्न गया. कैजुअलीकरण/ठेकाकरण बढ़ा है. आउटसोर्सिंग बढ़ा है. 2015–2023 के बीच 18 लाख सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम किस्म के उद्योग (MSMEs) बंद होकर 54 लाख लोगों ने रोजगार खो दिया. 'रोजगार विहीन वृद्धि' मुख्य रुझान बन गया. आर्थिक असमानताएं गंभीर स्तर तक पहुंच गयीं. बेरोजगार पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक स्तर पर पहुंच गया. सघन मजदूरी (labour intensive) वाली भारत देश की अर्थव्यवस्था संघन पूंजी (capital intensive) वाली बनती जा रही है. रोजगार खो जाने वाली श्रमिक शक्ति औद्योगिक क्षेत्रों से वापस मूड़ कर कृषि क्षेत्र की तरफ जा रही है. 2016–2017 से 2021–22 के बीच 5.2 करोड़ों में से 2.7 करोड़ लोग यानी लगभग 50 प्रतिशत तैयारी (औद्योगिक) क्षेत्रों से वास चले गए. वस्त्र, भवन निर्माण, फुड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार की कमी अधिक दिख रही है. शहरों में रोजगार कम होने के कारण कृषि पर निर्भर होने वालों की संख्या बढ़ी है. 2018–19 के बीच 42.5

प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर थे, जबकि यह संख्या 2022–23 में 45.8 प्रतिशत तक बढ़ गयी. इससे कृषि क्षेत्र और संकट में फंस गया. पिछले 30 वर्षों में 4 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की. 26 करोड़ कृषि मजदूर बदहली जिंदगियां जी रही हैं.

आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि आज देश में गरीबों की संख्या 81.35 करोड़ों तक पहुंच गयी; 75 प्रतिशत ग्रामीण जनता एवं 50 प्रतिशत शहरी जनता गरीबी में पिस रही है. प्रति वर्ष 7 लाख यानी रोज 160 युवा आत्महत्या कर रहे हैं. देश में 10 करोड़ से अधिक युवा मादक प्रदार्थों के चक्कर में जूझ रहे हैं. विश्व में सबसे अधिक गरीब होना वाला देश भारत देश है. 2024 के विश्व भुखमरी की सूची में श्रीलंका, नेपाल, म्यान्मार एवं बंगलादेश से पिछड़ कर भारत देश 105वें स्थान पर है. पिछले 30 वर्षों में दिसंबर 2024 के पहली सप्ताह तक रुपया की मूल्य एक डालर के लिए 84.72 रुपये तक गिर गया. एक महीना में ग्रामीण जनता की आय 1,059 रुपये एवं शहरी जनता की आय 1,286 रुपये तक घटी है. विश्व के औसत प्रति व्यक्ति आय में हमारा देश की जनता के औसत प्रति व्यक्ति आय एक चौथायी से कम है. अर्जुनसेन गुप्ता कमेटी के मुताबिक देश की आबादी में 77 प्रतिशत लोग 20 रुपये की रोजवारी आय से जीवनयापन कर रहे हैं. मार्च 2024 के विश्व असमानता लेब नामक एक शोध संस्था के आंकड़े के मुताबिक भारत देश में उच्च आयवाला वर्ग के एक ही प्रतिशत लोग देश की आय में 22.6 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करते हैं. यह पूरा दुनिया में ही अधिक है. अब संपदा के मामले को देखा जाय, 2022–23 में एक प्रतिशत अमीरों के पास 40.1 प्रतिशत संपदा है. इससे देश में आर्थिक असमानताएं कौंसी स्तर पर पहुंय गयी, खरबपतियों की संख्या क्यों बढ़ रही है, इसे समझ सकते हैं. इस तरह देश में मुट्ठीभर दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के हाथों में भारत देश की संपदा केंद्रीकृत होना वैश्वीकरण नीतियों का ही नतीजा है.

इस समयकाल में संकटग्रस्त साम्राज्यवाद के लिए आईटी विकास एक हद तक सहयोग दिया. भारत देश में कुछ नए खरबपति आईटी कंपनियों को स्थापित कर एमएनसीयों को आउटसोर्सिंग कर मुनाफें कमाए. देश में उच्च स्थान में होने वाली 20 सोफ्टवेयर कंपनियां कुल सोफ्टवेयर निर्यातों में लगभग आधे हिस्सा तक निर्यात कर रही हैं. यह एक तबकें के अमीर एवं उच्च मध्यम वर्ग के लिए विभिन्न अवसर प्रदान किए. नए अमीर वर्ग एवं नए शोषण के स्वरूप सामने आए. अत्यधिक सस्ते कौशल श्रम वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के बीपीओ (बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) व्यापार, बयोटेक एवं आईटी व्यापार सफल हो गए. इनमें से मुख्य

नौकरियों में अमेरिका वालों को ही नियुक्ति की जाती है. इसलिए अमेरिकी कर्मचारी एवं भारत देश के कर्मचारी के बीच वेतन अनुपात 24:1 तक, यानी बहुत अधिक अंतर होता है. इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं देशीय दलाल नौकरशाह पूंजीपति कंपनियां अधिक मुनाफें आर्जित कीं. लेकिन कृत्रिम बुद्धिमता का प्रभाव कई क्षेत्रों की तरह आईटी क्षेत्र पर भी रहा है. इससे पिछले 3–4 वर्षों से उसका वैभव कम होता जा रहा है.

दलाली शासक एक तरफ निर्यात उद्देशित उत्पादन को बढ़ाने पर प्रोत्साहन दिए, दूसरी तरफ आयात पर पाबंदियों को ढील कर रोजवारी जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले 1,400 से अधिक वस्तुवों पर तमाम आयात शुल्कों की समाप्ती की. कृषि उत्पादनों की व्यवस्थाओं को कुछ कार्पोरेट संस्थाएं अपने हाथों में लेने का प्रयास कर रही हैं. चूंकि ई–कामर्स के जरिए व्यापार बढ़ रही है, इसलिए व्यापार पर इजारेदार संस्थाओं का प्राबल्य बढ़ रहा है; छोटे एवं मध्य स्तर के व्यापारी दिवालिया हो रहे हैं.

शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में एक तरफ सरकारें जनकल्याण कार्यकलापों की जिम्मेदारी से हट रही हैं, दूसरी तरफ निजीकरण एवं कार्पोरेटीकरण के साथ एमएनसीयों एवं सीबीबी के एकाधिकार गंभीर स्तर तक पहुंच गया है. चूंकि हजारों की संख्या में सरकारी स्कूलें बंद पड़े हैं, इसलिए गरीबों के लिए शिक्षा के अवसर न कि बराबर हो गए हैं. बच्चों के लिए पेशेवर उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं का इस्तेमाल करते हुए कार्पोरेट मालिकानों द्वारा आईआईटी, आईआईएम जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों एवं नीट प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग केंद्रों की शिक्षा का व्यापारीकरण कर अत्यधिक पैसे कमा रही हैं. इस क्षेत्र में पहले से आयी हुई, ज्यादातर सामंती राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली कंपनियों को शैक्षणिक ट्रस्ट के नाम पर राज्यतंत्र द्वारा बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति को सस्ते दामों पर हवाला किया जा रहा है. इस तरह सरकारी मदद को लेकर बड़े बड़े शैक्षणिक साम्राज्यों का निर्माण हो रहा है. रिलयेंस, आजीम प्रेमजी, ओपी जिंदाल, बिड़ला जैसे कंपनियों द्वारा विश्व स्तर की शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण कर लिया गया. इस क्षेत्र में बाईजू जैसे नए दलाल नौकरशाह पूंजीपति आगे आए. मोदी सरकार नए तौर पर एक भी स्कूल निर्माण नहीं किया, बल्कि शिक्षा के लिए बजट आवंटन में कटौती की. नयी शिक्षा नीति के नाम पर मानव परिणाम क्रम, सामाजिक इतिहास एवं विज्ञान शास्त्र के बारे में उल्टे तौर पर परिभाषित करने वाली एवं मध्ययुगीन मनुवादी ब्राह्मणीय हिंदुत्व सांप्रदायिकता को घुसाने वाली शिक्षा प्रणाली को प्राथमिक स्तर से शुरू किया. हाल ही में आन

लाइन शिक्षा एक रुझान बन गया, जो कार्पोरेटीकरण का हिस्सा ही है. विदेशी विश्वविद्यालयों समेत सैकड़ों कार्पोरेट शैक्षणिक संस्थान पिछले तीन वर्षों में आगे आयीं.

स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछले दो दशकों में सीबीबी ने बरगद पेड़ जैसे जड़ें जमायी. तमाम प्रधान एवं दूसरी श्रेणी के नगरों में भी मल्टी स्पेशालिटी अस्पतालें आए. ये आडंबरपूर्वक व्यापार विज्ञापनों के जरिए जनता को आकर्षित कर, फीजों के रूपों में अधिक पैसे हड़पते हुए मरीजों का शोषण कर रहे हैं. निस्सहाय गरीबों के लिए खतरा बन गए. इनके बाद बीमा कंपनियां आती हैं. इन दोनों क्षेत्रों में ये सूपर मुनाफें कमा रहे हैं. छोटे पैसे समेत कितने भी मुनाफें के पीछे श्रमजीवियों का ही श्रम निहित होता है. तथाकथित जन सरकारें जनता का शोषण करते हुए सीबीबी को मजबूत कर रही हैं.

चूंकि पर्यटन क्षेत्र एक व्यापार बन गया, इसलिए कार्पोरेट कंपनियां इसमें प्रवेश किया. बहुराष्ट्रीय कंपनियों के होटल, रिसार्ट, ट्रावेल्स, पार्लर, सेलून, स्पा केंद्र कई खरबों रुपये का व्यापार बन गए. इसी वजह से दुःसाध्य बीमारीयों की व्याप्ति हो रही है.

भारत देश के सीबीबीयों के डिजाइनर ब्रांड ऊंचाइयों तक पहुंच गए. चूंकि आयातित फर्निचर वाली कई उद्योग भारत देश के बाजार में प्रवेश किया, इसलिए हजारों छोटे भारत देश के उत्पादक दिवालिया हो गए. मुख्य त्योहारों को कार्पोरेट या व्यापार राशी के जरिए व्यापारीकरण किया जा रहा है, सूपर मुनाफें आर्जित किया जाना ही नहीं, बल्कि साम्राज्यवादी एवं सामंती संस्कृति की व्याप्ति की जा रही है. खेलों को व्यापार स्तर तक ले जाया गया है. सिनेमा भी एमएनसीयों एवं सीबीबी के हाथों में चले गए. सामाजिक कार्यक्रमों का प्रबंधन (event management) एवं शादी समारोहों का प्रबंधन (wedding planners) इस बीच में आयी नयी सेवाएं थी. ग्रीटिंग्स एवं गिफ्ट उद्योग कुछ विदेशी ब्रांडों के नेतृत्व में चल रहा है.

पिछले दो एवं तीन दशकों से मुख्य रूप से पर्यावरण समस्याएं सामने आयीं. इसका फायदा उठाकर सैकड़ों एमएनसी एवं सीबीबी कमा रही हैं. भारत देश में सुजलान कंपनी पहले पवन चक्कियों का निर्माण शुरू किया. कई कंपनियों को ईएम6 भी है. मेट्रो नगरों में वायु गुणवत्ता कम होना एक व्यापार अवसर बन गया. रूम एवं आफीस एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, मास्कों के लिए व्यापारिक मांग बढ़ रही है. चूंकि कई राज्यों में भूगर्भ जलों को पेयजल के लिए इस्तेमाल

पर अनुमति दी गयी, इसलिए रिवर्स ओस्मोसिस के लिए व्यापारिक मांग ज्यादा बढ़ी है. स्थानीय स्तर पर नए किस्म के जमींदारों के लिए यह और एक व्यापारिक साधन बन गया. इससे भविष्य में भूगर्भ जल का स्तर और गिर जाता है.

इस चरण में वैश्वीकरण नीतियों को अमल करने में, 'अखंड भारत' को स्थापित करने के लिए भारत देश के दलाली शासकों, विशेषकर दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग की विस्तारवादीकांक्षा के अनुसार नीतियों को अमल करने में, ब्राह्मणीय हिंदुत्व विचारधारा को ऊंचा उठाने/अमल करने में, केंद्र में कांग्रस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार हो, भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार हो एवं विभिन्न राज्यों में प्रांतीय पार्टियों व संशोधनवादी व नयी संशोधनवादी सीपीआई व सीपीआई (एम) पार्टियों की सरकारें हो उतना बड़े अंतर नहीं रहे. इन शोषक–शासक वर्ग की तमाम पार्टियों का लक्ष्य है मात्र साम्राज्यवादियों, दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों एवं सामंती वर्गों के हितों को ही पूरा करना. देश में रोज–रोज शासक वर्गों के बीच बढ़ते कुत्तों के संघर्ष से उनके द्वारा अपनायी जाने वाले नीतियों से कोई लेना–देना नहीं है. वे संघर्ष अंतरराष्ट्रीय तौर पर साम्राज्यवादियों के बीच दिन–ब–दिन बढ़ते संकट के नजीते हैं. 'स्वदेशी', 'स्वावलंबन', 'देश चमक रहा है', 'दूसरी पीढ़ी के सुधार', 'मनमोहनोमिक्स', 'मोदीनोमिक्स', 'आत्मनिर्भर भारत' – शब्द प्रयोग कैसे भी हो, इनसे इस वास्तव स्थिति को छिपाया नहीं जा सकता.

2023 की शुरूआत में हिंडेन बर्ग के रिपोर्ट के जरिए अडानी घोटाला प्रकाश में आने के बाद प्रधान मंत्री मोदी एवं अडानी के बीच नजदीकी संबंध 'मोडानी' शब्द से कुख्याति हुई. विश्वभर में साम्राज्यवादी देशों में हो, अर्ध–औपनिवेशिक एवं अर्ध–सामंती देशों में हो, 'राज्य' शोषक वर्गों के हितों का ही संरक्षण देता है. लेकिन साम्राज्यवादी देशों में महाकाय एमएनसी एवं टीएनसीयों के कुछ मुखियाओं ने 'राज्य' से अत्यंत नजदीकी संबंध बनाकर अपने हितों को पूरा करते हैं, प्रतिद्वंद्वी कार्पोरेटों से सामना करने वाली प्रतिस्पर्धा से एवं समस्याओं से तमाम किस्म के संरक्षण प्राप्त करते हैं एवं लाभ उठाते हैं. अर्ध–औपनिवेशिक एवं अर्ध–सामंती देशों के कुछ सीबीबी में भी राज्य से अत्यंत नजदीकी संबंध बनाकर लाभ उठाते हैं. इसी को मुख्य धारा वाले मीडिया ने क्रोनी केपिटलिज्म/क्रोनी केपिटलिस्ट का शब्द प्रयोग कर रहे हैं. वर्तमान में भारत देश में अडानी, अंबानी जैसे दलाल नौकरशाह पूंजीपति केंद्र सरकार के घनिष्ठ मित्र (क्रोनी) बनकर लाभ उठा रहे हैं.

भारत देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपति कितने संपन्न होने के बावजूद, वे कभी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बना पाते. वैश्वीकरण में ऐसे लोगों के साम्राज्यवाद के साथ संबंध सुदृढ़ हो गए, विस्तारित हुए. बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) के साथ

किए जाने वाले ज्वाइंट वेंचरों में भारत देश के सहभागी को कम हिस्सा होने की वजह से उनपर मालिकाना नियंत्रण उनके पास नहीं होता है. इसलिए सीबीबी एमएनसीयों पर और अधिक निर्भर रहते हैं. इसमें कोई एक भी विश्व बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से (एमएनसी) से समग्र रूप से प्रतिस्पर्धा लेने का असली ग्लोबल सिकंदर नहीं है. दरअसल वे मात्र एमएनसीयों के दलाल हैं.

साम्राज्यवादियों के हितों के अनुसार जब का तब बदलती जा रही हमारी देश की अर्ध–औपनिवेशिक एवं अर्ध–सामंती व्यवस्था में दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग आधिपत्य स्थान में है. इसमें दलाली सरकारें हमेशा साम्राज्यवादी एमएनसी व टीएनसीयों की सेवा करती हैं. उच्च राजनेता एवं उच्च अधिकारी संपदा आर्जित करने के लिए साम्राज्यवादियों की अधिकाधिक पादसेवा करते हैं. देश के उद्योग एवं कृषि क्षेत्रों को नष्ट करते हैं. खुद के द्वारा बनाए गए अपने ही संविधान में स्वयं सेंध मारते हैं. उनके 'आत्मनिर्भर भारत' के नारा कितना झूठ है, इससे आसानी से समझा जा सकता है. उन्होंने व्यापक ग्रामीण इलाकों के पुराने व पिछड़े अर्ध–सामंती सत्ता के स्वरूपों से आत्मसात होते हैं. किसी भी तरह की जनवादी चेतना हो, आंदोलन हो, उन्हें कुचल देते हैं. ब्राह्मणीय विचारधारा इसे मदद करती है. दलाली सरकार ब्राह्मणीय हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ावा देते हुए, ऐसी भावना को प्रोत्साहन करते हैं कि उसी विचारधारा से ही लोगों को शांति मिलेगी. बाबा, साधु–संतु बढ़ जाते हैं. इससे मुस्लिम आदि धार्मिक अल्पसंख्यक लोग और अधिक वापस अपनी धार्मिक सांप्रदायिक विचारधारा की तरफ जाते हैं.

वैश्वीकरण के दौर में भी जाति सीबीबी के विकास में मुख्य भूमिका अदा की है. विशेषकर उत्तर भारत देश में सीबीबी बहुत हद तक मात्र कुछ ही जातियों से ही विकसित होना स्पष्ट रूप से दिखती है. ब्राह्मण (गौड सरस्वत ब्राह्मण–GSB) जाति से आए विजय माल्या जैसे कुछ लोग हैं. लेकिन कई लोग बनिया एवं मारवाड़ियों से सीबीबी के रूप में विकसित हुए. इन दोनों जाति के सीबीबी ग्रुप हर वर्ष फर्बस खरबपति सूची में आधिपत्य में होती हैं. इसमें आम तौर पर अंबानी, अडानी एवं एस्सार ग्रुप के रुइया भाइयों के लिए जगह होती है. भारत देश के उद्योग क्षेत्र पर 'बनिया–ब्राह्मण' जातियों का प्रभुत्व चल रहा है. एक अध्ययन के मुताबिक, 21वीं सदी के दूसरा दशक में भारत देश में सबसे बड़े 50 कंग्लोमरेटों का प्रभुत्व है, जबकि देश के दो तिहाई हिस्से के सबसे बड़े सूचीबद्ध कंपनियों को बनिया–ब्राह्मण परिवार ही चला रहे हैं. चूंकि ये संबंध विश्वसनीयता हासिल कर पाते हैं, इसलिए आसानी से समझौतें करने या पैसे कमाने में अपने योगदान दे रहे हैं. ये संबंध अधीनता, इतिहास एवं जाति, इसी तरह मुनाफें एवं राजस्व को

ऊंचा उठाने वाली व्यापार संस्कृतियों पैदा कीं. अभी भी एक ही जाति के लोगों की आपसी सहयोग और अनुकूल होने वाले लोगों के बीच आपसी सहयोग जारी है. वही संबंध जो जाति एवं परिवार से नाता रखते हैं, प्रायः औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक नमूने पृष्ठभूमि जुटा रही है. इसीलिए थोड़ी भी नैतिक मूल्य नहीं होने वाली बनिया जाति के प्रति देश की जनता में असंतोष बहुत प्रबल हुआ है.

'बनिया–ब्राह्मण' आधिपत्य वाले उत्तर भारत देश के सीबीबी अपने व्यापारों में काम करने के लिए कर्मचारियों को नहीं, बल्कि पैसे, उसके अलावा प्रतिष्ठा के लिए भी रेंगने वाले अंधभक्तों को तैयार करते हैं. युद्ध व्यापार संस्कृति कई सीबीबी परिवारों में आधिपत्य में रहती है. वे हमेशा स्वयं युद्ध में लगे रहे वाले सोच रखते हैं. अपने विरोध में किसी भी समय में बनने वाले खतरे एवं होने वाली विश्वासघात को ध्यान में रखकर समय–समय पर अपनी युद्ध तत्परता को पुनर्जीवित करते हैं. 21वीं सदी में हुए बड़े बदलावों से पीड़क जाति संबंध वाले कुछ छोटे व्यापारी परिवार भी एकाएक पूरे विश्व में अपने दलाली व्यापार शेयरों को विस्तारित करते हुए भारी उद्योगों के मुखिया के रूप में, उसमें मुट्ठीभर संख्या में कुबेर परिवारों के रूप में बदल गए. इन दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के परिवारों की जीवन शैली बदल गयी. नयी संपन्न संस्कृति विकसित हुई. एक जमाने में साधारण व्यापारी परिवार अब प्रसिद्ध मजबूत आलीशान भवानों, कार, निजी जेट एवं बहुत बड़े आलीशान बोटों का निर्माण में निवेश करने लगे.

पिछले तीन दशकों में देश में प्रमुख दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के रूप में अंबानी, मित्तल, बिड़ला, अडानी, भारत देश मूल के प्रवासी हिंदूजा, रुइया (एस्सार), जिंदल, टाटा, थापर, बजाज, महींद्रा, मफतलाल, गोयंका, वेदांता, इन्फोसिस, आरपीजी जैसे ग्रुपों की कंपनियां, टीवीएस अय्यंगार, विजय माल्या, दिलीप सिंघवी, आजीम प्रेमजी, शिव नाडार, उदय कोटक, सैरस एस पूनावाला, सैरस पल्लोंजी मिस्त्री, शापूर्जी पल्लोंजी, नरेश गोयल, सुभाष चंद्रा, किशोर बियानी जैसे लोग ऊपर चढ़ गए. आईटी क्षेत्र में नए बनिया–मारवाड़ी व्यापारी नरेंद्र कुमार पाटनी, अरुण जैन ग्रुप, पुराने वस्त्र क्षेत्र में लक्ष्मी झुनझुनवाला, कस्लीवाल भाई ग्रुप, ओस्वाल ग्रुप, लोहिया ग्रुप विकसित हुए, जबकि अशोक भगीरथमल जिव्राजका, राजेंदर गुप्ता, गोपीराम गोयंका जैसे नए दलाल उद्योगपति आगे आए. और कुछ अन्य प्रमुख बनिया–मारवाड़ी ग्रुप फारमा, चीनी, इस्पात, प्लास्टिक उत्पादन, व्यापार वाहन, इलेक्ट्रिक उपकरण, निर्माण, माल परिवहन, नौ परिवहन, आदि क्षेत्रों में आगे आयीं. इनके अलावा पतंजलि जैसे कई महाकाय यूनिकार्न कंपनियां, असेटलाइट एवं ऐग्रिगेट नमूने स्टार्टप कंपनियां उभर कर विकसित हुईं.

जब वैश्वीकरण का चरण शुरू हुआ, यानी 1990 के दशक की शुरूआत तक विश्व में अत्यंत अमीरों की सूची में एक भी भारत देश के खरबपति नहीं थे. 1990 दशक के बीच तक मात्र दो भारत देश के खरबपति – कुमार मंगलम बिड़ला एवं धीरूभाई अंबानी ने 3 बिलियन डालर संपत्ति के साथ उस सूची में शामिल हुए. लेकिन भारत देश मूल के प्रवासी हिंदूजा भाइयों को इसमें शामिल नहीं किया गया. 2002 तक इस सख्या में धीरे–धीरे पांच तक पहुंच गयी. तब से लेकर यह विस्फोटन की तरह विस्तारित करने लगी. 2010 के अंत तक 49, 2014 तक 100 से अधिक, 2020 तक 102, 2022 तक 166, दिसंबर 2024 तक 185 भारत देश के खरबपति बन गए. 2022 के बीच तक इनकी संपदा प्रति रोज रु. 3,608 करोड़ वृद्धि कर रही थी. दिसंबर 2024 तक उनकी कुल संपदा 90,560 करोड़ डालर (रु. 76.66 लाख करोड़) हो गयी. इसमें कुछ पुराने परिवार से चलाने वाले कंग्लोमरेट ग्लोबल मल्टी नेशनल कंपनियों के रूप में परिवर्तित हुए. नयी पीढ़ी के खरबपति सोफ्टवेयर से लेकर माईनिंग तक विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हुए. 2002 में अडानी ग्रुप की संपत्ति मात्र 70 मिलियन डालर थी. वह 2012 तक 20 बिलियन डालरों तक, जून 2024 तक 111 बिलियन डालरों (रु. 9.24 लाख करोड़) तक (अगस्त तक रु. 15.44 लाख करोड़ तक) बढ़ी. 2010 में दो भारत देश के खरबपति – मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल ने विश्व के पांच संपन्नों में जगह बना लिए, जबकि 2022 में विश्व में अत्यंत धनाढ्यों की सूची में रु. 12,45,600 करोड़ों (तत्कालीन डालर मूल्य 80 रु. के हिसाब से 155.7 बिलियन डालर) की शुद्ध संपत्ति के साथ गौतम अंबानी दूसरा स्थान हासिल कर लिया. मुकेश अंबानी के मालिकाना वाली रिलयेंस संस्था ने मार्च 2002 में रु. 41,989 करोड़ बाजार पूंजी लगायी, वह मार्च 2022 तक 20 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के साथ रु. 17,81,841 करोड़ों तक पहुंच गयी. जून 2024 तक अंबानी ग्रुप की संपत्ति 109 बिलियन डालर, अगस्त तक रु. 25.75 लाख करोड़, बजाज ग्रुप की संपत्ति रु. 7.13 लाख करोड़, बिड़ला ग्रुप की संपत्ति रु. 5.39 लाख करोड़ों तक पहुंच गयी. ब्लूमबर्ग खरबपति सूची के मुताबिक जून 2024 तक विश्व के संपन्नों में अंबानी 12वें स्थान एवं अडानी 14वें स्थान पर थे. उसी समय में कांटार ब्रांड्ज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के सबसे 100 ब्रांडों में जगह प्राप्त करने वाले भारत देश के चार कंपनियों में 46वें स्थान पर टाटा कन्सल्टेन्सी सर्वीसेस (TCS) (4,479 करोड़ डालर), 47वें स्थान पर एचडीएफसी बैंक (4,326 करोड़ डालर), 73वें स्थान पर एयरटेल (2,526.3 करोड़ डालर), 74वें स्थान पर इन्फोसिस (2,468.6 करोड़ डालर) थे. इस तरह देश में एक नए सबसे अमीर दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ. देश के प्राकृतिक संसाधनों

एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं को अपनी संपत्ति के रूप में लूटने में सक्षम होने के कारण ही यह वर्ग खरबों संपत्ति हासिल कर पायी.

7. राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के विकास का कदम–कदम पर रोकने वाली साम्राजयवाद एवं दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्गः

राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग एक तरफ साम्राज्यवाद एवं दलाल नौकरशाह पूंजीवाद का दंश झेलते हुए, दूसरी तरफ सामंतवाद से बांधा हुआ है. वह राजनीतिक रूप से कमजोर रहने की वजह से उसे राजसत्ता में भागीदारी नहीं मिलती है. राज्यकोष पर किसी भी तरह का नियंत्रण एवं अधिकार उसे नहीं होता है. उसे साम्राज्यवाद से अपेक्षाकृत कम संबंध होते हैं. साम्राज्यवादियों एवं दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के गठजोड़ उनके बाजार को निरंतर कब्जा करता है. फलतः उनके उद्योगों में वृद्धि सीमित रहती है. रोज–रोज लाखों उद्योग दिवालिया होते हैं. इस तरह वह भारत के नवजनवादी क्रांति के तीनों दुश्मनों से अंतरविरोध रखती है. इसलिए इस क्रांति में चार क्रांतिकारी मित्र वर्गों में से वह एक है.

सत्ता हस्तांतरण से पहले, उसके बाद भी साम्राज्यवादियों, दलाल नौकरशाह पूंजीपति एवं सामंती वर्गों के भीषण हमलों का शिकार हुए वर्गों में यह राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग एक है. यह सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम किस्म के उद्योग, ठेके के अलावा थोक एवं खुदरा व्यापार, परिवहन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र, होटल जैसे व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में उसके निवेश हैं. देश की अर्थव्यवस्था में यह 30 प्रतिशत है. कृषि क्षेत्र के बाद यह 40 प्रतिशत (20 करोड़) लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले क्षेत्र है. कुल 6.33 करोड़ एमएसएमई उद्योगों में सूक्ष्म उद्योग 6.30 (90 प्रतिशत) करोड़ हैं, जबकि छोटे किस्म के उद्योग 3.11 लाख एवं मध्यम किस्म के उद्योग 5 हजार हैं. देश के निजी एवं सरकारी क्षेत्रों इन दोनों ने सूक्षम, छोटे एवं मध्यम किस्म (एमएसएमई) के व्यापारों/उद्योगों की सेवाएं लेते हुए, इन्हें अवैध तरीकें से अपने लिए अनुकूल तरीके से इस्तेमाल करते हुए शोषण व उत्पीड़न कर रहे हैं.

सत्ता हस्तांतरण के बाद देश में सबसे पहले अमल में लायी गयी मिश्रम अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के तहत एक मुख्य क्षेत्र के रूप में सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम किस्म के–एमएसएमई (पहले इसे छोटे किस्म के क्षेत्र कहते थे) क्षेत्र के लिए अचार एवं ताला बनाने से लेकर लकड़ी फर्नीचर तक सैकड़ों उत्पादन आरक्षित किए गए. इसने 'मेड इंन इंडिया' के नाम पर कई उत्पादों को उत्पादन करने में गरीब कारीगरों को सहयोग दिया. यह क्षेत्र विदेशी व स्वदेशी उद्योगों की तीव्र प्रतिस्पर्धा को झेल कर टिक पाया. लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चल

पाया. दलाली सरकारें इस नीति में सेंध लगायी.

वैश्वीकरण के दौर में इस क्षेत्र में कैजुअलीकरण अपना चरम पर पहुंच गया. इस क्षेत्र को सस्ते आयातों की बाढ़ ने डुबो दिया. कुछ वस्तुवों को उत्पादन करने का आरक्षण को रद्द कर इस क्षेत्र को नष्ट किया. इस क्षेत्र में अत्यंत साधारण समस्या एमएसएमई के लिए बकाया राशी सही समय पर भुगतान नहीं करना, जरूरी पूंजी नहीं जुटाना, कच्चे माल नहीं उपलब्ध कराना एवं बहुराष्ट्रीय कार्पोरेट कंपनियां एवं दलाल कार्पोरेट कंपनियां इन उद्योगों को अपनी अनुषंगी कंपनियों के स्तर तक घटाना. फलतः लगभग 80 प्रतिशत एमएसएमई इकाइयां अधिक ब्याज दरों पर निजी व्यापारियों के पास रुण लेना आम बात है. सस्ती श्रमशक्ति से बड़े पैमाने पर बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले इस क्षेत्र को कर्मचारी भविष्य निधि (PF), मेहंगाई भत्ता (DA), बोनस, ईसिस आदि तमाम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित रख कर उन्हें सिर्फ बड़े व्यापारी संस्थाओं, एमएनसी–टीएनसीयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित कर दिए.

अबिद हुस्सेन कमेटी के शिफारिशों के मुताबिक 1997 में इस क्षेत्र के लिए उद्देशित आईसक्रीम, बिस्कट, चावल मिल, दाल मिल आदि 14 मुख्य उत्पादनों को सरकार द्वारा आरक्षण हटा दिया गया. 1999 तक ही 'उदारीकरण' के तहत 3,000 किस्म के विदेशी उत्पादों, निर्यात–आयात (exim) नीति के मुताबिक 8,000 किस्म के विदेशी उत्पादों ने भारत देश के बाजार को डुबो दिया. निर्यात–आयात–2000 नीति के मुताबिक 714 वस्तुओं एवं 2001 में बाकी 715 वस्तुओं के आयात पर पाबंदी हटाने एवं नयी वस्त्र नीति–2000 के मुताबिक इस क्षेत्र के रेडीमेड वस्त्र तैयारी वाले भारी क्षेत्र को आरक्षण से हटाने से इन क्षेत्रों का स्वतंत्र बाजार ध्वस्त हो गया.

इस क्षेत्र में एफडीआई पर अधिकतम सीमा भी 24 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक सरकार ने बढ़ा दिया. इससे विदेशी पूंजी ने रेडीमेड वस्त्र तैयारी उद्योग को कब्जा कर लिया. बड़ी व्यापारी संस्थाओं से आउटसोर्सिंग (उत्पादन एवं सेवा – दोनों क्षेत्रों में) को प्रोत्साहन देते हुए, उसका स्वतंत्र अस्तित्व की समाप्ती की जा रही है. खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी एवं बड़े दलाल पूंजीपति की पूंजी को अनुमति दी गयी. इससे अमेरिका एवं यूरोप के खुदरा व्यापार के भारी संस्थाएं बड़े दलाल पूंजीपतियों से हाथ मिलाकर भारत देश में प्रवेश कर रही हैं. ये लाखों खुदरा व्यापारियों को दिवालिया कर रही हैं. विदेशी फर्नीचर उद्योगों को अनुमति देने के कारण भारत देश के हजारों छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं.

नोटबंदी एवं जीएसटी की वजह से सूक्षम उद्योगों में 40 प्रतिशत दिवालिया होने की स्थिति पैदा हुई. ई–वे बिल नीति ने ट्रांसपोर्टरों को दिवालिया कर दी. नोटबंदी के कारण 50 लाख नौकरी चली गयी. रिजर्व बैंक के आंकड़ें के मुताबिक ही देशभर में 4,86,291 सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम किस्म के उद्योग बंद हो गए. 2015–2023 के बीच 18 लाख एमएसएमई बंद होकर 54 लाख लोग रोजगार खो दिए. उनके मालिकों एवं मजदूर गंभीर कष्ट–तकलीफों का शिकार हुए. प्रवासी मजदूर बेकार हो गए. 2019 में 42.9 प्रतिशत वाले मजदूर सहभागिता दर 2022 में 39 प्रतिशत गिर गया.

करोना महामारी के दौर में मोदी सरकार 'महामारी एवं प्राकृतिक विपदाओं को अवसर के रूप में बदल डालें' के नारे को लेकर एमएसएमई को पुनःपरिभाषित किया. इस क्षेत्र को साम्राज्यवादी कंपनियों एवं दलाली कंपनियों को हवाला कर दिया. इससे ये कार्पोरेट कंपनियां सीधे इस क्षेत्र में घुस रही हैं या वित्त पोषण कर रही हैं.

सरकारी नीतियां बनाने वाले सीआईआई, एफआईसीसीआई, असोचम जैसे सैकड़ों अंगों में दलाल कार्पोरेट कंपनियों को प्रतिनिधित्व है. लेकिन एमएसएमई क्षेत्र को कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं है. रुण जरूरतों को पूरा करने के लिए उद्देशित प्रधानमंत्री रोजगार गैरंटी योजना, मुद्रा, सांप्रदायिक उद्योगों की अक्षय कोष (स्फूर्ति), कायिर बोर्ड योजनाएं, सूक्ष्म एवं छोटे उद्योगों की रुण गैरंटी योजना (CGTMSE), रुण आधारित मूलधन सब्सिडी योजना जैसे कई योजनाएं हैं. इन योजनाओं के लिए सरकारी आवंटन पर्याप्त मात्रा में नहीं है. इस क्षेत्र के मात्र 16 प्रतिशत उद्योगों को ही बैंकों से रुण मिल रहे हैं. तैयारी क्षेत्र में 40 प्रतिशत उत्पादन करने वाले इस क्षेत्र के लिए रुण 2015–2020 के बीच 19 प्रतिशत कम हो गए.

यंत्र सामग्री नहीं होने, जायज दर पर कच्चे माल नहीं मिलने, इनके उत्पादों के लिए बाजार सुविधा नहीं होने, उत्पादन खर्च बढ़कर, उत्पादों के लिए जायज दर नहीं मिलने, देश–विदेशी कार्पोरेट कंपनियों की प्रतिस्पर्धा के कारण इनके उत्पादों के लिए व्यापारिक मांग नहीं होने, बिजली की कमी एवं अधिक बिजली दरें यह क्षेत्र दिवालिया होने के लिए मुख्य कारण हैं. दरअसल इंटरनेशनल फाइनान्स कार्पोरेशन (आईएफसी) के नेतृत्व में 2019 में की गयी एक शोध के मुताबिक एमएसएमई उद्योगों के लिए रु. 16.66 लाख करोड़ रुण जरूरी हैं. भारत देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपति एवं सामंती शासक वर्गों को इस क्षेत्र की जरूरतों एवं उसके लिए जरूरी टेक्नोलोजी उपलब्ध कराने पर ध्यान नहीं है. उनकी साम्राज्यवादी प्रायोजित नीतियों के कारण इस क्षेत्र के लाखों उद्योग

दिवालिया हो रहे हैं. उत्पादक शक्तियां निरंतर ध्वस्त हो रही हैं. इसमें काम करने वाले करोड़ों लोग गरीबी से जूझ रहे हैं. इन तमाम कारणों से एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि दर गिर रहा है. इससे बाजार में मांग एवं जीडीपी वृद्धि दर और सीमित हो रहा है. इन उद्योगों के मालिक के रूप में राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग भी निरंतर धक्का खा रहा है.

८. 'भारत' राष्ट्र एवं देश की 'एकता' व 'समग्रता' के नाम पर देश को राष्ट्रीयताओं का कैदखाना बनाने एवं 'अखंड भारत' के लक्ष्य के पीछे मात्र साम्राज्यवादियों एवं दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के ही हत मौजूद हैं

हमारा देश को ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा कब्जा करने के बाद अपनी साम्राज्यवादी हितों के लिए देश को औपनिवेशिक एवं अर्ध–सामंती देश के रूप में परिवर्तित हुआ. इसके साथ ही देश में राष्ट्रीयताओं पर शोषण, उत्पीड़न, दमन एवं भेदभाव शुरू होकर राष्ट्रीयताओं का सवाल उभर कर आया. इसका मुख्य कारण है साम्राजयवादी वित्तीय पूंजी के साथ देश में बनिया–मारवाड़ी दलाल पूंजीपतियों एवं स्थानीय जमींदारों–सामंतियों का सांठगांठ. यह गठजोड़ देश में पूंजीवादी विकास क्रम एवं समस्त राष्ट्रीयताओं एवं आदिवासियों का सहज विकास एवं राष्ट्रीय राज्यों का गठन करने के क्रम के लिए मुख्य अवरोध बन गया. हिंदू धर्म–पीड़क सांप्रदायिक जातियों के व्यापारिक जातिगत पृष्ठभूमि से आए भारत देश के दलाल पूंजीपति वर्ग में सत्ता हस्तांतरण के पहले से ही देश को आधिकारिक तौर पर हिंदू राज्य के रूप में एवं हिंदू धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में तब्दील करने की भावना है. तब से वे हिंदुत्व विचारधारा को समक्ष रूप से इस्तेमाल करते हुए 'भारत राष्ट्र' की भावना को आगे लाया. बनजिगा (कर्नाटक) जाति के लोग 'राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग' का प्रतीक बन गए. साम्राज्यवादियों के ताबेदार बनने वाले दलाली बनिया, मारवाड़ी एवं पारसीयों की तरह उन्होंने (बनजिगा) 'भारत राष्ट्र' की भावना को प्रतिनिधित्व नहीं किया. ब्रिटिश शासकों ने राष्ट्रीयताओं को टुकड़ों में विभाजित कर विभिन्न प्रांतों (प्रोविन्सों) एवं 'राज्यों' को जोड़ने लायक ''ब्रिटिश इंडिया'' प्रोविन्सों को ''स्थानीय राज्यों'' के रूप में गठित किया गया. उदाहरण के लिए, तेलुगु बोलने वाले लोगों का भूभाग को दो टुकड़ों में विभाजित किया गया. उनमें से एक भाग को मद्रास प्रेसिडेन्सी में (इसमें तेलुगु लोगों के अलावा तमिल, कन्नड़, मलयाली लोग भी थे), दूसरा भाग को हैदराबाद राज्य में (इसमें तेलुगु लोगों के अलावा मराठी, कन्नड़ बोलने वाले लोग भी थे) शामिल किया गया. गुजरातियों को 200 से अधिक बहुत छोटे–छोटे स्थानीय राज्यों में विभाजित किया गया. बंबई प्रेसिडेन्सी में सबसे बड़े मराठा भूभाग के अलावा गुजरातियों को भी

शामिल किया गया. मराठा, गुजराती, बंगाली, ओडिया, तेलुगु, कन्नड़ इस तरह हर एक राष्ट्रीयता और उनके भूभागों को छोटे–छोटे टुकड़ों के रूप में अन्यों से कृत्रित रूप से जोड़ा गया. राष्ट्रीयताओं को विभाजित कर, राष्ट्रीयताओं की एकता और विकास को नष्ट कर अपने शोषण का रास्ता सुगम बनाया.

ब्रिटिश साम्रजयवादियों ने भारत देश के दलाल पूंजीपतियों के साथ हाथ मिलाकर, सामंतवाद को अपने हितों के अनुसार पुनर्गठित कर, उसे अपनी सामाजिक बुनियाद बनाकर देश को लूट लिया. इस क्रूर शोषण के खिलाफ, देश के तमाम इलाकों एवं राष्ट्रीयताओं की जनता औपनिवेशिक दास श्रृंखलाओं को तोड़कर स्वतंत्रता हासिल करने के लक्ष्य से बंगाली, तेलुगु, तमिल, मराठा, कन्नड़, गुजराती आदि राष्ट्रीयताओं के संघर्ष फूट पड़े. मार्क्स ने यह शिक्षा दी कि जब ब्रिटिश औपनिवेशिकवादी आईर्लेंड को कब्जा किया, वहां विकसित होने वाले तमाम किस्म के उद्योगों को ध्वस्त किया, ताबूत बनाने वाले एक मात्र उद्योग ही वहां बच गया, इसलिए अगर आईर्लेंड राष्ट्रीयता का अस्तित्व को बचाना है, तो उस राष्ट्रीयता की जनता को ''स्वयंशासन एवं कृषि क्रांति....'' की जरूरत है. यह हमारा देश को भी लागू होता है. लेकिन भारत देश के दलाल पूंजीपति एवं बड़े सामंती वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस पार्टी ने देश में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम के उभार के प्रति गद्दारी की; राष्ट्रीयताओं के संघर्षों की वादा–खिलाफी की; ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से सांठगांठ होकर सत्ता हस्तांतरण के लिए समझौतें कर लिए.

सत्ता हस्तांतरण के बाद भारत देश के दलाली शासक वर्गों ने 'भारत राष्ट्र' एवं 'अखंड भारत' की भावनाएं फैलाते हुए हमारा देश के मजदूर, किसान आदि श्रमिक जनता के लिए, राष्ट्रीय पूंजीवादी शक्तियों, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीयताओं की एकता और तमाम इलाकों का विकस के लिए मुख्य अवरोध बन गए. भारत देश के संविधान में मौजूद नाम मात्र संघीय सूत्रों का भी कुचलते हुए, आधिपत्य वाले एकिक (unitary) सूत्रों को यथेष्ट लागू किए.

कश्मीर को इंडिया एवं पाकिस्तान दोनों ने कब्जा कर कश्मीर के आत्मनिर्णय अधिकार को कुचल दिया. इसी तरह भारत देश के दलाली शासक वर्ग उत्तर–पूर्व इलाके के मणिपुर, नगालैंड एवं असम भूभागों को वहां की राष्ट्रीयताओं, आदिवासी जनता की इच्छा के विपरीत कब्जा कब्जा किया. देश में भाषा आधारित राज्यों को गठन करने की वादा–खिलाफी की. देश में विभिन्न राष्ट्रीयताओं की जनता बहुत खून बहाने के बाद ही 30 राज्यों का गठन हुआ. पृथक राज्य गठित करने की मांग को लेकर कई जगहों पर आंदोलन अभी भी जारी है.

कांग्रेस सरकार 'मजबूत केंद्र सरकार', 'देश की एकता', 'देश की समग्रता' एवं 'देश की सुरक्षा' के नाम पर निरंकुश शासन चलाया. साम्राज्यवादियों, सीबीबी एवं सामंती वर्गों के हितों को पूरा किया. इसके तहत ही अभी तक कौंसी पार्टियों की सरकारें बनने के बावजूद उनके द्वारा वहीं नीतियां चलायी गयी. भारत देश विभिन्न राष्ट्रीयताओं का आवास नहीं है, भारत देश में एक ही राष्ट्रीयता है, वह है 'हिंदू' राष्ट्रीयता; हिंदू धर्म ही सांस्कृतिक रूप से इस राष्ट्र को एकजुट करती आयी है, इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर भारत देश को एक ही राष्ट्रीयता वाला देश (सिंगल नेशन स्टेट) कहते हुए 'अखंड भारत' की स्थापना करने के लक्ष्य से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) ने राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की. यह दलाली शासक वर्गों की पार्टी के रूप में शुरू से ही इसके अनुसार कार्यरत है. भाजपा मई 2014 में केंद्र में सत्ता में आने के बाद 'वस्तु सेवा कर' (जीएसटी) के नाम पर आर्थिक एकीकरण हासिल करने के तहत समूचा देश में एक ही कर (जीएसटी) नीति को अमल में लायी. 'एक दश–एक कर' नारा दिया. 'एक देश–एक रेशन कार्ड' को नाम के वास्ते ही सही, अमल में लाया. वह 'अखंड भारत' की स्थापना की दिशा में 'एक भारत–श्रेष्ठ भारत' नारे को सामने लाया. वर्तमान में 'एक देश–एक चुनाव' नीति को लाने के लिए तैयारियां कर ली है. अत्यंत प्रतिक्रियावादी एवं पूराने ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी शक्तियों द्वारा 2047 तक हासिल करने के लिए उद्देशित 'नया भारत' (न्यू इंडिया) का मतलब है देश के सभी उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं को कुचलने वाली, भारत देश के संविधन के औपचारिक संघीय स्वभाव को भी खत्म कर, पूरी तरह ऐकिक (unitary) स्वभाव वाली निरंकुश एवं केंद्रीकृत देश के रूप में तब्दील करने के बजाय और कुछ नहीं है. हिंदुत्व फासीवाद का शरण लेने वाली सीबीबी साम्राज्यवादियों के साथ सांठगांठ होकर समूचा देश को एकीकृत बाजार के रूप में तब्दील करने के लिए जल्दबाजी कर रही है.

इसलिए देश में मात्र भाषा आधारित राज्यों की स्थापन के लिए ही विभिन्न राष्ट्रीयताएं लंबे संघर्ष करना पड़ा. लंबे समय तक कश्मीर, नगा, मणिपुर एवं असम राष्ट्रीयताएं भारत देश से अलग होने के अधिकार समेत राष्ट्रीयता के आधार पर स्वयंनिर्णय अधिकार के लिए लड़ रही हैं. ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीयता संबंधी जड़ों पर आधारित होकर देश के कई इलाकों एवं राज्यों में पृथक राज्य गठित करने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, उभर रहे हैं. उत्तर–पूर्व भारत देश की विभिन्न राष्ट्रीयताएं एवं प्रादुर्भाव राष्ट्रीयताएं (आदिवासी कबीले समुदाय) अपनी स्वायत्तता (autonomy) एवं पृथक राज्य गठित करने की मांग कर रही हैं. विभिन्न

राज्यों में प्रांतीय भेदभाव के खिलाफ, प्रांतीय पिछड़ेपन के खिलाफ, राज्यों के अधिकार बढ़ाने, निधियों का आवंटन बढ़ाने एवं अंतरराज्यीय नदी जलों में जायज हिस्से के लिए तथा सीमा विवादों को हल करने के लिए आंदोलन चल रहे हैं.

इन मांगों को हासिल करने के नाम पर विभिन्न राज्यों एवं प्रांतों में कई प्रांतीय पार्टियां गठित होकर, विभिन्न समयों में, विभिन्न स्तरों में आंदोलन चलाया. फिर भी वे ज्यादातर साम्राज्यवादियों, दलाल नौकरशाह बड़े पूंजीपति एवं बड़े सामंती वर्गों के हितों को ही पूरा करने वाली है, इसलिए राष्ट्रीयताओं की जनतांत्रिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पायी. विभिन्न अवसरवादी संशोधनवादी पार्टियां भी वास्तव में राष्ट्रीयताओं के आत्मनिर्णय अधिकार के खिलाफ है. वे मुख्य रूप से साम्राज्यवादियों, दलाल नौकरशाह बड़े पूंजीपति एवं बड़े सामंती वर्गों के हितों को ही पूरा कर रही हैं. कौंसी पार्टी सत्ता में होने के बावजूद, राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों में जनता का खून बहा रही हैं और सघन दमन अभियान चला रही हैं. इन्हें अलगाव आंदोलनों के रूप में दिखा कर, इनके खिलाफ जनता में पूंजीवादी अंध–राष्ट्रवाद एवं ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवाद बहका रही हैं. राष्ट्रीयताओं, प्रादुर्भाव राष्ट्रीयताओं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के बीच अनेकता एवं तनाव/संघर्ष पैदा करते हुए विभाजित करो–राज करो नीति अमल कर रही हैं. साम्राज्यवादी हितों को पूरा करने वाली भारत देश के दलाल शासक वर्गों को उखाड़ फेंक कर, हर राष्ट्रीयता को अलग होने का अधिकार समेत आत्मनिर्णय अधिकार एवं सर्वांगीण विकास हासिल करने के लिए राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों को सर्वहारा पार्टी द्वारा नेतृत्व प्रदान करना आवश्यक है.

९. भारत देश के शासक वर्गों की विस्तारवादीकांक्षा के पीछे मात्र साम्राज्यवादियों एवं ब्राह्मणीय हिंदुत्व–पीड़क जाति आधिपत्य वाले सीबीबी के ही हित मौजूद हैं

ब्रिटिश उपनिवेशवाद हमारा देश को लूटने के क्रम में, हिंदू महासागर इलाके में अपनी आधिपत्य स्थापित करने के लिए हमारा देश को एक रणनीतिक इलाके के रूप में इस्तेमाल किया. इसमें भारत देश के दलाल पूंजीपति वर्ग को मात्र भारत देश में ही नहीं, अफ्रीका एवं एशिया में ब्रिटिश शासन होने वाले कई देशों में भी उनके दलाल के रूप में काम किया. सत्ता हस्तांतरण के बाद भारत देश के दलाली शासक वर्ग अपनी आर्थिक एवं सैनिक शक्ति एवं राजनीतिक प्राबल्य को इस्तेमाल कर दक्षिण एशिया के देशों पर अपना आधिपत्य चला रहे हैं. वे देश की उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के अलावा दक्षिण एशिया के तमाम भूभागों को मिलाकर 'अखंड भारत' स्थापित करने के लक्ष्य से काम कर रहे हैं. वे साम्राज्यवाद के बल पर विस्तारवादीकांक्षा के साथ देश को एक प्रतिघाती दुर्ग के रूप में तब्दील किया,

जिससे दक्षिण एशिया की शांति के लिए खतरा बन हुआ है. भारत देश के शासक वर्गों की विस्तारवादीकांक्षा के पीछे मात्र साम्राज्यवादियों, ब्राह्मणीय हिंदुत्व–पीड़क जाति आधिपत्य वाले सीबीबी के हित के बजाय और कुछ नहीं है.

कुल मिलाकर, इन तीन दशकों में वैश्वीकरण के जरिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी विश्वभर में एक योजना के तहत पिछड़े देशों पर किए जाने वाले हमले गंभीर स्तर पर पहुंच गए. भारत देश के दलाल नौकरशा पूंजीपति एवं सामंती वर्ग साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी पर निर्भर रहने एवं उसके हितों से अपने हित जुड़े रहने की वजह से उससे उनका सांठगांठ अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया. देश में कौंसी सरकार सत्ता में होने के बावजूद साम्राज्यवादियों, दलाल नौकरशाह पूंजीपति एवं सामंती वर्गों के हितों को पूरा करने वाली नीतियां अमल कर रही हैं. देश के बजटों में अधिक हिस्सा एमएनसी एवं भारत देश के सीबीबी कार्पोरेटों के हितों के लिए आवंटित करती आयी हैं. मोदी सरकार पिछली सरकारों से अत्यधिक तेजी से उन्हें अमल कर रही है. तेल, परमाणु इंधन, हथियार एवं युद्ध समग्री के लिए मुख्य रूप से वह आयातों पर निर्भर है. उसके उत्पाद एवं निर्यात साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से किए गए ज्वाइंट वेंचरों से संबंधित हैं और द्वितीय श्रेणी में आती हैं. 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के आपसी विरोधाभासी भावनाओं को बाजू में रखते हुए, जनता को मूर्ख बनाने वाले तमाम प्रचार–प्रसार उन्हें दिग्भ्रमित कर भटकाने का प्रयास के आलाव और कुछ नहीं है. देश में प्रमुख आर्थिक कार्यकलापों के रूप में कनस्ट्रक्शन (निर्माण), मूलबूत सुविधाएं (इनफ्रास्ट्रक्चर), कच्चे माल के लिए खनन (खदान), सोफ्टवेयर, साम्राज्यवादियों की तैयारी वस्तुओं के कलपुरजों का एसेंब्लिंग एवं सेवा कार्यकलाप चल रहे हैं. देश कच्चे माल, कुछ मुख्य कृषि संबंधी श्रम एवं सेवाओं का निर्यात करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में तब्दील हो गया है. देश से बौद्धिक श्रम, कौशल विहीन श्रम, अर्धकौशल वाला श्रम का प्रवास भी अधिक मात्रा में हो रहा है. साम्राज्यवादी देशों से मुख्य रूप से यंत्रों (capital goods), कई किस्म के तैयारी वस्तुओं एवं टेक्नोलोजी का आयात करना जारी है.

सूपर मुनाफें के खोज में विदेशी पूंजी एवं नयी टेक्नोलोजी पर आधारित होकर देश में कई स्टार्टप कंपनियों को स्थापित करने की वजह से नए तौर पर अनेक शक्तियां दलाल नौकरशाह पूंजीपति एवं सामंती वर्गों में शामिल हो गयीं. अपने प्रोजेक्टों के लिए आदिवासी एवं गैर–आदिवासी किसानों एवं शहरी गरीबों को जबरन विस्थापित करना साम्राज्यवादी विकास का नमूना बन गया है. फलतः अर्थव्यवस्था पर अंतरराष्ट्रीय इजारेदार पूंजीवादी संस्थाओं का आधिपत्य, देश के

प्राकृतिक संसाधनों का लूट, उत्पीड़ित जनता की श्रमशक्ति के शोषण, उत्पीड़न, दमन एवं पर्यावरण विध्वंस कई गुणा बढ़ गए हैं. देश की अर्थव्यवस्था विदेशी रुण पूंजी का दलदल में गर्दन भर फंस गयी है. अर्ध–उपनिवेश वाला देश की स्थिति और दूभर हो गयी है. देश की पराधीनता बढ़ी है. चूंकि यह नयी उपनिवेश किस्म का अर्धउपनिवेश देश है, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र संपूर्ण रूप से विकसित होने का मौका नहीं है, अतः मात्र साम्राज्यवादियों एवं दलाली शासक वर्गों के पूंजी, कच्चे माल एवं बाजार जरूरतों के अनुसार ही बदलाव हुए हैं. उनके प्रतिक्रियवादी चरित्र में कोई बदलाव नहीं है.

इस तरह वैश्वीकरण के चरण में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीकों में विभिन्न साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं संस्थाओं के अलावा, उनके साथ विभिन्न स्वरूपों में सांठगांठ होने वाली देशीय दलाल कार्पोरेट कंपनियां लाखों करोड़ रुपये के मुनाफें आर्जित किए/संपदाएं बढ़ायीं. उदाहरण के लिए, मोदी सरकार के पहले पांच वर्ष के शासन में देश के अंदर 20.30 लाख करोड़ रुपये के एफडीआई निवेश आए, जबकि उसी समय में हर वर्ष लगभग 47.09 लाख करोड़ रुपये की देशीय संपदा को साम्राज्यवादी एमएनसीयों ने लूट कर ले गए. इस तरह दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग हमारा देश में साम्राज्यवाद के लिए दासता करने वाले साधन के रूप में बना हुआ है. वह स्वावलंबन की बुनियाद पर देश का औद्योगिकीकरण के खिलाफ है. वह देश को कर्ज के दलदल में फंसाकर साम्राज्यवादियों के मनमानी लूट का आवास बना दिया. इसी क्रम में ही वैश्वीकरण के चरण में भारत देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग साम्राज्यवाद के लिए अत्यंत विश्वसनीय दलाल के रूप में सेवा करते हुए ही स्वयं कई गुणा मजबूत हुआ.

संक्षेप में, सीबीबी को जाति आधारित सामंवाद से अटूट राजनीतिक–सांस्कृतिक बंधन हैं. अपने अस्तित्व के लिए सामाजिक बुनियाद के तौर सामंतवाद को बरकरार रखना जरूरी है. उसका चरित्र के मुताबिक देखा जाय, वह जनतांत्रिक सामाज बनाने के खिलाफ है. विस्तारवादी हितों से सीबीबी को 'अखंड भारत' एवं 'हिंदूराष्ट्र' की स्थापना करने का लक्ष्य मौजूद है. इसमें अपने हित भी होने के कारण साम्राज्यवाद सीबीबी के विस्तारवादी हितों को बढ़ावा देता रहा है. संयुक्त राष्ट्र के तथाकथित शांति संरक्षण दलों में भारत देश के शासकों द्वारा विश्वभर में अनेक देशों में भारत देश के सैन्य बलों एवं अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाने के पीछे साम्राज्यवादियों, विशेषकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के हितों को पूरा करने के अलावा, अपने विस्तारवादी हित भी मौजूद हैं. इसी सिलसिले में ही मोदी के शासन में धारा 370 की समाप्ती, नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) आदि कदम लिए

गए. तद्वारा दलाली शासकों ने 'भारत राष्ट्र' के नारे को एक नीति के रूप में अमल कर रहे हैं. एक तरफ उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं को कुचलते हुए, दूसरी तरफ, इतिहास का तोड़–मरोड़ करते हुए, देश की जनता को 'हिंदुत्व' विचारधारा में डुबो रहे हैं. वे साम्राज्यवादियों के मार्गदर्शन में देश में नाम मात्र संसदीय जनवाद को एक कला तौर पर विकसित करते आए हैं. यह 'जनतंत्र' दरअसल तानाशाह के बगैर और कुछ नहीं है. वर्तमान में आरएसएस–भाजपा मोदी के नेतृत्व में ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी शक्तियां संसद में एवं अधिकतर विधानसभाओं में 'भीड़ का ताकत' हासिल कर, राज्यतंत्र एवं संवैधानिक संस्थाओं का फासिजीकरण कर रही हैं. अपने फासीवादी एजेंडे पर अमल कर रही हैं.

1960 व 70 के दशकों में सीबीबी के हितों के लिए कांग्रेस सरकार एक तरफ बैंकों, बीमा, कोयला, तेल क्षेत्रों की राष्ट्रीयकरण एवं राजाओं के भरण–पोषण की समाप्ति, दूसरी तरफ सार्वजनिक संस्थाओं की वृद्धि से सामंती वर्ग कुछ कमजोर हुई, जबकि सीबीबी विकसित होकर मजबूत हुआ था. भूमि सुधारों के जरिए कुछ जगहों पर सामंती जायदाद (estates) को जब्त करना एवं उनपर आधारित उनके निजी मिल नष्ट हो जाने की वजह से भी सामंती वर्ग कुछ कमजोर हुई थी. एक क्रम में शासक वर्गों के गठजोड़ में सामंती वर्ग से तुलना किया जाय तो, सीबीबी अपना आधिपत्य स्थान एवं नेतृत्व भूमिका को और मजबूत किया है. वैश्वीकरण के दौर में सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योगों के शेयरों को एमएनसी, टीएनएसीयों और सीबीबी के कार्पोरेट कंपनियों के लिए कौड़ियों में बेचे जाने की वजह से विदेशी पूंजी के साथ सीबीबी के एक तबके की पूंजी बढ़ती रही है. सीबीबी ने सामंती वर्ग के साथ अपनी मित्रता को जारी रखते हुए, साम्राज्यवाद के हितों का पूरा करने की तरह अर्धसामंती संबंधों को नए स्वरूपों में जारी रखने की योजनाएं सरकार द्वारा बनाया गया और लागू करवाया गया. इससे सामंती शोषण के तरीकों में बदलाव आए. इससे सीबीबी एवं एमएनसी कंपनियों को ग्रामीण व्यवस्था में घुसपैठ करने में अधिक मदद मिली. अर्धसामंती संबंधों में उल्लेखनीय बदलाव आए. सामंती आधिपत्य के पिछले स्वरूपों के स्थान पर नए स्वरूप सामने आए. गांवों में यह सरकारी व गैरसरकारी 'पार्टी–सहकारी संगठन–पंचायत–पुलिस' प्रशासनों का सांठगांठ होकर व्यापक एवं सामूहिक रूप ले लिया. नयी सामंती शक्तियों के विकास में वित्तीय पूंजी ने महत्वपूर्ण भामिका अदा की. ठेका/कार्पोरेट कृषि का विस्तार हुआ.

सीबीबी अपने हितों को पूरा करने के लिए परिस्थितियों के अनुसार हमेशा बदलता रहा. विशेषकर सीबीबी के हितों के अनुसार दलाली सरकारों ने प्रगतिशील

दिखने वाले आडंबर बदलाव किए. अमेरिका एवं सोवियत संघ (वर्तमान में रूस) के बीच, इन दोनों से अन्य (जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस एवं इटली) साम्राज्यवादी देशों के बीच मौजूद अंतरविरोधों को अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. चीनी सामजिक–साम्राज्यवादियों के साथ भी हमारा देश की दलाली सरकारों एवं सीबीबी के बीच मजबूत संबंध चल रहे हैं.

भारत देश के औद्योगिक क्षेत्र में, निर्यातों, आयातों, व्यापारिक लेन–देन एवं बीमा क्षेत्र में साम्राज्यवादी पूंजी का आधिपत्य चल रहा है. भारत देश के दलाल शासकों द्वारा अमल किए गए विभिन्न औद्योगिक विकास के नमूने बड़े पैमाने पर साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी, तकनीक–टेक्नोलोजी, यंत्र, रुण, स्वीकृत राशी एवं सहायता पर निर्भर होकर, देश का साम्राज्यवादी लूट के अनुरूप, उनके देखरेख में ही बनाए गए. चूंकि भारत देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग व्यापार एवं बैंकिंग पृष्ठभूमि से आया, इसलिए उसे उन पर जितना ध्यान है, उतना ध्यान उत्पादन क्षेत्र पर नहीं है. सत्ता हस्तांतरण से पहले, उनके पूरा विकास सामंती शासकों से मित्रता एवं ब्रिटिश साम्राज्यवादी पूंजी से सांठगांठ एवं उसके हितों अनुरूप, उसके शर्तों पर ही हुआ था. यही कारण है, सत्ता हस्तांतरण के बाद भी, वे साम्राज्यवादी पूंजी पर आधारित पूंजी संचयन नीति का अमल किया. बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत देश में अपनी शाखाएं एवं अनुषंगी संस्थाओं की स्थापना करने के अलावा भारत देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग के साथ सांठगांठ होकर समझौतें कर यहां संयुक्त उद्योग (ज्वाइंट वेंचर) स्थापित करने लगे. साम्राज्यवादी पूंजी एवं भारत देश की बड़ी पूंजी एक दूसरे से लिपटने लगे. टेक्नोलोजी एवं पूंजीगत वस्तु (capital goods) बहुराष्ट्रीय संस्थाओं के हाथ में होने की वजह से इन संयुक्त उद्योगों में भारत देश की पूंजी का हिस्सा कितने होने परे भी, उनपर नियंत्रण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में ही रहता है. इसलिए राष्ट्रवादी औद्योगिकीकरण कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर सामने लाने हेतु भारत देश के सीबीबी के लिए कोई आधार नहीं रह गया. साम्राज्यवादी हितों के अंदर ही सुधारों को लागू कर विदेशी पूंजी एवं टेक्नोलोजी पर निर्भर होने की नीति का अमल किया. इससे विदेशी पूंजी पर निर्भरता, आंतरिक रुण एवं घाटा वित्तापेषण आम बात बन गयी.

साम्राज्यवादी पूंजी पर निर्भर होने की वजह से ''लंपट विकास'' एवं ''वक्रीकृत विकास'' भारत देश में बड़े पैमाने पर हो रहा है. ऐसे विकास से मुख्य रूप से विदेशी साम्राज्यवादी इजारेदार संस्थाओं एवं भारत देश के बड़े नौकरशाह दलाल पूंजीपति वर्ग ही फायदा उठा रहे हैं. यहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित उनकी

शाखाएं, अनुषंगी संस्थाएं, संयुक्त व्यापारों (ज्वाइंट वेंचरों) के अलावा भारत देश के बड़े नौकरशाह दलाल पूंजीपतियों द्वारा स्थापित उद्योगों या सरकारी पूंजी द्वारा स्थापित तमाम उद्योगों ने यंत्र, उपकरण, कलपुरजे एवं औद्योगिक कच्चे माल के लिए साम्राज्यवादी देशों पर ही निर्भर हैं. वे इन्हें अंतरराष्ट्रीय दरों से कहीं अधिक दरों पर बेचने वाले दुकानों के रूप में तब्दील कर दिए. इसलिए इन वस्तुओं के लिए भारत देश के बाजार आंतरिक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि साम्राज्यवादी पूंजी का 'अनुषंगी आंतरिक बाजार' के रूप में तब्दील हो गया. इस 'विकास' ने देश के संसाधनों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर लूटने का रास्ता बनाया. इस 'विकास' से मात्र साम्राज्यवादी देश और भारत देश के दलाल ही फायदा उठा रहे हैं.

साम्राज्यवादी देशों से बड़े पैमाने पर पूंजी इस देश आने के वाहक हैं, भारत देश के बड़े दलाल पूंजीपति वर्ग एवं राज्य. इस वित्तीय पूंजी से मिलाखत होने की वजह से ही साम्राज्यवादी देशों एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (विश्व बैंक एवं आईएमएफ जैसे) से रुण पूंजी देश में प्रवेश कर रहा है. उसने तमाम क्षेत्रों पर अपनी आधिपत्य स्थापित कर देश को रुणों के दलदल में एवं पराधीन स्थिति में धकेल रही है. साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ सौदेबाजी करने में सीबीबी की सीमित शक्ति उन्हें कुछ फायदें पहुंचा सकती है, तब भी वे साम्राज्यवादी मातहत में ही बंधे रहते हैं. बुनियादी तौर पर साम्राज्यवाद पर सीबीबी की निर्भरता ही इसका कारण है. लेकिन इस पराधीरता की वजह से जनता के लिए तो अपार नुकसान होते हैं.

अंतरराष्ट्रीय एवं देशीय राजनीतिक परिणामों पर निर्भर होकर सीबीबी के विस्तारवादी हितों को पूरा करने के तहत ही भारत देश की सरकार ने वर्ष 1973 में सिक्किम को कब्जा कर, उसे देश का हिस्सा बनाया था. पाकिस्तान के साथ दो बार युद्ध किया एवं पाकिस्तान से बंगलदेश को अलग किया. ईलम मुद्दे को हल करने के बहाने भारत देश की सेनाओं को श्रीलंका में भाजा. इस तरह वह दक्षिण एशिया के तमाम देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और षडयंत्र रच रही हैं. वह मात्र दक्षिण एशिया बाजार के लिए ही नहीं, बल्कि साम्राज्यवाद का दासता करते हुए ही एशिया, अफ्रीका एवं लातीन अमेरिका देशों में भी अपनी पूंजी को विस्तार करने की कोशिशें कर रही है. संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा मंडल में स्थायी सदस्यता के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है.

10. सीबीबी के प्रति संशोधनवादियों एवं विभिन्न मा–ले पार्टियों के रुख

भारत देश में कम्युनिस्ट पार्टी ने सैद्धांतिक एवं राजनीतिक रूप से कमजोरी व्यवहार किया था. वह भारत देश के समाज का सही अध्ययन एवं शोध के साथ वर्ग विश्लेषण नहीं करने की वजह से सही रणनीति एवं कार्यनीति अपनाने में अक्षम रही. दुश्मनों एवं मित्रों को अलग कर, दुश्मनों को अलग–थलग करते हुए तमाम मित्रों को मिलाकर, दुश्मनों को हराने की कार्यनीति को सृजनात्मक रूप से विकसित नहीं कर पायी. फलतः उसने सोचा कि भारत देश के बड़े पूंजीपति का वर्ग चरित्र राष्ट्रय स्वभाव वाला चरित्र है. राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष में गोलबंद हुई व्यापक जनता को क्रांतिकारी नेतृत्व देने के बजाय बड़े दलाल पूंजीपति वर्ग का ताबेदार बन गया. क्रांतिकारी नेतृत्व के अभाव में साम्राज्यवादियों एवं भारत देश के बड़े पूंजीपतियों की षड़यत्रों का किसी भी प्रतिरोध नहीं रह गया. 1947 में देश का विभाजन की उनकी साजिश को 'मुस्लिम राष्ट्रीयताएं' के गलत अवधारणा से भाकपा ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया. उसने इस वास्तव को देखने में अक्षम रही कि मुस्लिमों में मात्र मुट्ठीभर बड़े दलाल पूंजीपतियों ने ही पाकिस्तान की मांग कर रही है. सत्ता हस्तांतरण के बाद भी भाकपा ने भारत देश के राज्य का चरित्र सही रूप से समझ नहीं पाया. इसलिए बड़े दलाल पूंजीपति का वर्ग चरित्र एवं उसकी कार्यप्रणाली पर गलत अवधाराणाएं बड़े पैमाने पर व्याप्त थीं.

भाकपा (एम) का रुख के अनुसार मात्र व्यापार पूंजीपति वर्ग ही दलाल हैं. यानी साम्राज्यवादी पूंजीपति वर्ग के लिए कच्चे माल उपलब्ध कराना एवं देशीय बाजार में उनके वस्तुओं को बेचना करते हुए उनके दलालों के रूप में व्यवहार करना ही उनकी जिम्मेदारी है, ऐसी आम समझदारी रखती है. इसका मतलब यह हो गया कि दलालों को राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग से अलग करने में एक मानदंड यह है, विदेशी पूंजी के दलालों के रूप में मात्र व्यापार क्षेत्र में ही शामिल होना, ऐसा देखा जा रहा है. उसने इस तरह औद्योगिक पूंजीपति वर्ग को दलाली वर्ग के रूप में नहीं देख रहा है. भाकपा (एम) ने बतायाः ''यहां इस सच्चाई को मान्यता देनी चाहिए कि आज नया राज्य (भारत देश का संघ) एवं नयी सरकार के नेतृत्व में औद्योगिक बड़े पूंजीपति वर्ग पहला स्थान दखल कर मजबूत शक्ति के रूप में आगे आया है.वह दलाली वर्ग नहीं है'' (Divergent views between our Party and the CPC on certain fundamental issues of program and policy, A resolution passed by Central Committee of CPI (M), A supplimentary of People's Democracy, September 10, 1967). भाकपा (एम) समझती है कि भारत देश के तमाम पूंजीपति वर्ग साम्राज्यवादी दलाल नहीं है, इसलिए वह राष्ट्रीय

एवं जनवादी क्रांति में राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग की क्रांतिकारी भूमिका को चिन्हित करने में विफल रही है, ऐसा स्पष्ट हो जाता है. सत्ता हस्तांतरण के बाद शोषण, उत्पीड़न एवं दमन से परेशान होकर, आक्रोशित व्यापक जनता को क्रांतिकारी नेतृत्व करने में वह अक्षम रही, उल्टे तेलंगाना सशस्त्र किसान संघर्ष का विश्वासघात किया. उसके बाद भाकपा एवं भाकपा (एम) दोनों ने संसदीय लाईन अपनाकर संशोधनवाद एवं नयी संशोधनवाद में फंस गयीं.

मा–ले आंदोलन से संबंधित मा–ले पार्टियों में आम तौर पर दलाल नौकरशाह पूंजीवाद को सरकारी क्षेत्र से बराबर मानने का गलत रुझान है. यह अवधारणा दलाल नौकरशाह पूंजीवाद से संबंधित अवधारणा को उसके विभिन्न स्वरूपों में से एक मात्र स्वरूप तक सीमित करती है. कई मा–ले पार्टियां इस बात से सहमत है कि दूसरी विश्व युद्ध के बाद के समयकाल में नौकरशाह पूंजीपति वर्ग की भूमिका मजबूत हुई. चूंकि साम्राज्यवादी आधिपत्य के परिप्रेक्ष्य में (पूंजी का) प्राथमिक संचयन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य एक मुख्य भूमिका निभाई, इसिलए सीबीबी मजबूत हुई, ऐसा कुछ पार्टियों ने अपना राय दिया. यह दलाल नौकरशाह पूंजीवाद जड़ जमाने से संबंधित पहलू है, ऐसा और कुछ पार्टियों की दलील है. साम्राज्यवादी रुण पूंजी के साथ अर्थव्यवस्था में वृद्धि के अलावा सीबीबी का भी उद्भव हुआ है, ऐसा उनका राय है. विशेषकर, सीआरसी ऐसी दलील को सामने लायी थी. दरअसल, विभिन्न चरणों में उत्पीड़ित देशों के लिए पूंजी का निर्यात विभिन्न स्वरूप ले लिए. कुछ मौकों पर वह प्रत्यक्ष निवेश के रूप में है, और कुछ मौकों पर पोर्टपोलियो निवेश (शेयर आदि निवेश) या रुण, 'सहायता' के रूप में है. इसे देखकर सीआरसी द्वारा नयी उपनिवेशवाद को गुणात्मक रूप से एक नया चरण बताया जाना, साम्राज्यवाद को अपना सामाजिक आधार के रूप में सामंतवाद को संरक्षण देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी सिद्धांत बनाया जाना वस्तुगत वास्तविकता से विरुद्ध है. 'पूंजीवादी विकास', 'साम्राज्यवाद सामंतवाद को उखाड़ देती है' आदि तमाम संशोधनवादी एवं सुधारवादी सिद्धांत मालेमा की अवधारणा से विपरीत है. नय उपनिवेशवाद मात्र सामाज्यवादी आधिपत्य एवं शोषण में एक नया स्वरूप या पद्धति है. इसमें प्रत्यक्ष आधिपत्य एवं शोषण के बजाय, अप्रत्यक्ष शासन, शोषण एवं नियंत्रण होते हैं. उपनिवेशवादी चरण की तरह नयी उपनिवेशवाद में भी साम्राज्यवाद सामंतवाद को परिवर्तित करती है. दलाल नौकरशाह पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाता है. साम्राज्यवाद अधिकाधिम कपटतापूर्ण एवं प्रतिक्रियावादी बन जाती है. वह संशोधनवाद को एक मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है.

कुछ पार्टियां दलालों एवं नौकरशाह पूंजीपतियों को एक ही वर्ग के रूप में समझती हैं. और कुछ पार्टियां उन्हें अलग–अलग वर्गों के रूप में देखती हैं. 1970 में भाकपा (मा–ले) की 8वीं कांग्रेस द्वारा पारित पार्टी कार्यक्रम में विशेषकर सरकारी क्षेत्र को दलाल नौकरशाह पूंजीवाद के रूप में बताने को लेकर कुछ लोग इस स्वरूप के पूंजीवाद मात्र सरकारी क्षेत्र को ही लागू है, ऐसा समझ बनाया. दरअसल, औद्योगिक क्षेत्र के बड़े निजी एवं सरकारी क्षेत्र दोनों और तथाकथित 'आधुनिक' दिखने वाले बड़े सामंती वर्ग भी नौकरशाह पूंजीवाद की अवधारण की दायरे में आते हैं.

इसी तरह नौकरशाह पूंजीवाद के बारे में माओवादी अवधारणा का अनुप्रयोग करने में, अर्धसामंती संबंधों में हुई परिवर्तनों के स्वभाव को विश्लेषण करने एवं समझने में अधिक जटिलता है. 1970 के पार्टी कार्यक्रम भारत देश में 'पूंजीवाद का विकास' को समझने में विफल हुआ, ऐसा कहते हुए मार्क्सवादी–लेनिनवादी खेमे की कुछ पार्टियां प्रायः ''वक्रीकृत पूंजीवाद'' की अवधारणा को इस्तेमाल कर रही हैं. यह एक निश्चित प्रकार की पूंजीवाद है, इसे बताने के लिए ''वक्रीकृत'' का शब्द प्रायः इस्तेमाल कर रही हैं. यहां बताए जाने वाले पूंजीवादी संबंधों को मात्र ''वक्रीकृत'' शब्द को ही इस्तेमाल करना उतना ठीक नहीं होगा. ये संबंध पूंजीवादी (साम्राज्यवादी) देशों के संबंधों से गुणात्मक रूप से अलग है. इस समस्या में 'वक्रीकरण' का स्वभाव पर एक टिप्पणी अवश्य देनी पड़ेगी. इन संबंधों के बारे में साम्राज्यवाद का दासता करने संबंधित मात्र एक ही पहलू को 'वक्रीकरण' शब्द में व्यक्त होता है. माआने ने इस तरह परिभाषित किया कि वह ''देशीय सामंती वर्ग और पूराने प्रकार के धनी किसानों के साथ भी नजदीकी से जुड़ा रहता है''. माओ के सूत्रीकरण में, नौकरशाह पूंजीवाद का मतलब ''दलाली, सामंती, राज्य–इजारेदार पूंजीवाद ही है''. साम्राज्यवाद, सामंतवाद एवं राज्य – इन तीनों के बीच संबंध पर अवश्य ध्यान देना है. इसके विपरीत मात्र ''वक्रीकृत पूंजीवाद'' का सूत्रीकरण मूल बात को छिपाती है. वैज्ञानिक रूप से माओ द्वारा सूत्रबद्ध 'दलाल नौकरशाह पूंजीवाद' का सिद्धांत एवं परिभाषा को ही हमें बार बार दुहराना चाहिए. 'वक्रीकृत पूंजीवाद' के बारे में बाकी मा–ले पार्टियों की टिप्पणी और हमारी टिप्पणी के बीच अंतर है. हमारी टिप्पणी के मुताबिक वक्रीकृत पूंजीवाद का मतलब मात्र दलाल नौकरशाह पूंजीवाद ही है. दलाल नौकरशाह पूंजीवाद की अवधारणा से विपरीत 'वक्रीकृत पूंजीवाद' पर टिप्पणी देना राजनीतिक गलती की ओर ले जाती है.

साम्राज्यवादी युग में औपनिवेशिक एवं अर्ध–औपनिवेशिक देशों द्वारा सामना की

जाने वाली इस तरह के विशेष समस्याओं को पहली बार मार्क्सवादी महान शिक्षक कामरेड माओ ने सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक रूप से सफलतापूर्वक हल किया था. उन्होंने इस तरह बतायाः ''एक दलाल का असली अर्थ है, एक विदेशी व्यापारी संस्था में काम करने वाले चीनी प्रबंधक या कर्मचारी. दलालों ने विदेशी आर्थिक हितों को संरक्षित करते हुए साम्राज्यवाद और विदेशी पूंजी के साथ नजदीकी संबंध रखते हैं'' (माओ त्से तुङ, चयनित ग्रंथों से पहला ग्रंथ, ''चीनी समाज में वर्गों का विश्लेषण'' नामक निबंध के अंत में दिया गया विवरण से).

एक औपनिवेशिक या अर्धऔपनिवेशिक देश के पूंजीपति वर्ग के बारे में कामरेड माओ ने इस तरह बताया, ''साम्राज्यवादी देशों के पूंजीपतियों द्वारा पले–बढ़े और उनके हितों को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करने वाला वर्ग हैः ग्रामीण इलाकों के सामंती शक्तियों से उसे बहुत नजदीकी संबंध होते हैं'' (चीनी क्रांति और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी).

यानी एक औपनिवेशिक या अर्ध–औपनिवेशिक देश के पूंजीपति वर्ग, वह व्यापार पूंजीपति वर्ग हो या औद्योगिक पूंजीपति वर्ग हो, साम्राज्यवादी पूंजी को प्रत्यक्ष रूप से दासता करने हुए, स्वदेश के खिलाफ साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण एवं उत्पीड़नों को गहरा करने में सहयोग देना वाला वर्ग है, वह है दलाली पूंजीपति वर्ग.

कामरेड माओ की शिक्षाओं पर आधारित होकर, 1969 में ही भाकपा (मा–ले) एवं एमसीसी पार्टियों ने इस सूत्रीकरण को चिन्हित कर लिया कि भारत देश की ठोस अर्ध–औपनिवेशिक एवं अर्ध–सामंती सामाजिक परिस्थितियों में भारत देश के पूंजीपति वर्ग में दलाली चरित्र निहित है. 1970 में संपन्न भाकपा (मा–ले) की 8वीं कांग्रेस द्वारा पारित पार्टी कार्यक्रम एवं संविधान में एवं एमसीसी पार्टी की रणनीति एवं कार्यनीति में भी उक्त सूत्रीकरण को शामिल किया गया. इनके मुताबिक भारत देश के पूंजीपति वर्ग में दो तबके मौजूद हैं – एक है, विदेशी पूंजी का दलाली करते हुए, विदेशी पूंजी के हितों के साथ अपने हित जुड़े हुए बड़े दलाल पूंजीपति वर्ग. दूसरा है, भारत देश की अर्धव्यवस्था की स्वतंत्र विकास चाहने वाले राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग. चूंकि 15 अगस्त, 1947 के सत्ता हस्तांतरण के साथ यह दलाल पूंजी का राज्य पूंजी के साथ मेलमिलाप हो गया, इस तरह बड़े दलाल पूंजीपति वर्ग दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग के रूप में उद्भव हुआ. यह वर्ग बड़े सामंती वर्ग के साथ मिलकर राजसत्ता दखल करने के बाद भारत देश अर्ध–औपनिवेशिक एवं अर्ध–सामंती अर्थव्यवस्था बन गयी.

उक्त तीन चरणों में दलाल नौकरशाह पूंजीपति (सीबीबी) वर्ग के बारे में पड़ताल

किए गए विषयों का सारांश निकालने के लिए हम साम्राज्यवाद से शुरू करना पड़ेगा. क्योंकि, वह साम्राज्यवाद का संरक्षण में ही पला—बढ़ा और उसकी वृद्धि हुई है. साम्राज्यवाद के बगैर उसका अस्तित्व नहीं है. दलाल नौकरशाह पूंजीवाद का विकास में कृषि, उद्योग, व्यापार के अलावा बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कम्युनिकेशन्स जैसे सेवा क्षेत्र मुख्य क्षेत्र बन गए हैं. 1960 दशक के अंत एवं 1970 दशक की शरूआत में अमेरिकी साम्राज्यवाद ने पिछड़े देशों की सरकारों को तीन प्रतिघाती कर्तव्य निर्देशित कियाः 1. नौकरशाही पूंजीवाद का विकास; 2. सामंती दलाल नौकरशाही राज्य का पुनर्गठन; 3. क्रांति को कुचलना. वे सरकारें साम्राज्यवादी जरूरतों के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया दीं. ठीक वे ही कर्तव्य एलआईसी नीति बनाने में मदद कीं. विश्व में, विशेषकर उत्पीड़ित देशों में क्या हो रहा है, इसके बारे में ऐतिहासिक दृष्टि प्राप्त करने एवं समझने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है. पिछड़े देशों में विकसित हो रहा 'पूंजीवाद' आर्थिक विकास का व्यक्तीकरण नहीं है. वह साम्राज्यवाद के अधीन होने वाला पूंजीवाद है. बाजारों के लिए संघर्ष करने वाले साम्राज्यवादियों की जरूरत को पूरा करता है. पिछड़े देशों में पराधीन औद्योगिकीकरण को बढ़ाने, तद्वारा उन (नौकरशाह पूंजीवाद) के हितों को पूरा करने, विशेषकर सस्ते में पूंजी वस्तुओं के उद्योगों को स्थापित करने एवं विकसित करने में इससे मदद मिलती है. अमेरिकी साम्राज्यवादी संकट इसे प्रेरित करता है. तमाम अंतरविरोधों को तीखा बनाता है.

चूंकि दूसरा विश्व युद्ध में अमेरिकी साम्राज्यवाद एक महाशक्ति के रूप में उद्भव हुआ, इसलिए वह पिछड़े देशों के ग्रामीण इलाकों में अपनी पूंजी की घुसपैठ के अनुरूप विभिन्न पिछड़े देशों की ठोस परिस्थितियों के मुताबिक सामंतवाद को बदल दिया. विशेषकर भारत देश जैसे देशों में 'हरित क्रांति' को आरंभ किया. अधिक मुनाफें प्राप्त करने के लिए अपने 'तकीनीशियनों' को भेजा. कृषि कानूनों को सामने लाया. इन्ही को 'कृषि सुधार कार्यक्रम' कहलाए गए. ये सुधार सामंतवाद को मात्र साम्राज्यवाद एवं सीबीबी के अनुकूल तराशने के लिए ही लाए गए, इसके अलावा और कुछ नहीं. इसलिए नए स्वरूपों में जमीन समस्या सामने आयी. इससे किसान जनता पर शोषण एवं उत्पीड़न दोगुणा हो गए. भारत देश के मजदूर, किसान, अन्य श्रमिक जनसमुदाय को लूट कर आर्जित पूंजी, उत्पादक साधन एवं श्रमशक्ति साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी, सीबीबी एवं सामंतवादियों के हाथों में पूंजी के रूप में संचित हो रहे हैं. इसी वजह से मध्यम वर्ग (निम्न पूंजीपति) के लोग, छोटे व मध्य स्तर के पूंजीपति वर्ग (राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग) के हाथों में पूंजी संचित नहीं हो रही है. व्यापक गरीब जनता सबकुछ खो जा रही

है, रोजगार के लिए कचाकच भरे हुए शहरों में दूभर जिंदगियां जी रही है. साम्राज्यवादी पूंजी के जरिए उत्पीड़ित देशों में 'वृद्धि' ने पिछड़ेपन, उत्पीड़न एवं हिंसा को और अधिक कर देती है. इसलिए नवजनवादी क्रांति चलाने में दलाल नौकरशाह पूंजीवाद को समझना बहुत ही आवश्यक है. चूंकि हम मालेमा की रोशनी में चलते हैं, इसलिए नौकरशाह पूंजीवाद के बारे में चर्चा करने के लिए हमने साम्राज्यवाद के प्रधान आर्थिक लक्षणों से शुरू करते हैं – इजारेदार, पराश्रयी एवं मरणावस्था में चटपटा रही पूंजीवाद. जैसाकि लेनिन ने कहा 'साम्राज्यवाद का बहुत ही गहरी आर्थिक बुनियाद है इजारेदार'. वित्तीय पूंजी ने इसे सृजन करता है.

हमारा देश साम्राज्यवादी जंजीरों से अर्ध–सामंतवाद एवं दलाल नौकरशाह पूंजीवाद के उत्पीड़न झेलने वाला देश है. आज भी दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों एवं सामंतीयों का गठजोड़ हमारा देश के शासक वर्ग हैं. अर्ध–सामंतवाद में जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिणाम होते रहे हैं, इन्हीं की वजह से मध्ययुग के काल तक एक दूसरे से लिपटे गए जाति एवं वर्ग के बीच अंतर बढ़ते गए, फिर भी प्रधानतया सांप्रदायिक व्यापारी जातियों – बनिया एवं मारवाड़ियों से ही सीबीबी का विकास हुआ. सीबीबी ने अपने प्रांतीय वं अन्य राष्ट्रीय अस्तित्वों में भी जाति पर लिपटा रहा है. इससे यह स्पष्ट होता है कि औद्योगिक क्षेत्र पर पीड़क जाति के दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग का इजारेदार कायम है. लेकिन पूंजी का संचयन क्रम तेज होते ही दलाल पूंजीपति वर्ग के बीच जाति, राष्ट्रीयता, प्रांत आदि विभाजन रेखाएं क्रमशः मिट जा रही हैं, ऐसा दिखा रहा है, चूंकि, अर्ध–औपनिवेशिक एवं अर्ध–सामंती बुनियाद एवं ऊपरी ढांचा में ये मजबूती से गाड़े हुए हैं, इसलिए इस व्यवस्था को मौलिक रूप से परिवर्तित करने के बगैर, सारांश में ऐसा बदलाव होने का संभावना नहीं है.

दलाल नौकरशाह पूंजीवाद मात्र साम्राज्यवाद एवं बड़े पूंजीपतियों से संबंधित मामला नहीं है. वह बड़े सामंतियों को भी सेवा करती है. उक्त तमाम तीनों चरणों में विदेशी पूंजी के लिए स्वदेशी बिचौली के रूप में काम करने का उसका दलाली चरित्र में कोई बदलाव नहीं है. देश की सामाजिक व्यवस्था में कई राजनीतिक एवं आर्थिक बदलाव आने के बावजूद, वह साम्राज्यवादी पूंजी का दासता करते हुए, उसे देश में घुसपैठ करने एवं मजबूत होने का प्रधान साधन के रूप में सीबीबी की भूमिका पहले ही जैसा जारी है. सीबीबी अपने हितों के लिए जब पुराने मालिक अनुकूल नहीं होता है, तब नया मालिक को दासता करने के लिए तैयार हो जाता है. यह साम्राज्यवाद के अधीन ही, उसका दासता करने के ढांचे में ही होता है.

उक्त तीनों चरणों में यह दिखायी देता है कि साम्राज्यवाद भारत देश में अपनी जरूरतों के अनुसार निरंतर अर्ध–सामंतवाद में कुछ बदलाव करती रही है और दलाल नौकरशाह पूंजीवाद की वृद्धि करती रही है. वह सत्ता हस्तांतरण के बाद अपने नयी–उपनिवेशवादी अप्रत्यक्ष शासन को दलाल नौकरशाह पूंजीपति एवं सामंती वर्गों के जरिए चलाता रहा है. यह बदलाव पूंजीवाद द्वारा सामंतवाद का स्थान लेने से नहीं हुआ. वह दोनों को एक दूसरे से लपेट लिया है. इसलिए भारत देश के जाति आधारित सामंतवाद के प्ररिप्रेक्ष्य में दलाल नौकरशाह पूंजीवाद द्वारा अर्ध–सामंती संबंधों को जिस तरह से परिभाषित किया जाता है, उसी तरह उन अर्ध–सामंती संबंधों द्वारा दलाल नौकरशाह पूंजीवाद को पहचान किया जाता है. उद्योग एवं वैचारिक क्षेत्र, ये दोनों ही क्षेत्रों में यह सच है. सामंतवादी वर्ग एवं दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग से बने शासक वर्ग के गठजोड़ में दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों ने ही नेतृत्व (लीडिंग रोल) में हैं. यह नेतृत्व की भूमिका उसका मूल लक्षण है. यह नेतृत्व की भूमिका उसे अपनी बलबूते से प्राप्त नहीं हुई. जाति आधारित सामंतवाद अपनी नेतृत्व भूमिका को उपनिवेशवादी मजबूतीकरण के कारण खो दिया. उस पर नौकरशाह पूंजीवाद नहीं, बल्कि साम्राज्यवाद का आधिपत्य होता है. हालांकि एक विशेष वर्ग के रूप में दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग को अपने ही विशेष हित हैं. इसलिए उसे कुछ अवसरों पर किसी न किसी साम्राज्यवादी देशों के साथ अंतरविरोध पैदा हो सकते हैं. लेकिन कुल मिलाकर, वह साम्राज्यवाद के बगैर स्वतंत्र रूप से अपना व्यवहार नहीं कर सकता. दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग की नेतृत्व भूमिका से शासक वर्गों के गठजोड़ एवं नीति निर्णयों में उसे असीमित अधिकार या सुविधाएं नहीं मिलेंगे. अंततः साम्राज्यवाद ही उन्हें तय करता है. साम्राज्यवाद के लिए अर्ध–सामंती एवं दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्गों दोनों की जरूरत है. इसलिए दलाल नौकरशाह पूंजीवाद को आगे ले जाने की दिशा में सरकार (राज्य) द्वारा लिए जाने वाले हर कदम में साम्राज्यवादी जरूरतों के अनुरूप ही सीबीबी एवं अर्ध–सामंतीयों के बहुल हित निहित होते हैं.

1920 में लेनिन ने ''साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा एक क्रमबद्ध तरीके से किए जाने वाले विश्वासघात'' के बारे में चेतावनी दी थी. ''साम्राज्यवादी शक्तियां राजनीतिक रूप से स्वतंत्र राज्यों के परदे में आर्थिक, वित्तीय एवं सैनिक रूप से पूरी तरह उन पर निर्भर होने वाले राज्यों को स्थापित करती हैं''. जैसाकि लेनिन ने बताया, ऐसी निर्भरता का ही एक स्वरूप है अर्ध–उपनिवेश.

लेनिन एवं माओ की शिक्षाओं की रोशनी में हमें उक्त तीन चरणों के संश्लेषण के रूप में इस तरह वर्णन कर सकते हैं. पहला – एक अर्ध–उपनिवेश एवं

औपचारिक स्वतंत्र राज्य – लेकिन वास्तव में उसने आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक रूप से साम्राज्यवादी शक्तियों पर निर्भर होता है. चूंकि विश्व पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था में अर्ध–उपनिवेश देश एक हिस्सा है, इसलिए उसके शासक वर्ग इस निर्भरता से छुटकारा नहीं पा सकते. क्योंकि वे मात्र साम्राज्यवादी इजारेदार पूंजी का दासता करने द्वारा ही अस्तित्व में रह सकते हैं, विकास कर सकते हैं. दूसरा – अर्ध–उपनिवेश देश एक मात्र साम्राज्यवादी शक्ति के अधीन में नहीं होता है. वह ऐसी युद्ध क्षेत्र है, जिसपर आधिपत्य के लिए एक से अधिक साम्राज्यवादी शक्तियां होड़ में लगी रहती हैं. इसने देश के शासक वर्गों को उन साम्राज्यवादी शक्यों के बीच सौदेबाजी करने के लिए कुछ हद तक अवसर प्रदान कर सकता है. इसलिए ऐसा दिखयी देता है कि वे स्वतंत्र हैं, लेकिन ऊपर से दिखने वाला चीज को वास्तव के साथ उलझना नहीं चाहिए. तीसरा – एक अर्ध–उपनिवेश पर विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियों के नियंत्रण का स्तर उनकी ताकत, घुसपैठ एवं अन्य वस्तुगत परिस्थितियों के मुताबिक होगा. चूंकि विभिन्न चरणों में वस्तुगत परिस्थितियों में अंतर होंगे, इसलिए साम्राज्यवादी शक्तियों के नियंत्रण स्तर भी निरंतर एक ही तरह नहीं होगा. जब कई साम्राज्यवादी शक्तियां होड़ में लगी रहती हैं, एक चरण में उनमें से एक शक्ति को अधिक नियंत्रण हो सकता है और अगला चरण में दूसरी शक्ति अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सकता है.

हमारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी द्वारा बनायी गयी एमओपी दस्तावेज (2020) ने बताया कि *'दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग हमारा देश में साम्राज्यवाद का दासता करने वाला एक साधन के रूप में है'* (पृष्ठ 234 एवं 243 में). हालांकि यह स्पष्ट है कि भारत देश के शासक वर्गों में दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग ने नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए साम्राज्यवाद निर्देशित आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों को लागू करते हुए जंगलों का कार्पोरेटीकरण, कृषि क्षेत्र का कार्पोरेटीकरण एवं तमाम क्षेत्रों का कार्पोरेटीकरण कर रहा है, इसलिए दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग एवं देश के व्यापक जन समुदायों के बीच अंतरविरोध वैश्वीकरण के चरण में तेज होता जा रहा है. इन पूरे विषयों को लेकर सीबीबी एवं भारत देश की जनता के बीच अंतरविरोध को प्रमुख एवं मौलिक अंतरविरोधों में शामिल करने की अत्यंत आवश्यकता सामने आयी है. इसलिए *दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग हमारा देश में साम्राज्यवाद का दासता करने वाला एक प्रधान साधन* (**principle vehicle**) *के रूप में है* – ऐसा बताना ठीक होगा. दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग एवं भारत देश की जनता के बीच अंतरविरोध निम्नांकित दोनों अंतरविरोधों में – साम्राज्यवाद और भारत देश की जनता के बीच का अन्तरविरोध और पूंजी और श्रम के बीच

का अन्तरविरोध – ही निहित है, ऐसा बताना से स्पष्टता नहीं मिलेगी. भारत देश के शासक वर्गों के गठजोड़ को नेतृत्व करने वाले दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग का महत्व के बारे में एवं जनता के हितों को साम्राज्यवादियों के लिए बेचते हुए देश की पुरोगति में अवरोध बनकर, उसके द्वारा निभाई जाने वाली अत्यंत विश्वासघाती भूमिका के बारे में वर्णन करने के लिए वह काफी नहीं है. भारत देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग में विस्तारवादी चरित्र निहित है. उसने साम्राज्यवाद से शरीक होकर भारत देश की राष्ट्रीयताओं के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त दक्षिण एशिया प्रांत की जनता को प्रत्यक्ष रूप से उत्पीड़ित करने वाले लुटरा है. उसके खिलाफ देश और दक्षिण एशिया प्रांत में भी उत्पीड़ित जनता पहले से ही कई आंदोलन किए और कर रहे हैं. इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत देश के दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग साम्राज्यवाद के अधीन होने के बावजूद, वह एक अलग वर्ग के रूप में अस्तित्व में है, उसने मात्र साम्राज्यवाद का कटपुतली नहीं है, वह साम्राज्यवाद का दासता करते हुए ही अपनी वर्ग के हितों को भी पूरा कर रहा है.

यही वर्ग विशाल अर्ध–सामंती सामाजिक बुनियाद को इस्तेमाल कर जनता को बंधनों में रखता है व अपना आधिपत्य जारी रखता है. ऐसा साबित हो चुका है कि ये देशद्रोही हैं, विघटनकारी हैं, जनता के प्रति क्रूर दुश्मन हैं. ये वंचक हैं, झूठ बोलने वाले हैं, भ्रष्ट हैं व विश्वासघातक हैं, जनता की हत्याकांड–नरसंहार करते हैं, लैंगिक अत्याचार करते हैं. भारत देश की संसदीय व्यवस्था साम्राज्यवादियों, सीबीबी एवं बड़े सामंती वर्गों के शोषण, शासन एवं नियंत्रण के लिए एक साधन है. यह झूठा लोकतंत्र है. संशोधनवादी एवं नयी संशोधनवादी पार्टियां उनके सेवक के अलावा और कुछ नहीं है.

सीबीबी साम्राज्यवादी पूंजी के लिए प्रधान वाहक है और राज्य में सीबीबी एवं सामंती गठजोड़ में वह नेतृत्व भूमिका अदा कर रहा है, ऐसा बताने से भारत देश का अर्ध–औपरिवेशिक एवं अर्ध–सामंती चरित्र में बदलाव नहीं होगा. अभी भी वह मुख्य रूप से कृषि आधारित देश है, इसलिए सामंतवाद एवं व्यापक जनसमुदायों के बीच अंतरविरोध प्रधान अंतरविरोध के रूप में बना रहेगा. सशस्त्र कृषि क्रांति को आगे बढ़ाना ही इस चरण में केंद्रीय कर्तव्य के रूप में रहेगा. इसके अलावा, इसे आगे बढ़ाते हुए ही, सीबीबी विरोधी एवं साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों का भी निर्माण करना होगा एवं जारी रखना होगा. सामंत विरोधी संघर्ष से साम्राज्यवाद विरोधी आंदोल विकसित होता है, ऐसा सोचना या सामंत विरोधी संघर्ष एक स्तर तक विकसित होने के बाद उसे संचालित करना है, ऐसा बताना गलत होगा.

इसलिए इस अर्ध–औपनिवेशिक एवं अर्ध–सामंती व्यवस्था में साम्राज्यवाद को निशाना बनाते हुए चलायी जाने वाली क्रांति राष्ट्रीय क्रांति के रूप में, अर्ध–सामंतवाद को निशाना बनाते हुए चलायी जाने वाली क्रांति जनवादी क्रांति के रूप में होगी. चूंकि तीनों पहाड़ों – साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद एवं सामंतवाद भारत देश की व्यापक जनता के निशानें पर हैं, इसलिए साम्राज्यवाद विरोधी, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद विरोधी एवं सामंत विरोधी वर्ग संघर्षों को संचालित करते हुए हमारा देश में क्रांति को आगे बढ़ाना होगा. जाति आधारित सामंतवाद में औद्योगिक एवं व्यापार हितों की वृद्धि होना या कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की घुसपैठ सामंत विरोधी संघर्ष को किसी भी तरह से कमजोर करने का सूचक नहीं है. किसी भी तरह से वह सशस्त्र कृषि क्रांति के केंद्रीय कर्तव्य को स्थानांतरित करने का सूचक नहीं है. इसलिए सामंतवाद एवं व्यापक जन समुदायों के बीच अंतरविरोध ही प्रधान अंतरविरोध के रूप में जारी रहेगा. लेकिन उक्त बदलावों से अवश्य यह प्रकट होता है कि कृषि क्रांति में नए पहलुओं का उद्भव हुआ है. कृषि में दलाल नौकरशाह पूंजीवाद के ठोस स्वरूपों एवं जाति आधारित सामंती संबंधों के ठोस व्यक्तीकरणों को पहचान कर, उनके खिलाफ ठोस संघर्ष एवं सांगठनिक स्वरूप अपनाना आवश्यक है.

1970 में संपन्न हमारी पार्टी की 8वीं कांग्रेस ने भारत देश के उत्पादन संबंधों एवं वर्ग संबंधों को मौलिक रूप से सटीक विश्लेषण कर, उनके आधार पर भारत देश के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए मौलिक रूप से सही क्रांतिकारी लाईन/आम लाईन (basic revolutionary line/general line) तय की थी. उसके आधार पर ही हमने भारत देश की क्रांति को आज की स्थिति तक विकसित किए हैं. हालांकि वह दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग (सीबीबी) को एक सुस्पष्ट अस्तित्व रखने वाला वर्ग (distinct class) के रूप में पहचान नहीं किया. इससे 1970 से आज तक हमने दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग एवं व्यापक जनता के बीच मौजूद अंतरविरोध को एक प्रमुख अंतरविरोध के रूप में हो या मौलिक अंतरविरोध के रूप में पहचान नहीं किया. यह अंतरविरोध साम्राज्यवाद और भारत देश की जनता के बीच का अन्तरविरोध और पूंजी और श्रम के बीच का अन्तरविरोध में ही निहित होते हैं, ऐसी समझदारी हमारे अंदर जारी रही. फलतः एक तरफ सीबीबी के सुस्पष्ट अस्तित्व का इंकार करते हुए, दूसरी तरफ निशाने बनाने वाले लक्ष्यों में से उसे एक लक्ष्य के रूप में बताते रहे हैं. यह परस्पर विरोधाभास है. भारत देश के उत्पादन संबंधों के मुताबिक देखा जाए, औद्योगिक, सेवा एवं कृषि क्षेत्रों के अपार

उत्पादन साधनों पर सीबीबी के पास मालिकाना/अधिकार है. इस आधार पर वह भारत देश की श्रमजीवियों के साथ उत्पादन करवा रहा है, उत्पादित वस्तुओं को दखल कर रहा है. इस क्रम में वह साम्राज्यवादी पूंजी के लिए प्रधान वाहक एवं सेवक के रूप में रहा है. इसलिए हम कहते हैं कि वह स्वतंत्र नहीं है. स्वतंत्र नहीं होना अलग बात है, सुस्पष्ट वर्ग के रूप में अस्तित्व में रहना अलग बात है. हमारा देश के औद्योगिक व सेवा क्षेत्रों में एवं कृषि क्षेत्र के कुछ उद्योगों में, कुछ यूनिटों, कुछ कृषि क्षेत्रों में, कुछ बागानों में साम्राज्यवादी, एमएनसी–टीएनसीयों की पूंजी 20 से 100 प्रतिशत होने के बावजूद, कुछ कंपनियों में सीबीबी की पूंजी भी 20 से 100 प्रतिशत तक है. इनके आधार पर सीबीबी एक स्वतंत्र वर्ग नहीं है, ऐसा कहते हुए ही, वह सुस्पष्ट अस्तित्व होने वाला वर्ग के रूप में भी बताना जरूरी है.

औपनिवेशिक, अर्ध–औपनिवेशिक, नया औपनिवेशिक एवं अर्ध–सामंती देशों में सामंती वर्ग भी साम्राज्यवाद के अधीन ही रहता है. वह भी साम्राजयवादी पूंजी का वाहक एवं सेवक है. लेकिन सामंती वर्ग को हमने एक सुस्पष्ट वर्ग के रूप में पहचान लिए हैं और उसे क्रांति के एक लक्ष्य के रूप में शामिल किए हैं. जैसाकि सामंती वर्ग स्वतंत्र नहीं होने के बावजूद, उसे सुस्पष्ट वर्ग के रूप में पहचान लिए हैं, वैसा ही सीबीबी को भी सुस्पष्ट वर्ग के रूप में पहचानना आवश्यक है.

सीबीबी मामले में माओ द्वारा शिक्षित बुनियादी सिद्धांत को भारत देश की क्रांति से सृजनात्मक रूप से अनुप्रयोग करने में हमारे अंदर अस्पष्टता, यांत्रिकता एवं रूढ़ीवाद चलते रहे हैं. फलतः राजनीतिक क्षेत्र में सीबीबी के खिलाफ राष्ट्रीय पूंजीपति समेत बाकी उत्पीड़ित वर्गों को मिलाकर रणनीतिक एवं कार्यनीतिक संयुक्त मोर्चा के मंचों को गठित करने का राजनीतिक कार्य पर ध्यान नहीं देने की स्थिति एवं लंबे समय से राजनीतिक गलती करने की स्थिति पैदा हुई. इस वजह से सामंतवाद एवं व्यापक जनता के बीच अंतरविरोध को प्रधान अंतरविरोध कहते हुए भी उसे यांत्रिक रूप से समझ लिए, प्रधान रूप से किसान जनता एवं आदिवासी जनता में क्रांतिकारी कार्य करने के नाम पर बाकी कार्यों पर ध्यान नहीं देने की जड़ात्मक समझदारी से ग्रसित हो गए. शहरों एवं मैदानी इलाकों में किए जाने वाले राजनीतिक एवं सांगठनिक कार्य को उचित महत्व नहीं दे पाएं.

साम्राज्यवादी अस्तित्व के लिए उपनिवेश होना मुख्य शर्त है. इसीलिए जब तक साम्राज्यवाद अस्तित्व में रहती है, तब तक विश्व में पिछड़े देशों या एशिया, अफ्रीका एवं लातीन अमेरिका के देश साम्राज्यवाद के लिए उपनिवेशों के रूप में हो, अर्ध–उपनिवेशों के रूप में हो, नए उपनिवेशों के रूप में हो, रहना अनिवार्य है. वर्तमान में साम्राज्यवाद द्वारा अपनायी गयी नयी औपनिवेशिक नीति के तहत ये

देश अर्ध–औपनिवेशिक एवं अर्ध–सामंती देश के रूप में हैं. इसलिए एशिया, अफ्रीका एवं लातीन अमेरिका देशों में साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के बगैर वहां स्वतंत्र राष्ट्रीय पूंजीवाद का विकास नहीं होगा. अर्ध–औपनिवेशिक एवं अर्ध–सामंती देशों में जब तक साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद एवं सामंतवाद को उखाड़ फेंकने की नवजनवादी क्रांति पूरा नहीं होता, तब तक उन देशों में जमीन की समस्या का हल नहीं होगा, जनतंत्र की स्थापना नहीं होगी एवं राष्ट्रीय मुक्ति नहीं होगी. इसलिए जमीन समस्या को हल कर, जनतंत्र की स्थापना कर, राष्ट्रीय मुक्ति हासिल करने तक उन देशों की क्रांतियों का स्वभाव नवजनवादी क्रांति यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक क्रांति का ही होगा. वह समाजवादी क्रांति नहीं होगी. नवजनवादी क्रांति में साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद एवं सामंतवाद उखाड़ फेंकने के लक्ष्यों के रूप में रहेंगे. इसलिए इन देशों में साम्राज्यवाद एवं उस देश की जनता के बीच, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद एवं व्यापक जनता के बीच, सामंतवाद एवं व्यापक जनता के बीच होने वाले अंतरविरोध मौलिक अंतरविरोधों के रूप में होंगे. इनमें से वर्तमान में सामंतवाद एवं व्यापक जनता के बीच अंतरविरोध प्रधान अंतरविरोध के रूप में होगा.

इसलिए भारत देश की अर्ध–औपनिवेशिक एवं अर्ध–सामंती अर्थव्यवस्था में घटित बदलावों को और उसमें दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग की नेतृत्व भूमिका को ध्यान में रखकर, जैसाकि 'भारत देश के उत्पादन संबंधों में बदलाव–हमारा राजनीतिक कार्यक्रम' नामक दस्तावेज में बताया गया, ग्रामीण इलाकों में ''जोतने वाले को जमीन, क्रांतिकारी किसान कमेटियों/किसान–मजदूर संगठनों, क्रांतिकारी जन कमेटियों के हाथों में सारी हकूमत, साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय संस्थाओं, पूंजीवादी जमींदारों, दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के कृषि क्षेत्रों व बगानों को जनता के हाथों हवाले करें, जल–जंगल–जमीन–इज्जत–अधिकार के लिए लड़ें के मुख्य नारे पर केंद्रित कर वर्ग संघर्षों को विकसित करना है. इसके अलावा दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग के खिलाफ चार उत्पीड़ित वर्गों, उत्पीड़ित तबकों एवं उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के व्यापक जन समुदायों को गोलबंद करने के लिए देशव्यापी जनवादी संयुक्त मोर्चा का निर्माण करना है. यह संयुक्त मोर्चा ठोस राजनीतिक कार्यक्रम के साथ काम करना है.

दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग के खिलाफ भारत देश की व्यापक जनता के संघर्ष का लक्ष्य, मुख्य रूप से चार उत्पीड़ित वर्गों, उत्पीड़ित तबकों एवं उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के हितों का संरक्षण करना ही है. सीबीबी के खिलाफ संघर्ष साम्राज्यवाद विरोधी एवं सामंत विरोधी संघर्ष एक ही समय में अभिन्न अंग के रूप

में एकताबद्ध होकर चलते रहेंगे. इन संघर्षों का लक्ष्य यही है. ये सब नवजनवादी क्रांति का हिस्सा है. देश में राष्ट्रीयताओं को अलग होने के अधिकार समेत आत्मनिर्णय अधिकार देते हुए, राष्ट्रीयताओं का सर्वांगीण विकास के लिए भरोसा देते हुए, संघीय सूत्र पर आधारित स्वतंत्र एवं स्वावलंबी नवजनवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित करने द्वारा ही वे संघर्ष अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं. यह लक्ष्य हासिल करने के लिए दीर्घकालीन लोकयुद्ध की लाईन को लेकर सर्वहारा के नेतृत्व में मजदूर–किसान की मित्रता पर निर्भर होकर चार क्रांतिकारी वर्गों को एकताबद्ध कर नवजनवादी क्रांति को सफल बनाना है, इसके बिना कोई चारा नहीं है.

देश में 'वैश्वीकरण' के हमले के कारण गंभीर रूप से नुकसान झेल रहे तमाम उत्पीड़ित वर्ग, तबके एवं उत्पीड़ित राष्ट्रीयताएं नवजनवादी स्वावलंबी अर्थव्यवस्था के लिए तीन महान पहाड़ों के खिलाफ जारी संघर्ष में मुख्य शक्तियां होंगी. इसमें मजदूर, किसान, निम्नपूंजीपति वर्ग, राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग यानी चार उत्पीड़ित वर्ग, दलित, आदिवासी, महिला, धर्मिक अल्पसंख्यक आदि उत्पीड़ित तबकें एवं कश्मीर, नगा, मिजो, मणिपुरी, असम आदि देश के तमाम उत्पीड़ित राष्ट्रीयताएं होंगी. इन्हें अपनी मांगों पर प्रचार व आंदोलन तथा वर्गसंघर्ष के प्रक्रियाओं द्वारा गोलबंद करना चाहिए. कानूनी व गैर–कानूनी, खुला व गुप्त संघर्ष व सांगठनिक स्वरूपों का समन्वय करते हुए जनांदोलनों व प्रतिरोध आंदोलनों का उभार पैदा करना चाहिए.

इसके लिए 1947 से पहले, आंदोलनों में कांग्रेस व सीपीआई के नेतृत्व के विश्वासघात से सबक लेकर सच्ची स्वाधीनता संग्राम का निर्माण करना चाहिए. तभी देश को साम्राज्यवादियों के बंधनों से, तमाम प्रतिक्रियावादियों से – विशेषकर देश में प्रतिक्रियावाद को संरक्षित करने वाली व्यापक ग्रामीण इलाके की अर्धसामंती गतिरोध से आजादी मिल सकती है.

नवजनवादी स्वावलंबी व्यवस्था साम्राज्यवादियों एवं दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग के तमाम उद्योगों, बैंकों एवं अन्य संस्थाओं को जब्त कर लेती है. साम्राज्यवादियों को भुगतान करने वाले तमाम रुणों को रद्द करती है. छोटे उद्योगों को संरक्षण देकर, मझोले उद्योगों को सीमित एवं नियंत्रित करती है. जमींदारों की तमाम जमीन को जब्त कर खेतिहर–गरीब किसानों के बीच वितरित करती है. किसानों पर सूदखोरों एवं व्यापारियों के शोषण को समाप्त करती है. तद्वारा देश में मजदूर, अर्ध–मजदूर, किसान, शहरी मध्यम वर्ग समेत तमाम उत्पीड़ित वर्गों, उत्पीड़ित सामाजिक तबकों एवं उत्पीड़ित राष्ट्रीयाओं की मुक्ति का रास्ता सुगम

बनाता है. एक स्वावलंबी अर्थव्यवस्था में वर्तमान शोषणमूलक व्यवस्था से विपरीत दो मौकिल पहलू निहित होते हैंः

पहला विषय, उत्पादों के लिए देशीय बाजार विस्तारित करेगा, जिससे बुनियादी स्तर पर देश का औद्योगिकीकरण का मार्ग सुगम बनाएगा. सिर्फ व्यापक जन समुदायों के क्रयशक्ति बढ़ाने द्वारा ही यह संभव होगा. उनमें से अधिकतर लोग ग्रामीण इलाकों में आवास करते हैं. ग्रामीण इलाकों में सिर्फ पुरानी व पिछड़े अर्ध–औपनिवेशिक एवं अर्ध–सामंती उत्पादन संबंधों को ध्वस्त करने द्वारा ही इसे हासिल किया जा सकता है. जनता की गरीबी का मुख्य कारण है सिर्फ इस पुरानी उत्पादन के संबंध. इस पिछड़ेपन से जनता की मुक्ति करने के बाद, नवजनवादी सरकार कृषि में भारी निवेश करेगी. भारत देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रेरक शक्ति की पैदाइश होगी. किसी भी सूरत पर निर्यातों पर निर्भर होने का जरूरत नहीं होगी. बाजार के लिए धनी वर्ग के विनिमय स्वरूपों पर निर्भर करने की जरूरत नहीं होगी.

दूसरी, विदेशों से आने वाली भारी पूंजी निवेश को समाप्त करना. हमने तमाम विदेशी कार्पोरेट/दलाली पूंजी को जब्त करने से भविषय में देश में नयी पूंजी नहीं आने के बावजूद देश में कोई बड़ी विपदा नहीं होगी.

उस तरह की अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर निर्भर करेगी. साम्राज्यवादियों का नहीं, बल्कि देश के हित पूरा करने वाली नीतियां बनाकर अमल करेगी. भारत देश 140 करोड़ आबादी वाला बड़ा देश है. उसके पास बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधन एवं उपजाऊ जमीन हैं. इस महान देश के लोग वर्तमान व्यवस्था की बंधनों से मुक्ति होने से, देश के विकास एवं वृद्धि करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी.

11. हमारा राजनीतिक कार्यक्रम

भारत देश का सामंतवाद जाति आधारित सामंतवाद है. यह भारत देश के समाज की विशिष्टता (purticularity) है. यह बुनियाद में है एवं ऊपरी ढांचा में है. यह जाति आधारित सामंतवाद भारत देश का सामाजिक जीवन के तमाम क्षेत्रों को प्रभावित करता है. इस विशिष्टता की वजह से ही शूद्र जाति के कारीगर व्यापार क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, बैंकिंग क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो, पूंजीपतियों के रूप में विकसित नहीं हो पाएं. भारत देश के सीबीबी के अधिकतर लोग बनिया (वैश्य) जाति के लोग हैं. भारत देश के सीबीबी में निहित इस विशिष्टता के बारे में हमने इस दस्तावेज में पहचान कर लिए हैं. सीबीबी में निहित वर्ग चरित्र को पहचानने वाले सार्वजनिक पहलू (generality) के साथ उसमें

निहित जाति चरित्र को पहचानने वाली विशिष्ट (purticularity) पहलू को भी पहचान कर लिए हैं. एशिया, अफ्रीका एवं लातीन अमेरिका के अधिकतर देश के सीबीबी से भी, विशेषकर दक्षिण एशिया देशों के सीबीबी से भी भारत देश के सीबीबी अपेक्षाकृत मजबूत है. इनके सभी पहलुओं पर आधारित होकर सीबीबी के खिलाफ हमारा राजनीतिक कार्यक्रम बनाएंगे.

भारत देश के सीबीबी के बारे में समग्र रूप से अध्ययन कर, उसे एक सुस्पष्ट अस्तित्व होने वाले वर्ग के रूप में पहचान कर, सीबीबी और व्यापक जन समुदायों के बीच अंतरविरोध को मौलिक अंतरविरोध के रूप में शामिल करने से हमारी भारत देश की क्रांति की कार्यनीति में होने वाले बदलावों के बारे में अब देखेंगे.

पहला बदलाव, हमने अभी तक पूंजी एवं श्रम के बीच के अंतरविरोध के बारे में जो बताते आए है, उसे प्रमुख अंतरविरोधों से हटना होगा. कामरेड माओ की शिक्षा के मुताबिक मैलिक अंतरविरोध एक वस्तु या क्रम के सार या स्वभाव को निर्धारित करते हैं. उन मैलिक अंतरविरोध का हल करने द्वारा ही संबंधित वस्तु या क्रम के सार या स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं. अर्ध–औपनिवेशिक एवं अर्ध–सामंती समाज में भारत देश की जनता सामंतवाद, साम्राज्यवाद एवं दलाल नौकरशाह पूंजीवाद नामक तीन बड़े पहाड़ों के नीचे पीस रही है. इसीलिए हमने उन तीनों को नवजनवादी क्रांति के चरण में उखाड़ फेंकने वाले लक्ष्यों के रूप में पहचान कर लिए हैं. उसके मुताबिक पूंजी एवं श्रम के बीच के अंतरविरोध को हमने नवजनवादी क्रांति के चरण में हल नहीं कर पाएंगे. नवजनवादी क्रांति के चरण में साम्राज्यवाद एवं दलाल नौकरशाह पूंजीवाद को नेस्तनाबूद करने वाले लक्ष्यों के रूप में पहचान कर, भारत देश की जनता पर साम्राज्यवादी पूंजी, दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग की पूंजी के शोषण एवं उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रहे हैं. ऐसी स्थिति में पूंजी एवं श्रम के बीच अंतरविरोध को अलग से एक प्रमुख अंतरविरोध के रूप में शामिल करने से वह राष्ट्रीय पूंजीपतियों को निशाना बनाने की तरफ ले जाएगा. नवजनवादी क्रांति के चरण में हमने राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग को निशाना नहीं बनाएंगे, नहीं बनाना चाहिए. नवजनवादी क्रांति की विजय के बाद देशीय/राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था (domestic/national economy) को विकसित करने के तहत राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग को एक स्थान उपलब्ध कराएंगे.

दूसरी बदलाव, सीबीबी को मौलिक अंतरविरोधों में शामिल करने द्वारा – नवजनवादी क्रांति के चरण में हमारे तीनों लक्ष्यों – साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद एवं सामंतवाद के खिलाफ मजदूर, किसान, निम्नपूंजीपति वर्ग/मध्यम वर्ग एवं राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग को रणनीतिक संयुक्त मार्चा एवं कार्यनीतिक संयुक्त

मोर्चा में गोलबंद करने का राजनीतिक कार्य तेज करना है/करेंगे.

तीसरा बदलाव, चूंकि वर्तमान में देशभर में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र में, वन क्षेत्रों में साम्राज्यवादी पूंजी एवं दलाल नौकरशाह पूंजी बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर प्राकृतिक संपदाओं को लूट रही है, इसलिए उनके खिलाफ वर्ग संघर्ष एवं संयुक्त मोर्चा का कार्य तेज करने के लिए फायदामंद होगा. उदाहरण के लिए, 'वन क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने आ रहे देश–विदेशी कार्पोरेटों को मार भगाएं', 'देश के प्राकृतिक संसाधनों/संपदाओं को बचाएं', इस तरह स्पष्ट रूप से नारे दे सकते हैं. इसी तरह 'देश के कृषि क्षेत्र का कार्पोरेटीकरण को बंद करो', 'देश के किसानों की जमीन को लूटने वाले साम्राज्यवाद एवं दलाल नौकरशाह पूंजीवाद को मार भगाएं, उपजाऊ जमीन को बचाएं', इस तरह स्पष्ट रूप से नारे दे सकते हैं.

चौथा बदलाव, साम्राज्यवाद एवं दलाल नौकरशाह पूंजीवाद के खिलाफ वर्ग संघर्ष चलाने का मतलब है, मात्र औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी (मैदानी एवं वन क्षेत्रों में) उनके खिलाफ वर्ग संघर्ष चलाना है, ऐसी स्पष्टता मिल पाएगी. इसी तरह मात्र आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि एक ही समय में आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में या सामाजिक जीवन के तमाम क्षेत्रों में साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद एवं सामंतवाद के खिलाफ वर्ग संघर्ष चलाना है, ऐसी स्पष्टता मिल पाएगी.

सीबीबी विरोधी संघर्ष नवजनवादी क्रांति का हिस्सा है. इसलिए देश के शहरी, मैदानी एवं वग क्षेत्रों में सामाजिक जीवन के तमाम क्षेत्रों में साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद एवं सामंतवाद के खिलाफ/उन तीनों के गठजोड़ के खिलाफ वर्ग संघर्ष तेज करने में मददगार हो, इस तरह हमारा राजनीतिक कार्यक्रम बनाएंगे. 'भारत देश के उत्पादन संबंधों में बदलाव–हमारा राजनीतिक कार्यक्रम' यानी केंद्रीय एमओपी दस्तावेज के मुताबिक देश के सात वर्गीकृत इलाकों में लागू करने लायक इस राजनीतिक कार्यक्रम को बनाएंगे. केंद्रीय एमओपी दस्तावेज में निम्नांकित सात वर्गीकृत इलाकों को पहचान कर लिए हैं:

i. अभी भी अर्ध–सामंती व्यवस्था मजबूत वाले क्षेत्र;

ii. वर्गसंघर्ष के कारण अर्ध–सामंती संबंध कमजार हुए क्षेत्र;

iii. वक्रीकृत पूंजीवादी संबंध होने वाले क्षेत्र;

iv. मुख्य रूप से बागान होने वाले क्षेत्र;

v. नगरीय आर्थिक जीवन से अविभाज्य रूप से आपस में जुड़े हुए उपनगरीय

(suburban) ग्रामीण क्षेत्र;

vi. पहाड़ी अंचल एवं जंगलों से होने वाले आदिवासी क्षेत्र;

vii. समुद्र तटीय क्षेत्र;

देश के असमान वृद्धि के अनुसार विभिन्न इलाकों की निर्दिष्टता एवं विशेषताओं के आधार पर वर्ग संघर्ष चलाने के लिए, संबंधित इलाकों में प्रधान दुश्मनों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा गठित कर वर्ग संघर्ष चलाने के लिए हमने उक्त वर्गीकृत इलाकों को पहचान कर लिए हैं.

वर्ग अंतरविरोध तीखे होकर अर्ध–सामंती व्यवस्था अपेक्षाकृत मजबूत होने वाले इलाकों में 'जोतने वालों को ही जमीन' का नारा मुख्य नारा होगा. लेकिन इन इलाकों में अर्ध–सामंतवाद को प्रधान रूप से निशाना बनाते हुए ही साम्राज्यवाद एवं सीबीबी के शोषण एवं उत्पीड़िन के खिलाफ भी संघर्ष चलाना है.

अर्ध–सामंती व्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर होने वाले इलाकों में, वक्रीकृत पूंजीवादी संबंध अपेक्षाकृत मजबूत होने वाले इलाकों में 'साम्राज्यवाद एवं सीबीबी के पूंजीपति जमींदारों के कृषि क्षेत्रों को जनता के हाथों हवाला करें (राष्ट्रीयकरण करें)' का नारा प्रधान नारा होगा.

हमारा देश में चाय, काफी, रबड़, सुपारी, मसाले वस्तुओं के तमाम बागान देश–विदेशी कार्पोरेट कंपनियों का ही हैं. देश–विदेशी कार्पोरेटों के हितों के पूरा करने के लिए ही राज्य सरकारों के वन विभाग के अधीन में सागौन, रबड़, युकलिप्टस आदि बागान लगाए जा रहे हैं. मुख्य रूप से बागान होने वाले क्षेत्रों में 'देश–विदेशी कार्पोरेटों के बागानों एवं सरकारी बागानों को जनता के हाथों हवाला करें/राष्ट्रयकरण करें' के नारे से वर्ग संघर्ष चलाना है.

उपनगरीय (suburban) क्षेत्रों की जनता के आर्थिक जीवन आस–पास के नगरीय/शहरी आर्थिक जीवन का अभिन्न अंग के रूप से आपस में जुड़ा रहेगा. यानी, इस इलाके की जनता में अधिकतर या उल्लेखनीय संख्या में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में असंगठित मजदूर (ठेका एवं कैजुअल) काम करते हैं. कुछ लोग सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में पर्मनेंट कर्मचारियों एवं मजदूरों के रूप में काम करते हैं. इन इलाकों में रियल एस्टेट माफिया, विभिन्न किस्म के माफिया के शोषण व उत्पीड़न, साम्राज्यवादी एवं सीबीबी के कार्पोरेटों के शोषण व उत्पीड़न बढ़ रहे हैं. इसलिए इन इलाकों में 'सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में ठेका एवं कैजुअल व्यवस्था को रद्द करो', 'मजदूर व कर्मचारियों के लिए पर्मनेंट रोजगार दो', 'जनता की संपत्ति को बचाएं', 'रियल एस्टेट माफिया को मार भगाएं' एवं 'साम्राज्यवादियों एवं

सीबीबी के शोषण व उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करें' के नारे के साथ वर्ग संघर्ष चलाना है. इसके लिए इन इलाकों में अधिकतर इलाकों को शहरी संगठन में शामिल करना है. विभिन्न इलाकों की विशेषताओं के आधार पर कुछ इलाकों को ग्रामीण इलाकों के संगठन में शामिल किया जा सकता है.

पहाड़ी अंचल एवं जंगलों से होने वाले क्षेत्रों में अधिकतर आदिवासी जनता रहेगी. इसलिए इस इलाके में 'जल, जंगल, जमीन, इज्जत एवं अधिकार के लिए लड़ें' का नारा प्रधान नारा होगा. यह नारा मुख्य रूप से साम्राज्यवादियों एवं दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग एवं लुटेरी सरकारों के खिलाफ है. इन इलाकों में भारत देश की क्रांति के निशाने पर रहे साम्राज्यवादियों, दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों, सामंतियों एवं लुटेरी सरकार के खिलाफ वर्ग संघर्ष चलाना है. इस समझदारी से हमने जनता के लिए अनुकूल होने वाले आदिवासी एवं गैर–आदिवासी दबंगों नेताओं एवं पुजारियों को साम्राज्यवाद व सीबीबी विरोधी संयुक्त मोर्चा में शामिल करना है. इन इलाकों में होने वाले आदिवासी एवं गैर–आदिवासी जमींदारों के खिलाफ 'जोतने वाले को ही जमीन' के नारे से संघर्ष चलाना है.

वैश्वीकरण शुरू होने के बाद समुद्र तीटीय इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए साम्राज्यवादी एवं सीबीबी के कार्पोरेट संस्थाएं बहुत प्रयास कर रहे हैं. इन इलाकों में नए बंदरगाहों का निर्माण, पुराने बंदरगाहों का विस्तार, सेजों (एसईजड) का निर्माण–विस्तार, तटीय गलियारों का निर्माण, पेट्रो रसायन उद्योगों की स्थापना, रिसार्टों का निर्माण, तटीय इलाकों में पर्यटन केंद्रों को विकसित करना, तटीय इलाके के जलों में पॉवर बोटों द्वारा मछली पकड़ना, नमक तैयारी यूनिटों का निर्माण आदि से यहां की जनता विस्थापन की समस्या को गंभीर रूप से सामना कर रही है. इसलिए 'तटीय इलाके के प्राकृतिक संसाधनों पर जनता का ही अधिकार', 'तटीय इलाकों संसाधनों को लूटने वाले साम्राज्यवादी एवं सीबीबी के कार्पोरेटों को मार भगाएं', 'प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं, तटीय इलाके के जलों में कार्पोरेटों द्वारा मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाओ', 'तटीय इलाके के जलों पर मछुआरों का ही अधिकार', 'तटीय इलाके के पर्यावरण का विनाश करने वाले देश–विदेशी कार्पोरेटों को मार भगाएं' एवं 'पर्यावरण को बचाएं' के नारे देना है. यहां मुख्य रूप से साम्राज्यवादियों एवं सीबीबी के खिलाफ वर्ग संघर्ष चलाना है.

पिछड़े देशों के कृषि क्षेत्रों में देश–विदेशी कार्पोरेट संस्थाओं ने घुसपैठ करने एवं कांट्रैक्ट व कार्पोरेट कृषि के जरिए उस क्षेत्र को दखल करने का गंभीर प्रयास कर रही हैं. फलतः आगामी दिनों में हमारा देश में जमीन देश–विदेशी कार्पोरेटों

के पास केंद्रीकृत होगी. 2020–21 के किसान संघर्ष की वजह से केंद्र सरकार ने किसान विरोधी व कार्पोरेट अनुकूल तीन कृषि कानूनों को अस्थायी रूप से वापस करने के बावजूद, हमारा देश के कृषि क्षेत्र का कार्पोरेटीकरण का खतरा अभी भी मंडरा रहा है. इसीलिए उक्त तमाम वर्गीकृत इलाकों में 'हमारी जमीन कब्जा करने आ रहे देश–विदेशी कार्पोरेटों को मार भगाएं', 'हमारी जमीन को बचाएं', 'जमीन को लीज पर लेने एवं खरीदने का अधिकार देश–विदेशी कार्पोरेटों को नहीं है' एवं 'कांट्रैक्ट एवं कार्पोरेट कृषि पर प्रतिपंध लगाओ' की मांगों के लेकर संघर्ष चलाना है. इसी तरह किसानों की जमीन देश–विदेशी कार्पोरेटों को सौंपने के बुरे मंशे से जमीन डिजिटलीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल इंडिया जमीन रिकार्डों का आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DIRMP) एवं 'स्वामित्व' (SVAMITA) कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांगों को लेकर आंदोलन चलाना है.

जाति उत्पीड़न के खिलाफ उक्त तमाम इलाकों में वर्ग संघर्ष चलाना ही है. लेकिन जाति उत्पीड़न अपेक्षाकृत अधिक रहने वाले जगह पर, विशेषकर पीड़क जातियों का दुरहंकार एवं उन जातियों द्वारा दलितों पर किए जाने वाले हमलों के खिलाफ आंदोलन चलाना है. दलित समस्या का मतलब है जमीन, इज्जत एवं सत्ता की समस्या है. इसलिए 'जमीन, इज्जत एवं अधिकार के लिए लड़ें, जाति उत्पीड़न के खिलाफ लड़ें', 'ब्राह्मणवाद को कब्र में समाओ', 'जातिप्रथा को छोड़ दो' एवं 'तमाम श्रमजीवी जनता एक हो' के नारों को लेकर दलितों को गोलबंद कर वर्ग संघर्ष चलाना है. जाति दुरहंकार हमलों को प्रतिरोध करने के लिए आत्मरक्षा दस्ते गठित करना है. पीड़क जातियों द्वारा दलितों पर किए जाने वाले हमलों का मुकाबला करना है. इन हमलों के जिम्मेदार लोगों के मुखियाओं को उन्मूलन करना है. जातिप्रथा को मजबूत करने वाली हिंदुत्व, सामंती शक्तियों को वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में मुकाबला करना है. 'साम्राज्यवादियों, दलाल नौकरशाह पूंजीपति व सामंती वर्गों के खिलाफ लड़ें–नवजनवादी व्यवस्था की स्थापना करें' एवं 'लुटेरी व्यवस्था की समाप्ति के लिए लड़े–जाति उन्मूलन के लिए लड़े– समाजवाद–साम्यवाद की स्थापना करें' के नारों से दलितों को गोलबंद करना है.

वैश्वीकरण के बाद वन, मैदानी एवं शहरी क्षेत्रों में साम्राज्यवादियों, सीबीबी एवं सामंती वर्गों का सांठगांठ बहुत बढ़ा है. इसलिए विभिन्न इलाकों में मात्र एक ही वर्ग के खिलाफ संघर्ष चलाना संभव नहीं है. इन तीनों इलाकों में भी इस गठजोड़ के खिलाफ वर्ग संघर्ष चलाना है. केंद्रीय कमेटी द्वारा प्रकाशित 'भारत देश के उत्पादन संबंधों में बदलाव–हमारा राजनीतिक कार्यक्रम' नामक दस्तावेज में समाज

के उत्पीड़ित वर्गों, उत्पीड़ित सामाजिक तबकों एवं उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के आर्थिक, राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण समस्याओं पर 36 मुख्य विषयों के राजनीतिक कार्यक्रम मौजूद है. आंदोलन के ताकत पर आधारित होकर देश में उन 36 मुख्य विषयों के राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर वर्ग संघर्ष चलाना है. विशेषकर, साम्राज्यवाद एवं दलाल नौकरशाह पूंजीवाद के खिलाफ ठोस रूप से निम्नांकित राजनीतिक कार्यक्रम को अमल करना है:

- तमाम विदेशी कंपनियों/संस्थाओं, ब्राह्मणीय हिंदुत्व बनिया–मारवाड़ी आदि पीड़क जाति आधिपत्य वाले बड़े दलाल पूंजीपति व सामंती शासक वर्गों और उनके सरकारों के कंपनियों/संस्थाओं की पूंजी, बैंकों व संपत्ति का जब्त करना चाहिए. बहुराष्ट्रीय कंपनियों व संस्थाओं को मार भगाना है. उनके संपत्ति को जब्त करना है. विदेशी आर्थिक/टेक्निकल आदि साजिशपूर्ण समझौतों व ज्वाइंट वेंचरों (संयुक्त उद्यमों) को रद्द करना है. बहुराष्ट्रीय संस्थाओं की आउटसोर्सिंग नीति को समाप्त करना है. निर्यात–निर्देशित व आयात पर निर्भर नीतियों को समाप्त करना है. विदेशी बाजारों पर एवं विदेशी टेक्नोलोजी पर हमारा देश के उत्पादनों की पराधीनता हटाना है. देशी बाजारों को विदेशी वस्तुओं से बचाना है. विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए बनायी गयी पर्यटन नीति, आईटी नीति, अनिमेशन नीति, फार्मा नीति, स्टार्टप नीति आदि को समाप्त करना है. मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट आदि, पब्लिक–प्राइवेट भागीदारी (PPP) नीति के तहत लागू की जा रही भारतमाला योजना, सागरमाला योजना, विशेष परिवहन गलियारा जैसे महत्वकांक्षी योजनाओं (फ्लेगशिप योजनाओं) को समाप्त करना है. ये सब मात्र साम्राज्यवादी–प्रायोजित योजनाएं हैं. एमएनसीयों–टीएनसीयों को देश की संपदा, संसाधन व सूपर मुनाफें ले जाने से रोकना चाहिए.
- वैश्वीकरण नीतियों को, उसके तहत विश्व व्यापार संगठन (WTO) समझौतों का रद्द करना है. स्वावलंबी कृषि व औद्योगिक नीतियों को विकसित करने के लिए सर्वहारा के नेतृत्व में चार उत्पीड़ित वर्गों, उत्पीड़ित तबकों व राष्ट्रीयताओं के लोगों को संगठित करना है.
- तमाम किस्म के विदेशी कर्ज को रद्द करना है.
- रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, बिलगेट्स फाउंडेशन जैसे विभिन्न साम्राज्यवाद–प्रायोजित फाउंडेशनों को, साम्राज्यवादी निधियों से चलाने वाले

विभिन्न गैरसरकारी संगठनों (NGOs) को भंडाफोड़ करना है. ''अध्ययनों/शोधों'', ''पाठ्यक्रमों'', ''पुरस्कारों'', ''कल्याणकारी कार्यक्रम'', ''सहायता'', ''समाज सेवा'' आदि नामों से उनके द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रमों का बहिष्कार करना है. देश से उन्हें मार भगाना है.

- बेरोजगारी बढ़ाने वाले टेक्नोलोजियों को पर रोक लगाना है. बेरोजगारी समस्या को हल करना है.
- एमएनसीयों एवं भारत देश के सीबीबी के कार्पोरेट कंपनियों के उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण (एलपीजी) के नीतियों की वजह से संकट में जूझ रहे मध्यम वर्ग के विभिन्न तबकों को गोलबंद कर जुझारू जनांदोलनों का खड़ा करना है.
- देशीय उद्योगों व छोटे उद्यम क्षेत्र (एमएसएमई) को संरक्षित करना है. राष्ट्रीय पूंजीपतियों के हितों को बचाना है.
- दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, मुस्लिमों, इसाइयों आदि धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं पर फौरी एवं दीर्घकालीन कार्यक्रमों को लेकर व्यापक जनांदोलनों का निर्माण करना है.
- साम्राज्यवादी व सामंती संस्कृति व मूल्यों का विरोध करना है. ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवाद के खिलाफ, उसकी प्रतिक्रियावादी विचारधारा के खिलाफ निरंतर बुनियाद में और ऊपरी ढांचे में संघर्ष करना है. सच्ची जनवादी मूल्यों व उसूलों के बुनियाद पर खड़े होकर नयी संस्कृति व नये मूल्यों से युक्त नवजनवादी संस्कृति का निर्माण करना है. धर्म जरूर सिर्फ व्यक्तिगत व्यवहार के रूप में रहना है. तमाम स्वरूपों के पितृसत्ता व जातिप्रथा का तीव्र विरोध करना है. जाति, धर्म, आर्थिक या शिक्षा में भेदभाव नहीं होने वाले, तमाम लोगों के लिए न्याय, समानता, परस्पर सम्मान के बुनियाद पर मानव संबंधों का निर्माण करना है. तमाम आर्थिक व सामाजिक शोषण के तरीकों का विरोध करने का सूत्र पर खड़े रहना है.
- देशभर में जनता की क्रयशक्ति को बढ़ाना है ताकि औद्योगिकीकरण का प्रोत्साहित किया जा सके. वास्तविक आधुनीकरण की तरफ, समूचे देश का विकास की तरफ (वर्तमान जेबों का भरने की तरीके को छोड़कर) आगे बढ़ना है. स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है. अमीरों व गरीबों के बीच असमानताओं को मिटाने के लिए जनता के लिए अनुकूल बजटों के

अलावा विशेष योजनाएं बनानी है.

- अधिक टैक्स व महंगाई के खिलाफ संघर्ष करना है. गरीबीरेखा के नीचे जी रहे 80 करोड़ गरीबों पर टैक्स को समाप्त करना है. उनके जीवन स्तर बढ़ाने लायक कल्याणकारी कार्यक्रम बनाकर व भ्रष्टाचार से मुक्त कर उन्हें लागू करना है तथा उन्हें खाद्य सुरक्षा देना है. निजी क्षेत्र के लिए सौंपी गयी खाद्यान्न संचयन सरकार द्वारा ही कराना है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना है. गरीबों के लिए पर्याप्त मात्रा में न्यूनतम दरों पर ही दैनिक उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराना है.
- देश की जनता के लिए खाना, आवास, कपड़ा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ हवा, पानी, मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार आदि का भरोसा के लिए आंदोलन चलाना है.
- भगवाकरण–निजीकरण–कार्पोरेटीकरण के लिए मार्ग सुगम बनाते हुए, ब्राह्मणीय हिंदुत्व विचारधारा वाली नयी शिक्षा नीति को रद्द कर वैज्ञानिक शिक्षा नीति को अमल करना है. समान्य शिक्षा प्रणाली को अमल करना है.
- देश में समाजवादी परिवर्तन लाने के लिए पहला कदम के रूप में भारत देश का संघीय जनता का जनतांत्रिक गणतंत्र (Federal Democratic Peoples Republic of India) का निर्माण करना है. क्योंकि सिर्फ समाजवाद ही हमारा देश को साम्राज्यवादियों के बंधनों से प्रभावशाली तरीके से मुक्ति कर सकती है.

- कश्मीर राष्ट्रीयता के अलावा नगा, मणिपुरी, असमी, उत्तर–पूर्व इलाके अन्य उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं द्वारा अलग होने के अधिकार समेत आत्मनिर्णय अधिकार के लिए चलाए जा रहे न्यायपूर्ण राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों में हमने शामिल होना है. उन्हें नेतृत्व करना है. राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों एवं प्रादुर्भाव राष्ट्रीयताओं से संबंधित हर जनवादी मांगों के लिए – समान दर्जा, पृथक राज्य, स्वायत्तता आदि मांगों के लिए लड़ना है. संघीय ढांचे पर जनवादी जनतंत्र को स्थापित कर राज्यों को तमाम न्यायसंगत अधिकार देना है. पिछड़े इलाकों की समस्याओं का हल के लिए प्राथमिकता देनी है. नदी जलों के हिस्से की समस्याओं एवं सीमा की समस्याओं न्यायपूर्ण तरीके से हल करना है.
- भारत देश के दलाल शासक वर्गों के विस्तारवादी नीतियों, 'भारत' राष्ट्रीयता,

'हिंदू' राष्ट्रीयता की भावना एवं तमाम दक्षिण एशिया देशों को कब्जा कर 'अखंड भारत' की स्थापना के लिए ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी शक्तियों द्वारा की जाने वाली साजिशों को पर्दाफाश कर हराना है.

- पर्यावरण संरक्षण के लिए तीन महान पहाड़ों को उखाड़ फेंकने के लक्ष्य से व्यापक जनांदोलन निर्माण करना है. वैकल्पिक विकास नमूना के साथ काम करना है.

शोषण व उत्पीड़न झेल रहे मजदूर व विभिन्न क्षेत्र के श्रमिक अपने आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं पर दिन–ब–दिन जुझारू आंदोलनों पर उतर रहे हैं. किंतु 2015 के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 74 प्रतिशत के देश के ग्रामीण इलाकों में आवास कर रहे किसानों की भागीदारी के सिवा साम्राज्यवादी व दलाली गठजोड़ के खिलाफ किसी भी संषर्घ सफल नहीं हो सकता. कृषि मजदूरों व गरीब किसानों के अलावा मध्यम वर्ग, धनी किसान साम्राज्यवादियों, सामंतियों एवं दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के शोषण एवं उत्पीड़न से शिकार हैं. ग्रामीण इलाकों में आवास कर रही आबादी में 70 प्रतिशत रहे कृषि मजदूरों व गरीब किसानों को सर्वहारा के नेतृत्व में एकजुट करना है. मध्यम किसान दृढ़ मित्र है, इसलिए उन पर निर्भर होकर, डुलमुल होने वाले मित्र धनी किसान को यथासंभव क्रांति के पक्ष में खड़ा करना है.

नवजनवादी क्रांति में निम्न पूंजीपति वर्ग, विशेषकर छात्र, शिक्षक एवं बुद्धिजीवी एक मुख्य शक्ति होंगे. उनमें जुझारूपन स्वभाव होता है, इसके अलावा जन दुश्मनों के खिलाफ जनमत का निर्माण करने में वे एक मुख्य भूमिका निभाते हैं. इसी तरह निम्न पूंजीपति वर्ग में होने वाले छोटे व्यापारियों एवं कारीगरों को क्रांतिकारी आंदोलन में गोलबंद करना है.

राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग डुलमुल मित्र वर्ग है. इसमें अधिकतर छोटे किस्म के उद्योग क्षेत्र से आते हैं. अपनी श्रम से अधिक शोषण पर ही निर्भर होने वाले कारीगार भी इसी में आते हैं. एमएनसी–टीएनसीयों एवं दलालों के बड़ी पूंजी से, नोटबंदी, जीएसटी जैसे सरकारी नीतियों से वे गंभीर रूप से पीड़ित हैं. आंदोलनों के पहला चरण में खुलेआम वे शामिल नहीं होते हैं. फिर भी एक तबका उसे कई अत्यंत उपयोगी मार्गों में मदद करती है.

जाति, पितृसत्ता, धार्मिक कट्टरता जैसे विभिन्न सामाजिक पीड़नों के दोहारा मार झेलने वाले दलितों, आदिवासियों, महिलाओं एवं धामिर्क अल्पसंख्यकों के व्यापक तबकों को इन आंदोलनों में गोलबंद करना है. इन तबकों को

आरएसएस–भाजपा के मोदी गुट के ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवाद के खिलाफ जुझारू आंदोलनों में गोलबंद करना है.

उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के साथ, विशेषकर भारत देश के शासकों के खिलाफ हथियार पकड़ने वाली राष्ट्रीयताओं के साथ संयुक्त मोर्चा गठित कर एक मजबूत आंदोलन का निर्माण करना बहुत ही मुख्य पहलू है.

निम्नपूंजीपति पार्टियां: देश के कई मा–ले पार्टियां और छोटे–मोटे दलित व बहुजन पार्टियां संसद के अंदर व संसद से बाहर रही हैं. वे मौलिक रूप से निम्नपूंजीपति स्वभाव वाली पार्टियां हैं. इसलिए उन पार्टियों से एकजुट होकर देश में भूमंडलीकरण नीतियों के खिलाफ संयुक्त रूप से आंदोलन चलाना है. ये शक्तियां जितने भी डुलमुल हों, जितने भी कम समय तक साथ देते हों, उन्हें मुद्दों के आधार पर आंदोलन में गोलबंद करने का प्रयास करना है. वे साम्राज्यवाद द्वारा पर्यावरण का विध्वंस, महिलाओं पर उत्पीड़न, बेरोजगारी, आदि में किसी एक ही पहलू को लेकर आगे आ सकते हैं. किंतु वे वास्तविक तौर पर जनता को गोलबंद करने लायक होना चाहिए. ऐसे संगठन ट्रेड यूनियन हो सकते हैं या मजदूर व किसान ग्रुप हो सकते हैं जो खुद पर हमलों का प्रतिरोध करना चाहते हों.

विभिन्न संगठन और व्यक्तियों: साम्राज्यवाद–विरोधी भूमिका निभाने वाले, विशेषकर किसी भी ग्रुप या संगठन में हिस्सा नहीं होने वाले व्यक्तियों को जरूर इस आंदोलन में लाने का प्रयास करना और प्रोत्साहित करना है ताकि इस आंदोलन द्वारा वे पहचान बना सके. साम्राज्यवादियों/दलालों जितने विनाशकारी हों, उतना ही उस तरह के बुद्धिजीवी भी आगे आते हैं और वे एहसास करते हैं कि वे अकेले नहीं है, बढ़ती प्रगतिशील शक्तियों के उभार का हिस्सा है, तब उनके अंदर आत्मविश्वास और बढ़ जाता है.

शासक वर्गों के बीच अंतरविरोध नवजनवादी क्रांति में विशेषकर एक मुख्य पहलू है – साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्थाओं में संकट बढ़ने के साथ–साथ इसका प्रभाव भारत देश पर होगी. शासक वर्गों के बीच अंतरविरोध तेज होंगे. ये अंतरविरोध इससे पहले ही उभरना शुरू हो गया. दुश्मन को और अलगाव में डालने और एक मजबूत साम्राज्यवाद–विरोधी व सामंत–विरोधी आंदोलन में जनतांत्रिक शक्तियों को संगठित करने के लिए इन अंतरविरोधों को निपुणता से इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

साम्राज्यवादी वैश्वीकरण नीतियों के मामले में केंद्र व राज्य स्तरों पर तमाम मुख्य संसदीय पार्टियों के बीच किसी भी तरह का मौलिक अंतर नहीं है. जब वे

विपक्ष के रूप में जो बाते करती हैं, सत्ता में रहते समय उन पर तत्पर नहीं होतीं. वे साम्राज्यवादियों की मांगों को पूरा करने के लिए जल्दबाजी करते हुए आपस में होड़ में लगी रहती हैं. क्षेत्रीय पार्टियां राज्य स्तर में ही नहीं, बल्कि केंद्र में भी साम्राज्यवाद–निर्देशित वैश्वीकरण को अमल करने में विश्वसनीय दलालों के रूप में व्यवहार कर रही हैं. कांग्रेस व भाजपा शासित राज्यों में वे अवसरवाद से उनके सामने घुटने टेक रही हैं. तमाम अन्य पार्टियों का दृष्टिकोण भी इससे अलग नहीं है. ऐसी दलाल व संशोधनवादी पार्टियां जो भी हो, एक ठोस नीति पर कुछ विरोध हो या कुछ कदम उठाया हो, वह वोट पाने के उपाय के रूप में हो या एक व्यापार लेन–देन के विरोध में दूसरों को समर्थन देने के रूप में हो, हो सकता है. इसलिए, इन शासक वर्ग पार्टियों में कोई भी पार्टी हो, विभिन्न संदर्भों में उनके द्वारा अपनाये जाने वाले ठोस दृष्टिकोण जनता के असंतुष्ट को इस्तेमाल करने व उन्हें भटकाने के लिए उद्देश्यित है.

उनके बीच अंतरविरोधों को हमने आंदोलन के हितों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. किंतु उन्हें साम्राज्यवाद–विरोधी शक्तियों के रूप में नहीं लेना चाहिए. हम जानते हैं कि उनके बीच अंतरविरोधों को जिस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है, यह आंदोलन में सर्वहारा शक्तियों का ताकत पर निर्भर रहता है. यहां एक मुख्य कर्तव्य है कि इन पार्टियों को पूरी तरह भंडाफोड़ करना, साम्राज्यवाद–दलाल नौकरशाह–बड़े सामंत–विरोधी एक निश्चित कार्यक्रम पर आधरित होकर उन पार्टियों के कैडरों को हमारी तरफ जीतना. विशेषकर हमने यह भंडाफोड़ करना चाहिए कि ये तमाम पार्टी मात्र देशद्रोही हैं; ये विदेशी शक्तियों के हितों के लिए काम कर रही हैं; यही पार्टियां विदेशी शक्तियों से सांठगांठ हो रही हैं. जनता इस बात को समझने से, एक उभार की तरह उठ खड़े होकर इन पार्टियों को मार भगा सकती है. हमने जनता में बड़े पैमाने पर इसकी चेतना बढ़नी चाहिए, ताकि उस उभार को साम्राज्यवादी हमले के खिलाफ मोड़ा जा सके.

हमें संशोधनवादियों के नेतृत्व वाले जनांदोलनों व जनसंगठनों से स्पष्ट रूप से विभजनारेखा खींचना अत्यंत आवश्यक है. देश के विभिन्न इलाकों में भिन्न–भिन्न परिस्थितियों के मुताबिक सांगठनिक व संघर्ष के स्वरूप बदलते हैं. जनांदोलन सशस्त्र संघर्ष व जनयुद्ध की मदद करते हैं. उसी तरह सशस्त्र संघर्ष और जनयुद्ध जनांदोलन और आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं. यही है जनांदोलन व सशस्त्र संघर्ष के बीच के द्वंद्वात्मक आपसी संबंध. सशस्त्र संघर्ष को आंदोलन के अन्य स्वरूपों से समन्वय नहीं करने से क्रांति की विजय संभव नहीं है. इसलिए सशस्त्र संघर्ष व अन्य स्वरूपों के आंदोलन दोनों की भी जरूरत है.

मजदूर आंदोलन, गंदी बस्तियों (slums) आदि बस्तियों में हो रहे आंदोलन, युवा आंदोलन, बेरोजगारी आंदोलन, छात्र आंदोलन एवं महिला आंदोलन व्यापक जनसमुदायों को राजनीतिक रूप से इकट्ठा करने में मदद करेगी. शासक वर्गों के विभिन्न नीतियों के खिलाफ राजनीतिक रूप से जनसमुदायों को गोलबंद करने का मुख्य पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

वर्ग विश्लेषण व सामाजिक शोध जितने भी वस्तुगत दिख सकता है, किंतु हमारी दैनिक गतिविधियों में उसका कोई संबंध नहीं होने से, भारत देश की आबादी में अत्यधिक बहुमत वाले व मजदूर वर्ग का दृढ़ एवं अत्यंत विश्वसनीय मित्र तथा क्रांति में मुख्य शक्ति के रूप होने वाले किसानों (विशेषकर गरीब, खेतिहर किसान) का सक्रिय समर्थन एवं सुदृढ़ भागीदारी भूमिका नहीं होने से वास्तविक अर्थ में क्रांतिकारी युद्ध को, वास्तविक अर्थ में क्रांति के हथियार के रूप में क्रांतिकारी पार्टी, जनसेना व संयुक्तमोर्चा को – इनमें से किसी को भी निर्मित नहीं किया जा सकता. इसलिए मजदूर वर्ग, किसान, युवा, छात्र, कर्मचारी, महिला आदि जन समुदायों को कई आंदोलनों में गोलबंद करना है और उन आंदोलनों के क्रम में उनकी राजनीतिक चेतना बढ़ाना है. तभी वे शोषक वर्गों की राजसत्ता को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता को समझ पाते है तथा पीड़क राज्ययंत्र को उखाड़ने के लिए जरूरी चेतना व सामूहिक संकल्प जुटा पाते हैं.

राजनीतिक कार्यनीतिक नारा

- साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीपति–विरोधी व सामंत–विरोधी वर्गसंघर्ष एवं दीर्घकालीन लोकयुद्ध को व्यापक व तेज करें!
- देश–विदेशी कार्पोरेटों के तमाम किस्मके शोषण के खिलाफ संघर्ष करें!
- राष्ट्रवाद के नाम पर देश का साम्राज्यवाद के लिए बेचने वाली मोदी सरकार का देशद्रोही नीतियों के खिलाफ संघर्ष करें!
- जोतनेवाले को जमीन!
- जल, जंगल, जमीन, इज्जत और अधिकार के लिए संघर्ष करें!
- सरकार व निजी क्षेत्रों में केजुअल व ठेका व्यवस्था को समाप्त करें! तमाम मजदूरों को परमनेंट करो! तमाम बेरोजगारों के लिए नौकरी दो!
- शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों का निजीकरण को विरोध करें!
- साम्राज्यवादियों, सीबीबी एवं सामंती हितों की सेवा करने वाली नयी शिक्षा नीति का विरोध संघर्ष करें!
- धार्मिक अल्पसंख्यकों पर ब्राह्मणीय हिंदुत्व धर्मोन्मदियों के हमले का निंदा करें! ब्राह्मणीय हिंदुत्व पफासीवाद के खिलाफ संघर्ष करें!
- दलितों पर पीड़क जातियों के हमले का प्रतिरोध करें! तमाम किस्मके जातिगत भेदभाव व जाति उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करें!
- पितृसत्ता के खिलाफ संघर्ष करें! महिलाओं पर तमाम किस्मके हमलों के खिलाफ संघर्ष करें!
- राष्ट्रीयताओं का स्वेच्छा, समानता और आत्मनिर्भर अधिकार के लिए संघर्ष करें!
- नवजनवादी क्रांति जिंदाबाद!

★★★